कल्पमेधा

जो लोग मिथ्या विचारों पर नियंत्रण रखते हैं और सत्य को जानने एवं बोलने का प्रयत्न करते हैं, वे ही अच्छे जीवन के निर्माता होते हैं।

– जान गाल्सवर्दी

शांति की राह

इजराइल और हमास के बीच दो वर्षों से चल रहे युद्ध पर फिलहाल विराम लग गया है। दोनों पक्ष शांति की राह पर लौट आए हैं। अमेरिका की ओर से तैयार की गई समझौता योजना के प्रथम चरण में हमास ने बीस बंधकों को रिहा कर दिया है और बदले में इजराइल ने उन्नीस सौ से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इसके साथ ही अब तक बारूदी आग की तपिश झेल रहे गाजा के नागरिकों ने भी राहत की सांस ली है। भारत और ब्रिटेन सहित कई देशों ने अमेरिका की इस पहल का स्वागत किया है। वैश्विक नेताओं को उम्मीद है कि शांति समझौता अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में अभी कई अड़चनें साफ नजर आ रही हैं। हमास के निरस्त्रीकरण, गाजा के शासन और फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने जैसे जटिल मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। ऐसे में इस पूरी कवायद को फिलहाल सिर्फ युद्ध रोकने के अस्थायी उपाय के तौर पर भी देखा जा रहा है।

शांति समझौते के अगले चरण कितने सफल रहेंगे, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि प्रस्ताव में रखी गई अन्य शर्तों पर हमास किस तरह का रुख अपनाता है। क्या हमास गाजा का नियंत्रण किसी बाहरी ताकत के हाथों में सौंपने के लिए राजी होगा? जैसा कि शांति प्रस्ताव में कहा गया है। दूसरी तरफ गाजा से अपनी सेना पूरी तरह हटाने को लेकर इजराइल की ओर से भी अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई हामी नहीं भरी गई है। इस स्थिति में शांति समझौते के सिरे चढ़ने को लेकर अभी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि, वैश्विक नेताओं का मानना है कि समझौते को लागू करने की शुरुआत अच्छी हुई और यह सकारात्मक दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस समझौते ने युद्ध को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है और इसने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के द्वार खोल दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समझौता पूरी तरह लागू होगा। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत इस क्षेत्र में शांति के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करता है।

इजराइल की ओर से युद्ध रोकने और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई से गाजा में खुशी का माहौल तो है, लेकिन वहां की स्थिति अब भी दयनीय है। कई इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद है और पुनर्निर्माण में वर्षों लग सकते हैं। इस युद्ध की शुरुआत सात अक्तूबर, 2023 को हमास के हमले से हुई थी, जिसमें एक हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे और कई नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 67 हजार से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा में आज भी लोग भोजन-पानी से लेकर स्वास्थ्य सहायता तक की बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में युद्ध विराम निश्चित तौर पर वहां के लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इससे गाजा में बाहरी मदद भेजने का रास्ता भी खुलेगा, जिसकी अभी नितांत जरूरत है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इजराइल और हमास शांति की राह पर आगे बढ़ेंगे और गाजा के नागरिकों के जीवन में फिर से खुशहाली और समृद्धि लौटेगी।

लापरवाही की परतें

सरकार की ओर से समाज के विभिन्न वर्गों के लिए नई-नई योजनाएं लागू की जाती हैं, मगर इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंच पाता है या नहीं, इस पर शायद ही कोई ध्यान दिया जाता है। इससे न केवल सरकारी धन का बेजा इस्तेमाल होता है, बल्कि वे लोग भी लाभ से वंचित रह जाते हैं, जिन्हें केंद्र में रखकर योजना तैयार की जाती है। यही वजह है कि सरकार की कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती हैं। संबंधित अधिकारियों की लापरवाही और निगरानी तंत्र का अभाव इसकी बड़ी वजह है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी यही हाल है। इसके तहत किसान परिवार का एक सदस्य ही लाभ ले सकता है। मगर केंद्रीय कृषि मंत्रालय की सत्यापन जांच में पाया गया कि बड़ी संख्या में पति और पत्नी दोनों ही इस योजना के लाभार्थी बने हुए हैं। सवाल है कि इस तरह की योजनाओं में आर्थिक सहायता से पहले पात्रता की जांच करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की जाती?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है। इसमें हर वर्ष तीन किस्तों में किसान परिवार के एक सदस्य को दो-दो हजार रुपए की राशि देने का प्रावधान है। इस रकम को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सीधे बैंक खाते में जमा किया जाता है। अगर यह नियम है, तो यह कैसे संभव हुआ कि एक ही घर से दो लोगों को राशि हस्तांतरित की जाती रही। जिन अधिकारियों के माध्यम से राशि जारी की जा रही थी, न तो उन्होंने और न ही संबंधित बैंक प्रबंधन ने कभी इस पर गौर करने की जरूरत महसूस की। इस योजना के अंतर्गत उन्नीस लाख से अधिक किसानों के सत्यापन से पता चला है कि इनमें 17.87 लाख पति-पत्नी ही लाभार्थी थे। इस हिसाब से करीब चौरानवे फीसद दंपति इस योजना का लाभ ले रहे थे। यह पहली बार नहीं है, जब किसी अहम योजना के क्रियान्वयन में इस तरह की लापरवाही सामने आई है। ऐसे में शासन-प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की योजनाओं की नियमित निगरानी हो, ताकि पात्र लोगों को इनका लाभ मिल सके।

भीड़ प्रबंधन में ठोस उपायों की दरकार

देश में आए दिन भगदड़ की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। ज्यादातर घटनाओं के जांच निष्कर्ष प्रशासनिक तैयारी की कमी, भीड़ नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था न होने और आयोजकों की लापरवाही की ओर इशारा करते हैं। ऐसे में जवाबदेही का पहलू अनिवार्य हो जाता है।

देवेंद्रराज सुथार

देश में बड़े आयोजनों के दौरान भीड़ में भगदड़ की घटनाएं राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई हैं। हाल के महीनों की बात करें, तो देश के विभिन्न हिस्सों में भीड़ प्रबंधन की विफलता के कारण कई लोगों की जान गई हैं। तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली में मची भगदड़ भी इनमें से एक है। इससे पहले प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ की स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें कई श्रद्धालुओं और यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पिछले वर्ष हाथरस में हुई भगदड़ की त्रासदी तो इतनी भयावह थी कि इसमें सौ से अधिक लोगों की जान चली गई। ये सभी घटनाएं प्रशासनिक तैयारी की कमी, भीड़ नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था न होने और आयोजकों की लापरवाही की ओर इशारा करती हैं। पिछले दो दशकों में भगदड़ की लगभग बाइस बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुल मिला कर पंद्रह सौ से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भीड़ प्रबंधन में लापरवाही बरती जाती है जो बार-बार त्रासदियों का कारण बनती है।

अनियंत्रित भीड़ से होने वाली इन दुर्घटनाओं के कई प्रमुख कारण हैं, जो प्रत्येक घटना में समान रूप से सामने आते हैं। सबसे पहली समस्या यह है कि अधिकांश आयोजनों में अनुमानित संख्या से कहीं अधिक लोग आ जाते हैं। हाथरस की घटना में प्रशासन को पचास हजार लोगों के आने की सूचना दी गई थी, जबकि वास्तव में वहां ढाई लाख से अधिक लोग पहुंच गए। इस तरह की गलत सूचना या जानबूझ कर कम संख्या बताने से प्रशासनिक तैयारी अधूरी रह जाती है। दूसरी बड़ी समस्या आयोजन स्थल पर पर्याप्त निकास मार्गों की व्यवस्था न होना है। कई बार भीड़ के प्रवेश के लिए तो व्यापक व्यवस्था होती है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने पर बाहर निकलने के लिए रास्ते छोटे या कम पड़ जाते हैं।

करूर की घटना में भी यही देखा गया कि संकरे रास्तों में हजारों लोग एक साथ बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। तीसरी समस्या प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की कमी है। अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर आयोजनों में स्थानीय स्तर के सेवादार या अप्रशिक्षित लोग भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जो आपात स्थिति में सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। चौथी समस्या आधुनिक तकनीक के उपयोग की कमी है, जैसे सीसीटीवी निगरानी, भीड़ की गति को मापने वाले सेंसर और तत्काल संचार प्रणाली, जो खतरे की स्थिति में शीघ्र हस्तक्षेप संभव बना सकें।

धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भगदड़ की घटनाएं विशेष रूप से चिंताजनक हैं, क्योंकि इनमें भावनात्मक आवेश का स्तर बहुत ऊंचा होता है। हाथरस और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ का अनियंत्रित होना इसी आवेश का उदाहरण है। धार्मिक स्थलों पर होने वाली भगदड़ में अक्सर यह देखा जाता है कि श्रद्धालु किसी भी संकेत या चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी आस्था की पूर्ति में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें आसपास के खतरों का भान नहीं रहता। राजनीतिक रैलियों में भी समान परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जहां समर्थकों का उत्साह और नेताओं को देखने की उत्सुकता भीड़ को अनियंत्रित कर देती है। इन सभी स्थितियों में आयोजकों की यह जिम्मेदारी

बनती है कि वे भीड़ के मनोविज्ञान को समझते हुए उचित व्यवस्था करें। भगदड़ की घटनाओं में जांच निष्कर्षों से पता चलता है कि अधिकांश मामलों में प्रशासनिक और आयोजकों की लापरवाही बड़ी वजह रही है। हाथरस घटना की न्यायिक जांच में यह पाया गया कि आयोजकों ने जानबूझ कर भीड़

> **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भीड़ नियंत्रण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन बहुत कम होता है। इन दिशा-निर्देशों में भीड़ के आकार का सही अनुमान लगाना, पर्याप्त प्रवेश और निकास मार्ग बनाना, चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं की तैयारी, सीसीटीवी निगरानी, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने यह भी सुझाव दिया है कि बड़े आयोजनों के लिए आयोजकों को प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर सुरक्षा योजना प्रस्तुत करनी चाहिए।**

की संख्या कम बताई और प्रशासन ने भी पूर्व तैयारी में कोताही बरती। करूर की घटना में भी सुरक्षा खामियां सामने आईं, जहां रैली स्थल पर पर्याप्त अवरोधक प्रणाली और आपातकालीन निकास की व्यवस्था नहीं थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना में रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी स्पष्ट थी, क्योंकि महाकुंभ के कारण भारी भीड़ की संभावना थी, फिर भी प्लेटफार्म पर समुचित व्यवस्था नहीं की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में भीड़ प्रबंधन को गंभीरता से नहीं लिया जाता और इसे केवल पुलिस बल की तैनाती तक सीमित मान लिया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि भीड़ प्रबंधन एक विशेषज्ञता का क्षेत्र है, जिसमें मनोविज्ञान, प्रौद्योगिकी और आपातकालीन प्रतिक्रिया का समन्वय आवश्यक है। विकसित देशों में बड़े आयोजनों के लिए विशेष भीड़ प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाती हैं और उन्हें लागू करने के लिए प्रशिक्षित दल होते हैं।

देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भीड़ प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन बहुत कम होता है। इन दिशा-निर्देशों में भीड़ के आकार का सही अनुमान लगाना, पर्याप्त प्रवेश और निकास मार्ग बनाना, चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं की तैयारी, सीसीटीवी निगरानी, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था शामिल है। इसके अतिरिक्त दिशा-निर्देशों में यह भी सुझाव दिया गया है कि बड़े आयोजनों के लिए आयोजकों को प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए और सुरक्षा योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। मगर, व्यावहारिक तौर पर कई आयोजक इन नियमों को दरकिनार कर देते हैं और प्रशासन भी राजनीतिक या धार्मिक संवेदनशीलता के कारण सख्त कार्रवाई से बचता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भीड़ प्रबंधन के लिए एक स्थायी और व्यावसायिक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, जो बड़े आयोजनों की निगरानी और मार्गदर्शन करे। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए जैसे- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भीड़ विश्लेषण प्रणाली, जो वास्तविक समय में भीड़ के घनत्व और गति को माप कर संभावित खतरों की चेतावनी दे सके। ड्रोन से निगरानी और ताप संवेदक का प्रयोग भी किया सकता है, जो भीड़ के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होते हैं। भगदड़ की घटनाओं में कानूनी जवाबदेही का प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण है। अधिकांश मामलों में आयोजकों के खिलाफ मामले दर्ज तो होते हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में ज्यादातर बच निकलते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान पर्याप्त हैं?

नीति निर्माताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि आयोजक और प्रशासन दोनों अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर रहें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक घटना के बाद एक स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, जिसकी सिफारिशों को कड़ाई से लागू किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जनसंख्या और सामाजिक-धार्मिक गतिविधियों के लिहाज से भारत एक विशिष्ट देश है, जहां वर्ष भर में कई बड़े आयोजन होते हैं। कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी के दही हांडी कार्यक्रम, राजनीतिक रैलियां और सांस्कृतिक महोत्सव जैसे अनगिनत अवसर होते हैं, जहां लाखों लोग एकत्र होते हैं। इन सभी आयोजनों को सुरक्षित बनाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है कि भीड़ में किस प्रकार का व्यवहार सुरक्षित है और आपात स्थिति में क्या करना चाहिए। शासन-प्रशासन, आयोजक और आम जनता सभी को मिल कर यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक आयोजन सुरक्षित हों। भीड़ प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा और इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।

जीवन के पहलू

दुनिया मेरे आगे

प्रेरणा अवस्थी

जीवन मनुष्य को प्रकृति के द्वारा दी गई एक अनमोल भेंट है। केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि के रूप में ही जीवन को परिभाषित कर देना इसके अर्थ के साथ अन्याय करना होगा। सही अर्थों में जीवन संघर्षों, अनुभवों, भावनाओं, सफलता-विफलता और परिस्थितियों की एक सतत यात्रा का नाम है। अगर हम जीवन को एक सतत अन्वेषण के रूप में देखें तो निश्चित ही हम इसके प्रत्येक पहलू को उचित ढंग से देखते हुए उसका मूल्यांकन कर पाने में सक्षम हो सकेंगे। मगर यह भी तय है कि अन्वेषण की प्रक्रिया के उपरांत सफलता एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए अन्वेषण का तर्क और जिज्ञासा के साथ संबद्ध होना नितांत आवश्यक है। जीवन का प्रत्येक पहलू असीम संभावनाओं से भरा है। केवल आवश्यकता है, तो उन संभावनाओं और अवसरों को पहचानने की। प्रत्येक दिन थोड़ा-सा समय निकालकर हमें अपने अंतर्मन में झांकने का प्रयास करना चाहिए और उस अंतर्मन में कुछ प्रश्नों के बीज बोने चाहिए। यथा- जीवन क्या है, मैं कौन हूं, मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है आदि। अपने अंतस की गहराइयों में उतरकर ही हम अपनी सभी शंकाओं का समाधान करने में सफल हो सकते हैं और एक बार जब शंकाओं का समाधान हो जाता है तो शांति का अथाह सागर हमारे हृदय में उमड़ पड़ता है।

बाह्य जगत की भाग-दौड़ तो कभी हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, किंतु इसी भागदौड़ में से हमें समय का अल्पांश अपने भीतर की यात्रा के लिए निकालने का प्रयास करना है। जीवन के हर मोड़ पर एक नई परिस्थिति हमारा स्वागत कर रही होती है। वह परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें पूर्ण इच्छाशक्ति, बुद्धि और विवेक के साथ ही उसे संभालना है। मानवता और प्रेम जैसे सद्गुणों की नौका पर सवार होकर और दृढ़ संकल्प की पतवार लेकर जब हम जीवनरूपी उदधि की यात्रा करते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन का प्रत्येक पहलू अपने आप ही हमारे अनुकूल होकर हमें सुखद परिणाम देने लगता है।

दरअसल, जीवन का प्रत्येक पहलू किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र अथवा किसी प्रयोगशाला के प्रयोग की तरह है। इसके संभावित परिणामों के भी अनेक विकल्प होते हैं, लेकिन प्रत्येक परिणाम, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक सत्य को सहज भाव से स्वीकार कर लेना ही हमें एक पूर्ण तथा सार्थक जीवन जीने की राह दिखाता है। प्रतिक्षण हम सुख की तलाश में ही रहते हैं, दुख को कदापि स्वीकार करना नहीं चाहते। किंतु हमें यह कटु सत्य अंगीकार करना होगा कि दुख भी इसी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जीवन रूपी संग्राम में अगर हम दूसरों की गतिविधियों पर केंद्रित रहेंगे, तो निश्चित बात है कि हम सदैव दुख से घिरे रहेंगे। दुख के बवंडर से अपने आप को बाहर निकालने का केवल एक ही तरीका है कि हम स्वतंत्र रूप से अपना कर्म करें। जीवन बहुत ही लघु अवधि का है और समय अपनी तीव्र गति के साथ हमें नजरअंदाज करते हुए दौड़ता जा रहा है। समय पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम जीवन के प्रत्येक छोटे पल को भी पूरी जीवंतता के साथ जीने का प्रयास करें और उस पल से निःसृत होने वाले आनंद की अनुभूति करें। विफलताएं, प्रतिकूल परिस्थितियां और भय, इनको अपना साथी मानते हुए इनसे सकारात्मकता को निचोड़कर उसे अपनी अभिप्रेरणा बनाने का प्रयास करके ही हम जीवन के प्रत्येक पहलू को सार्थक बना सकते हैं। केवल प्रश्नों और शंकाओं से घिरे रहकर हम जीवन के अर्थ से कभी परिचित नहीं हो सकते। जीवन के पहलुओं और उनके सच्चे अर्थ से तभी परिचित हुआ जा सकता है, जब हम उन्हें सहज भाव और शांति के साथ जीने तथा महसूस करने का प्रयास करें। अपने चारों ओर के परिवेश में जब हम जीवन को ढूंढ़ेंगे, तभी समझ सकेंगे कि जीवन वास्तव में क्या है। बहुत अधिक गंभीरता के साथ जीवन की विवेचना करने का प्रयास करना हमें जीवन के सच्चे भाव और सुंदरता से दूर ले जा सकता है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जीवन की सुंदरता का आनंद लेने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर लगाम लगानी होगी। इच्छाओं का ज्वार हमें आपाधापी और प्रतिस्पर्धा की ओर धकेल देता है, और ऐसी दशा में हम जीवन नहीं जी सकते। धैर्य और आत्मानुशासन जैसे गुण ही जीवन को सच्ची सुंदरता प्रदान कर सकते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में हमें अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने व्यक्तित्व को विकास के उत्तरोत्तर शिखरों तक पहुंचा सकें।

> **अपने जीवन के पहलुओं और उनके सच्चे अर्थ से तभी परिचित हुआ जा सकता है, जब हम उन्हें सहज भाव और शांति के साथ जीने तथा महसूस करने का प्रयास करें। अपने चारों ओर के परिवेश में जब हम जीवन को ढूंढ़ेंगे, तभी समझ सकेंगे कि जीवन वास्तव में क्या है।**

हर स्थिति में बंधनमुक्त होकर और शांतिपूर्ण मनःस्थिति के साथ छोटे-छोटे पलों में जीवन का रसास्वादन करना हमें एक सार्थक दिशा और दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। हर सुबह, हर शाम, हर रोज, हर रात, हर विचार, हरेक भावना और प्रकृति के प्रत्येक उपहार को पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ स्वीकार करते हुए अपने अधरों पर सदैव मुस्कान का आवरण बनाए रखना चाहिए। जीवन के आलेखन में रंग भरने में जीवन के प्रति हमारा नजरिया एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कभी किन्हीं परिस्थितियों में अगर हम विचलित महसूस करते हैं, तो ठीक उस क्षण हमें सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठकर अपने अंदर विद्यमान प्रेरक तत्त्व से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए जो व्यापक स्वरूप में हर जगह मौजूद है। निश्चित ही एकांत और साधना के वे क्षण हमें एक अद्भुत प्रेरणा देने का कार्य करेंगे और हम आत्मशक्ति से परिचित होकर जीवन की सुंदरता के उन्नत आयामों तथा पहलुओं को समझ पाने में सक्षम और समर्थ हो सकेंगे।

नैतिक पतन

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भीड़ ने पिछले दिनों एक दलित व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या कर दी। यह घटना समाज में भयावह संवेदनहीनता को उजागर करती है। वर्ष 2014 के बाद से ऐसी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, जहां भीड़ स्वयं अपराधी को दोषी ठहरा कर उसी समय सजा देना चाहती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। इस प्रवृत्ति के पीछे सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहें लोगों को उकसाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। किसी पर संदेह होते ही वीडियो या संदेशों के आधार पर भीड़ जुट जाती है और बिना सत्यापन के हिंसा पर उतर आती है। दूसरा कारण समाज में बढ़ता ध्रुवीकरण भी है। जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर विभाजन ने लोगों के मन में अविश्वास को गहरा कर दिया है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि ऐसे मामलों में पुलिस का रवैया अक्सर निष्क्रिय और संवेदनहीन रहता है। कई बार पुलिस मौके पर होती है, फिर भी हस्तक्षेप नहीं करती। यदि समय रहते कार्रवाई की जाए, तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। भीड़तंत्र समाज के नैतिक पतन का संकेत है।

– मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

अमेरिका की मनमानी

अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। वैसे भारत अब अमेरिका की हां में हां मिलाने वाला देश नहीं रहा। रूस से तेल और हथियार खरीदना एवं व्यापार बढ़ाना तथा कृषि एवं डेरी उत्पाद के लिए बाजार न खोलना अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। इससे भी ज्यादा अमेरिका द्वारा भारत पर भारी शुल्क लगाने पर कोई प्रतिक्रिया न दिखाना उसे ज्यादा परेशान कर रहा है। भारत-अमेरिकी संबंध सामान्य होने में सबसे बड़ी बाधा भारत का बढ़ता वैश्विक कद और उसकी आर्थिक प्रगति है। यह ईर्ष्या ही अमेरिका को भारत जैसे राष्ट्र से दूरी और पाकिस्तान के साथ नजदीकी बनाने के लिए मजबूर कर रही है। अमेरिका यह नहीं समझ पा रहा कि वह जितना भारत का अहित करेगा, उतना ही उसे भी नुकसान होगा। भारत सिर्फ अमेरिका से ही दोस्ती रखे, ऐसा किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता है।

– चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

ब्रिटेन का सहयोग

भारत में शिक्षा का स्तर देख कर ब्रिटेन चकित है। उसने भारत में उच्च श्रेणी की शिक्षा देने की पेशकश की है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को भारत के लिए आर्थिक वृद्धि का एक रास्ता माना जा रहा है। ब्रिटेन के साथ व्यापार तेज होने वाला है, इससे उत्पन्न अवसर बेजोड़ होंगे। इस साल जुलाई में लंदन में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी सैन्य प्रशिक्षण समझौता किया गया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षक अब ब्रिटेन की वायुसेना में प्रशिक्षण देंगे। दूसरी ओर ब्रिटेन के नौ विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर खोलने जा रहे हैं। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में अच्छी गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा की मांग है। उन्हें खुशी है कि ब्रिटेन के विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित करेंगे। यह दोनों देशों के लिए हितकारी होगा।

– युगल किशोर राही, छपरा

कमजोर होते पहाड़

'दरकते पहाड़' (संपादकीय, नौ अक्तूबर) पढ़ा। इसमें दोराय नहीं कि वन भूमि संक्षरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहाड़ों को लगातार क्षति पहुंचाने से इनकी मौलिक सुंदरता समाप्त हो रही है, क्योंकि सड़कों, भवनों और सुरंगों के निर्माण करने के लिए पहाड़ों को खोदा जा रहै है। वृक्षों के काटने से भी पहाड़ खोखले होते जा रहे हैं। हिमालयी क्षेत्र में सैलानियों की बढ़ती संख्या तथा वाहनों के दबाव से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। आए दिन बादल फटने का खमियाजा स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को झेलना पड़ता है। हाल के कुछ वर्षों में पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में वनभूमि और पहाड़ पर पेड़ों के संरक्षण को अब हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी ही होगी।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

एआइ बुनियादी कार्यों में तो उत्कृष्ट, लेकिन वैज्ञानिक तर्क का अभाव : अध्ययन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली और जर्मनी के फ्रेडरिक शिलर विश्वविद्यालय जेना (एफएसयू जेना) के अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) माडल बुनियादी कार्यों में तो उत्कृष्ट हैं, लेकिन उनमें वैज्ञानिक तर्क का अभाव है। 'नेचर कम्प्यूटेशनल साइंस' पत्रिका में प्रकाशित शोध से पता चला है कि अग्रणी एआइ माडल बुनियादी वैज्ञानिक कार्यों में तो आशाजनक परिणाम देते हैं, लेकिन उनमें मूलभूत सीमाएं भी हैं जो अनुसंधान वातावरण में उचित निगरानी के बिना लागू किए जाने पर जोखिम पैदा कर सकती हैं। आइआइटी दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर एनएम अनूप कृष्णन और एफएसयू जेना के प्रोफेसर केविन माइक जब्लोंका के नेतृत्व में शोध दल ने 'मैकबेंच' विकसित किया है जो पहला व्यापक मानदंड है जिसे विशेष रूप से यह मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया है कि दृष्टि-भाषा माडल वास्तविक दुनिया के रसायन विज्ञान और पदार्थ विज्ञान कार्यों को कैसे संभालते हैं।

आंध्र प्रदेश के करनूल के पर्वतारोही ने किया कमाल

भरत थम्मिनेनी 8,000 मीटर ऊंची नौ चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय

जनसत्ता ब्यूरो

आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पर्वतारोही भरत थम्मिनेनी मंगलवार को दुनिया के छठे सबसे ऊंचे पर्वत 'माउंट चो ओयू' (8,188 मीटर) पर चढ़ाई करने के साथ दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से नौ पर फतह करने वाले पहले भारतीय बन गए। इस 36 वर्षीय पर्वतारोही के करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि इस उपलब्धि से पहले थम्मिनेनी ने मई 2017 में माउंट एवरेस्ट, सितंबर 2018 में माउंट मनास्लु, मई 2019 में माउंट ल्होत्से, मार्च 2022 में माउंट अन्नपूर्णा, अप्रैल 2022 में माउंट कंचनजंगा, मई 2023 में माउंट मकालू, अक्तूबर 2024 में माउंट शीशपंगमा और अप्रैल 2025 में माउंट धौलागिरि पर चढ़ाई की थी। ये सभी 8,000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां हैं। बची हुई पांच शीर्ष चोटियां माउंट केटू, नंगा पर्वत, गशेरब्रुम एक व दो और ब्राड पीक पाकिस्तान में हैं और वर्तमान में भारतीय पर्वतारोहियों के लिए वर्जित हैं।

पर्वतारोहण

थम्मिनेनी ने भारत में अपने दोस्त को बताया कि 30 सितंबर को चीन के चो ओयू बेस कैंप पहुंचे, लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण उन्हें पहाड़ पर चढ़ने के शुरुआती प्रयास छोड़ने पड़े और आधार शिविर में ही रुकना पड़ा। उन्होंने बताया कि हमने 12 अक्तूबर तक इंतजार किया और फिर जल्दी से चोटी पर चढ़ने का फैसला किया। पर्वतारोही ने सफलतापूर्वक उतरने के बाद कहा कि मैं मंगलवार सुबह 6:55 बजे (चीनी समय) और 8:55 बजे (भारतीय समय) चोटी पर पहुंच गया था। थम्मिनेनी का यह कारनामा इसलिए और भी महत्त्वपूर्ण हो गया क्योंकि आधार शिविर से शिखर तक पहुंचने के उनके प्रयास में उनके साथ कोई शेरपा नहीं था।

पर्वतारोहण कंपनी बूट्स एंड क्रैम्पन्स के संस्थापक थम्मिनेनी को पहले ही भारत के सबसे कुशल पर्वतारोहियों में से एक का दर्जा मिल चुका है। थम्मिनेनी के एक मित्र दीपांजन दास ने बताया कि एक दशक के दौरान भरत ने छह महाद्वीपों में अभियान दलों का मार्गदर्शन किया है और भारतीय पर्वतारोहियों की नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। उनके नेतृत्व में एवरेस्ट 2025 अभियान ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं, जब हिमाचल प्रदेश की छोंजिन आंग्मो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दृष्टिहीन महिला बनीं और उस समय 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय, सात शिखरों की चुनौती पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने।

शिखर शिविर से एक रिकार्ड किए गए संदेश में पर्वतारोही ने अपनी इस उपलब्धि को देश के साहसिक खेलों के प्रति उत्साही नई पीढ़ी को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारतीय साहसिक खेलों की क्षमता का प्रमाण है। पहाड़ सम्मान, दृढ़ता और धैर्य की मांग करते हैं। आज चो ओयू की चोटी पर खड़े होकर, मैं इस यात्रा के लिए अपार कृतज्ञता महसूस करता हूं और आशा करता हूं कि यह भारतीय पर्वतारोहियों की एक नई पीढ़ी को सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।

भरत थम्मिनेनी

थम्मिनेनी ने भारत में अपने दोस्त को बताया कि 30 सितंबर को चीन के चो ओयू बेस कैंप पहुंचे, लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण उन्हें पहाड़ पर चढ़ने के शुरुआती प्रयास छोड़ने पड़े और आधार शिविर में ही रुकना पड़ा। उन्होंने बताया कि हमने 12 अक्तूबर तक इंतजार किया और फिर जल्दी से चोटी पर चढ़ने का फैसला किया।
शिखर शिविर से एक रिकार्ड किए गए संदेश में पर्वतारोही ने अपनी इस उपलब्धि को देश के साहसिक खेलों के प्रति उत्साही नई पीढ़ी को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारतीय साहसिक खेलों की क्षमता का प्रमाण है।

सीबीएसई ने एक साल से नहीं कराई सीटेट परीक्षा

लाखों अभ्यर्थी हैं परेशान, सोशल मंच का ले रहे सहारा

सुशील राघव

देशभर में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थी पिछले एक साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा इस परीक्षा की तिथि घोषित न किए जाने से उम्मीदवारों में बहुत नाराजगी है। सामान्यतः सीटेट वर्ष में दो बार की जाती है, लेकिन पिछले साल दिसंबर के बाद से यह परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है।

सीटेट वह राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, जो कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने के लिए अनिवार्य है। इसके माध्यम से दिल्ली के सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और कई राज्य स्तरीय भर्ती में शिक्षक बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। पिछली बार सीटेट दिसंबर, 2024 में हुई थी। उम्मीद थी कि जुलाई-अगस्त 2025 में अगला सत्र होगा। लेकिन अब अक्तूबर 2025 तक भी इसकी तिथि घोषित नहीं हुई है।

संकट

देश के विभिन्न राज्यों, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिल्ली से बड़ी संख्या में युवा अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सोशल मीडिया मंच एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इससे संबंधित कई अभियान चलाए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे अंतराल के कारण उनकी तैयारी पर असर पड़ रहा है और कई लोग उम्र सीमा की अंतिम स्थिति में पहुंच चुके हैं। दिल्ली की मानवी प्रजापति ने बताया कि हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा के इतने लंबे इंतजार से पढ़ाई का क्रम टूट गया है। अगर परीक्षा जल्दी नहीं होगी तो हम शिक्षक भर्ती में पीछे रह जाएंगे।

अभ्यर्थियों ने इस मुद्दे को लेकर आनलाइन अभियान शुरू किया है। अभ्यर्थी एक्स पोस्ट के जरिए वे शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई पर परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव बना रहे हैं। एक्स पर राहुल पटेल लिखते हैं कि एक साल से सीबीएसई द्वारा सीटेट नहीं कराई गई। इससे कई अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन तक नहीं कर पा रहे हैं। अतः सीटेट के लिए जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करके परीक्षा ली जाना चाहिए।

सीबीएसई की ओर से अब तक इस देरी का आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर पिछले सत्र के परिणाम और अंक प्रमाणपत्र से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन आगामी परीक्षा को लेकर कोई जानकारी नहीं है। शिक्षा क्षेत्र के जानकार कहते हैं कि सीटेट की देरी का असर न केवल अभ्यर्थियों पर, बल्कि आगामी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं पर भी पड़ेगा।

यदि पात्रता प्रमाणपत्र समय पर नहीं मिलेगा तो राज्य सरकारों और केंद्र के विद्यालयों में निकलने वाली भर्ती में अभ्यर्थी बैठ नहीं पाएंगे। अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं कि सीबीएसई तुरंत परीक्षा की तिथि घोषित करे और पहले की तरह साल में दो बार इसका आयोजन सुनिश्चित करे।

'ग्रीनहाउस' गैस उत्सर्जन पर अंकुश के लिए न हो धन की कमी : भारत

भारत ने जलवायु कार्रवाई के लिए निधि की कमी दूर करने की सीओपी30 से अपील की, पेरिस समझौते को अपनाये जाने के इस साल 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 'ग्लोबल स्टॉक टेक', पेरिस समझौता 2015 के तहत समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा है जो वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की दिशा में विश्व की सामूहिक प्रगति का आकलन करती है। हर पांच साल में आयोजित होने वाली यह समीक्षा बैठक, शमन, अनुकूलन और वित्त पोषण पर देशों की कार्रवाइयों की समीक्षा करती है तथा उन्हें भविष्य में अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।

पर्यावरण

भारत ने कहा है कि ब्राजील के बेलेम में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में विकासशील देशों को खुद को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढालने तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक संसाधनों की गंभीर कमी से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को ब्रासीलिया में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए प्रारंभिक वार्ता (प्री-सीओपी 30) बैठक के दौरान 'ग्लोबल स्टाक टेक' सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि बिना कार्रवाई के लगातार समीक्षा करने का समय बीत चुका है। उन्होंने कहा, 'बातचीत जरूरी है, लेकिन कार्रवाई भी जरूरी है।'

'प्री-सीओपी' जलवायु परिवर्तन पर 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन' (यूएनएफसीसी) का औपचारिक कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि इसके तहत बैठक के मेजबान देश में जलवायु से जुड़े राजनीतिक प्रश्नों की एक छोटी सूची पर मंत्री स्तर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, नहीं तो इनका हल करने में वार्ताकारों को हफ्तों लग सकते हैं। पेरिस समझौते को अपनाये जाने के इस साल 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यादव ने कहा, 'हमें अब महत्वाकांक्षी जलवायु उपायों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा और सबसे बड़ी चुनौती- विकासशील देशों के पास अनुकूलन और शमन के लिए संसाधनों की तत्काल कमी- का समाधान करना होगा।' 'ग्लोबल स्टॉक टेक', पेरिस समझौता 2015 के तहत समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा है जो वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की दिशा में विश्व की सामूहिक प्रगति का आकलन करती है। हर पांच साल में आयोजित होने वाली यह समीक्षा बैठक, शमन, अनुकूलन और वित्त पोषण पर देशों की कार्रवाइयों की समीक्षा करती है तथा उन्हें भविष्य में अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।

यादव ने प्रस्ताव किया कि वैज्ञानिक आकलनों को उनकी वैश्विक प्रासंगिकता पर उचित चर्चा किए बिना शामिल करने में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यादव ने 'प्री-सीओपी' बैठकों से इतर, संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टील, सीओपी 30 के लिए नामित अध्यक्ष आंद्रे कोरिया डी लागो तथा जलवायु कार्रवाई के लिए यूरोपीय संघ के आयुक्त वोपके होएकस्ट्रा से मुलाकात की। यादव ने कहा कि स्टील के साथ उनकी चर्चा वैश्विक जलवायु कार्रवाई को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि लागो के साथ उनकी बैठक पेरिस समझौते के कार्यान्वयन पर ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए जलवायु सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और अनुकूलन उपायों को मजबूत करने पर केंद्रित थी।

यादव ने सामूहिक और समावेशी जलवायु कार्रवाई के माध्यम से सीओपी30 को सफल बनाने के लिए भारत के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। होएकस्ट्रा के साथ बैठक में, दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ जलवायु साझेदारी को आगे बढ़ाने तथा ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

संतुलन

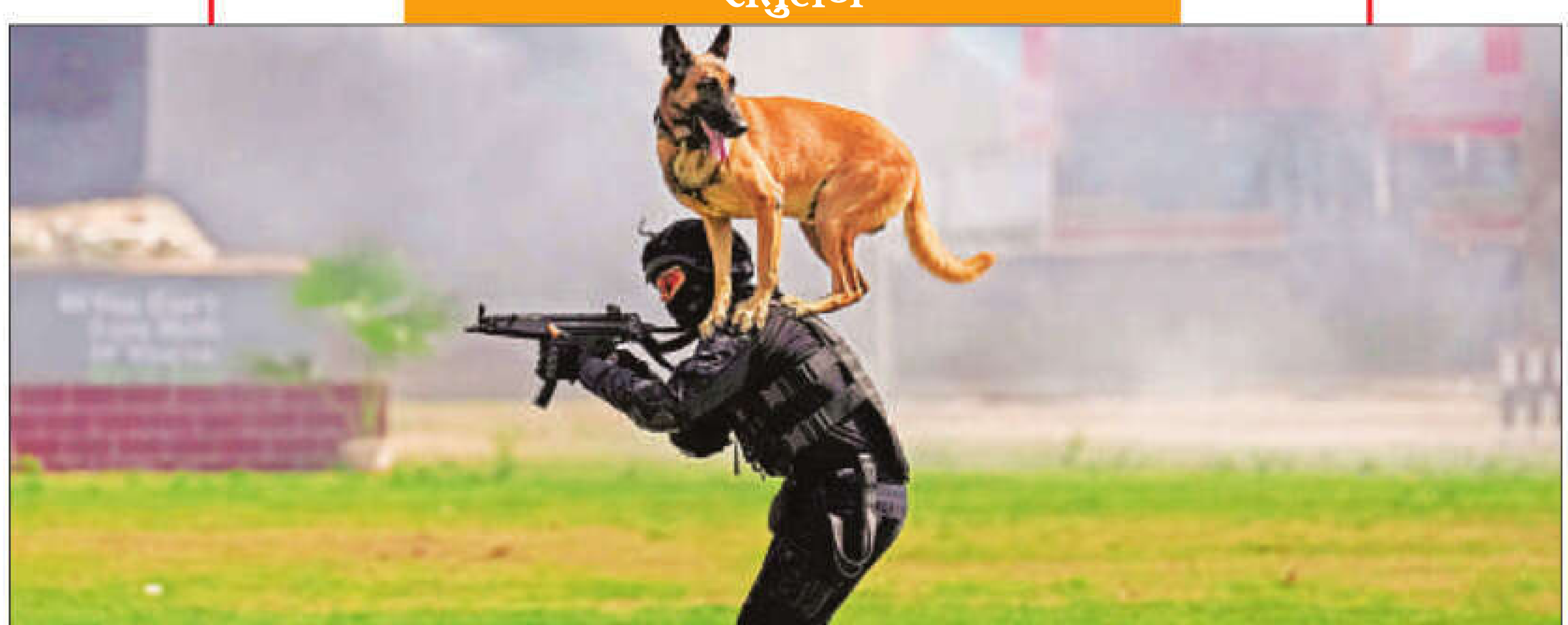

हरियाणा के मानेसर में मंगलवार को एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में एक कमांडो निशाना साधता हुआ।

बड़े दलों में उहापोह, निर्दलीय पर्चे भरने में आगे

पंकज रोहिला

बड़े राजनीतिक दलों के बीच नए उम्मीदवारों को लेकर घमासान मचा है। इस घमासान के बीच बिहार चुनाव के लिए 243 सीटों पर अब तक केवल 15 ही उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दर्ज कराएं है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक दर्ज कराए गए नामांकन निर्दलीय उम्मीदवारों से संबंधित है। अब बुधवार से इस प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस - सहयोगी व भाजपा सहयोगी दलों की सूची अब आनी शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए आगामी 17 अक्तूबर को ही नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है।

बिहार

सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही ओर घमासान मचा हुआ है। इसलिए सबसे पहले दोनों ही दल केवल उन सीटों को अपना पुख्ता दावा करने जा रहे हैं, जिन सीटों पर किसी भी दल के साथ कोई टकराव नहीं है। लेकिन भाजपा सहयोगी और कांग्रेस सहयोगी दल की ओर सारी स्थिति सामान्य होने का दावा किया जा रहा है। इसकी आधिकारिक पुष्टि सभी दलों की ओर से सोशल मीडिया मंच पर लगातार की जा रही है। जानकार मानते हैं कि ऐसी स्थिति होती, तो अब तक सीट के सभी समीकरण सामने आ चुके होते। इस वजह से अब उन सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जहां पर कोई विवाद नहीं है। इसके अतिरिक्त विवादित सीटों पर सहमति बनाने के लिए दलों के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे कम अंतर वाली सीटों पर है अधिक तनाव

बिहार विधानसभा के लिए कुल 122 विधायकों के बहुमत की जरूरत होती है। 2020 के चुनावी आंकड़े देखें तो में कांग्रेस व सहयोगी दलों के पास 110 सीट थीं जबकि भाजपा सहयोगी दलों के पास 122 सीट थीं। इस पूरे आंकड़े में केवल 12 सीटों से हार जीत का फैसला हुआ था। कुछ सीटों पर विपक्षी दलों के साथ जीत का अंतर बहुत ही कम था, इस अंतर को कम करके दोनों दल अपना बहुमत जुटाना चाह रहे थे। इन सीटों के दायरे में पांच हजार से कम वोट के अंतर वाली सीटों को रखा गया है। इन सीटों की सरकार बनाने में इस चुनाव में सबसे अधिक भूमिका रहने वाली है। ऐसी सीटों का आंकड़ा 50 से अधिक है। इन सीटों में 15 सीट राजद और 9 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। जबकि अन्य सीटें भाजपा सहयोगी दलों की झोली में थी।

सर्दी की शुरुआत में ही प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू

सुनील दत्त पांडेय

उत्तराखंड में प्रवासी पक्षियों का आगमन इस साल समय से शुरू हो गया है, परंतु इनकी संख्या पिछले सालों के मुकाबले अभी बहुत कम है, क्योंकि अभी इनके लिए सर्दी बहुत कम है सर्दी बढ़ने पर इनकी तादाद बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विज्ञानी और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश चंद्र भट्ट का कहना है कि इस बार अभी तक प्रवासी पक्षियों की 12 प्रजातियां ही उत्तराखंड की विभिन्न नदियों और झीलों में आई है। जिनमें साइबेरिया के सुर्खाब, पनकौवा, चकवा, चकवी, तील, मेलार्ड, सैंड पाइपर, स्पाट बिल डक, रिवर लैपविंग, नेट स्टील्स आदि शामिल है।

उत्तराखंड

देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में आसान झील में सबसे पहले दस्तक साइबेरिया के सुर्खाब विदेशी पक्षी ने दी है और सर्दियां बढ़ने के साथ-साथ ही अन्य प्रजातियों के पक्षी भी पहुंचने लगेंगे। कैलाश मानसरोवर तथा उसके आसपास लाल तलाईयों में रहने वाला राजहंस पक्षी अपने जोड़े के साथ नवंबर के प्रथम सप्ताह में उत्तराखंड की झीलों में डेरा डालेंगे। और धीरे-धीरे नवंबर के अंतिम सप्ताह तक उत्तराखंड की सभी झीलें और नदियां प्रवासी पक्षियों के झुंडों से सराबोर हो जाएंगी।

देहरादून के विकास नगर के आसान झील क्षेत्र के वन विभाग के वन दरोगा प्रदीप सक्सेना का कहना है कि उत्तराखंड में प्रवासी पक्षियों का आगमन अक्टूबर के महीने में शुरू हो जाता है और वे यहां पर मार्च तक यहां प्रवास करते हैं।

उत्तराखंड के देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में आसान झील के अलावा डाकपत्थर बैराज, ॠषिकेश के वीरभद्र गंगा बैराज, हरिद्वार के भीमगोडा गंगा बैराज, हरिद्वार के कनखल स्थित मिस्सरपुर में गंगा नदी इन प्रवासी पक्षियों के पसंदीदा डेरे हैं। उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ा दी गई है और मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के तराई और मैदानी क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी इस बार पिछले साल के मुकाबले समय पर आए हैं और इस बार उनके लिए उत्तराखंड में प्रजनन के लिए मौसम भी अनुकूल दिखाई दे रहा हैं। विज्ञानियों का मानना है कि ऐसा बदलते पर्यावरण के कारण हो रहा है और इस बार पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी भी पिछले साल के मुकाबले पहले पड़ने लगी है, जैसे-जैसे ठंड बढ़ती जाती है, प्रवासी पक्षी अपने मूल ठिकानों से उत्तराखंड के तराई और मैदानी क्षेत्रों की ओर कूच कर जाते हैं।

इस साल मध्य एशिया, मंगोलिया, चीन, साइबेरिया व रूस के पूर्वी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियां देहरादून के कालागढ़ क्षेत्र में यमुना घाटी, ॠषिकेश तथा हरिद्वार के गंगा तटों पर आ चुके है। प्रवासी पक्षियों की कुछ प्रजातिया जैसे सुर्खाब, जल काग ,ब्लैकविंग इसटिल्ट, रीवर लैपविंग, स्पाटबिल्ड़ डक, वैगटेल यानी सुदंर नेत्रों वाली खंजन, सैंड पाइपर, ,रीवर टर्न, रेड़नेप्पड़ आइबिस के समूह ॠषिकेश और हरिद्वार के गंगा क्षेत्र पर अपना नया ठिकाना बना चुके हैं। पक्षी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल अक्तूबर माह के प्रथम सप्ताह में प्रवासी पक्षियों का पहला जत्था देहरादून, हरिद्वार कोटद्वार पहुंचा तो तब इन क्षेत्रों का औसत तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में आसान झील में सबसे पहले दस्तक साइबेरिया के सुर्खाब विदेशी पक्षी ने दी है और सर्दियां बढ़ने के साथ-साथ ही अन्य प्रजातियों के पक्षी भी पहुंचने लगेंगे। कैलाश मानसरोवर तथा उसके आसपास लाल तलाईयों में रहने वाला राजहंस पक्षी अपने जोड़े के साथ नवंबर के प्रथम सप्ताह में उत्तराखंड की झीलों में डेरा डालेंगे। और धीरे-धीरे नवंबर के अंतिम सप्ताह तक उत्तराखंड की सभी झीलें और नदियां प्रवासी पक्षियों के झुंडों से सराबोर हो जाएंगी।

सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा

आपरेशन सिंदूर का अगला चरण और भी घातक होगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर ।

सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह फिर से पहलगाम जैसे हमले करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में आपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण और भी घातक होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, भारत को हजारों जख्म देकर खून बहाने की अपनी नीति पर कायम है और सेना इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने संवाददाताओं से कहा, इस बार हम जो कार्रवाई करेंगे वह पहले से भी जोरदार होगी। वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या आपरेशन सिंदूर का अगला चरण पहले

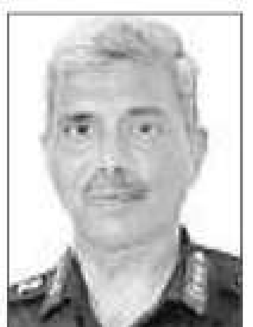

लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, पाकिस्तान, भारत को हजारों जख्म देकर खून बहाने की अपनी नीति पर कायम है और सेना इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

वाले से अधिक घातक होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान भविष्य में पहलगाम जैसे हमले कर सकता है, उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान की सोच में बदलाव नहीं आएगा, वह ऐसी हरकतें करता रहेगा। उन्होंने कहा, उसमें हमसे युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। वे युद्ध नहीं लड़ना चाहते। वह 'भारत को हजार जख्मों से लहूलुहान करने' की अपनी नीति के तहत ऐसी हरकतें करता है।

सैन्य कमांडर ने कहा कि भारत ने आपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा, हमने उसकी चौकियां और हवाई अड्डे तबाह कर दिए, लेकिन वह फिर से कुछ (पहलगाम जैसा हमला) करने की कोशिश कर सकता है। हमें तैयार रहना होगा। हम पूरी तरह तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की कार्रवाई पहले से भी ज्यादा घातक होगी। इससे पहले, पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहलगाम की तरह फिर से हमला करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा, उनमें हमारा सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान अपने मंसूबों से बाज नहीं आएगा, लेकिन भारतीय सेना उसे नाकाम करने के लिए तैयार है। इसके लिए हमें लोगों, खासकर पूर्व सैनिकों, का समर्थन चाहिए। हमें उम्मीद है कि पूर्व सैनिक हमारा साथ देंगे।

भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की, विधानसभा अध्यक्ष का टिकट काटा

13 मंत्रियों और नौ महिला उम्मीदवारों को मिली जगह, 48 मौजूदा विधायकों को फिर मौका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें 13 मंत्रियों और नौ महिलाओं के नाम शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया गया है।

भाजपा नवंबर में होने वाला विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के तहत लड़ रही है। वह 243 विधानसभा सीट में से 101 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। शेष सीटें गठबंधन सहयोगियों के हिस्से में गई हैं जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (एकी) भी शामिल है। भाजपा की पहली सूची में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर और पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को लखीसराय से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया गया है। यादव सात बार पटना साहिब से विधायक रह चुके हैं। पार्टी ने उनकी जगह हाई कोर्ट के वकील और भाजपा नेता रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह, कुम्हरार सीट से पांच बार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा का टिकट भी काटा गया है। उनकी जगह प्रदेश भाजपा के पूर्व महासचिव संजय गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा की पहली सूची में 13 मंत्रियों और नौ महिला उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने 48 मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका दिया है। शेष 30 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाद में की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष यादव ने टिकट कटने पर कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। वहीं, औराई से विधायक व पूर्व मंत्री रामसूरत राय के समर्थकों ने टिकट नहीं मिलने पर प्रदेश मुख्यालय में हंगामा किया और पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। भाजपा में सोमवार को शामिल हुए पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त सुजीत कुमार सिंह को दरभंगा जिले की गौड़ाबौरम सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा ने वर्तमान मंत्री मोतीलाल प्रसाद का टिकट काट दिया है।

गतिरोध वाली सीटों पर राजग में फिर होगी बातचीत

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में गतिरोध वाली सीटों पर विवाद को खत्म करने के लिए फिर से चर्चा होगी। मंगलवार को भाजपा ने सभी सहयोगी दलों को विवाद वाले करीब एक दर्जन सीटों पर उम्मीदवार घोषित न करने के लिए मनाया। सूत्रों का कहना है कि जद (एकी) अपनी कोटे की अहम सीटों को लोजपा (आर) को देने से नाराज है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं पार्टी भाजपा और जद (एकी) की सीट बराबर रखने को लेकर भी नाराज है। ऐसे में उम्मीद है कि जद (एकी) को भाजपा से एक अतिरिक्त सीट मिल सकती है।

मोदी आज बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार को 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उनसे संवाद करेंगे। बिहार भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बनाया कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' कार्यक्रम के तहत लाखों कार्यकर्ताओं को आभासी माध्यम से संबोधित करेंगे। शाम छह बजे होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर भी एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके सुझाव भी मांगे थे।

आयोग ने बिहार विस के चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को दिया निर्देश

उम्मीदवारों को देनी होगी सोशल मीडिया खातों की जानकारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया खातों की जानकारी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करानी होगी। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों को अपने किसी भी विभाग को जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) की मंजूरी भी लेनी होगी।

आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण में मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे की 'अवधि के दौरान थोक 'एसएमएस' और

आयोग के मुताबिक मतदान समाप्त होने से 48 घंटे की 'अवधि के दौरान थोक 'एसएमएस' और 'आडियो मैसेज' भेजना प्रतिबंधित है।

'आडियो मैसेज' (ध्वनि संदेश) भेजना प्रतिबंधित है। मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी मतदान क्षेत्र में टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, सिनेमा हाल में किसी भी चुनावी मुद्दे पर राजनीतिक विज्ञापन, थोक एसएमएस ध्वनि संदेश, ध्वनि-दृश्य प्रचार सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित है। आयोग के मुताबिक 9 अक्तूबर को आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत प्रत्येक पंजीकृत, राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय राजनीतिक दल और प्रत्येक उम्मीदवार को सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रकाशन से पहले सभी राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के वास्ते मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के समक्ष आवेदन करना होगा।

निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन हेतु जिला और राज्य स्तर पर एमसीएमसी का गठन किया गया है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एमसीएमसी से पूर्व-प्रमाणन के बिना राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइट सहित किसी भी इंटरनेट-आधारित मीडिया/वेबसाइट पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

नाराजगी पटना में मंगलवार को टिकट की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन करते लोग।

करीब तीन घंटे चली कांग्रेस की बैठक, 18 सीट पर सहमति बनी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

बिहार की सीटों के उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंगलवार को कांग्रेस की कार्य समिति में हर विधानसभा क्षेत्र के नामों पर चर्चा की गई और करीब तीन घंटे तक यह बैठक चली। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बैठक में 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर सीइसी ने सहमति जताई है।

संभावना जताई जा रही है कि देर रात में ही यह सूची जारी की जा सकती है। इस बैठक की अगुआई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने की। बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से जुड़े। बिहार में कांग्रेस शुरुआत से ही 76 सीट मांग रही थी लेकिन बाद में इन सीटों की संख्या साठ तक आ गई थी। पिछली बार 2020 चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थीं, अब कांग्रेस ने सीधे 6 सीट बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद 76 सीटों को चुना गया था। कांग्रेस ने 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा तो था मगर सीटें केवल 19 ही जीत पाई थी। चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता मदन झा ने बताया कि सिंगल सीटों पर नाम तय कर लिया गया है। 20 से 25 सीट पर दो नाम है।

बची हुई सीटों पर फैसला लेगी उप समिति : सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में 25 नाम तय किए गए हैं और पार्टी के पास पचास सीटों के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने बची हुई सीटों के लिए एक उप समिति का गठन किया गया है। अब कांग्रेस की उप समिति ही बिहार की शेष सीटों के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी। इसी बीच देर रात कुछ उम्मीदवारों के समर्थक भी पार्टी मुख्यालय में मौजूद थे, जो कि पार्टी के निर्णय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।

टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप, मुख्यमंत्री आवास के बाहर विधायक का धरना

जद (एकी) सांसद ने की इस्तीफे की पेशकश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

बिहार विधानसभा चुनाव की टिकट वितरण को लेकर पटना में दिनभर जद (एकी) में हंगामा चला। गोपालपुर सीट को लेकर एक ही संसदीय क्षेत्र से आए सांसद ने टिकट वितरण में गडबड़ी का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश की, जबकि दूसरी तरफ विधायक ने टिकट कटने के डर से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया।

दरअसल, मंगलवार को भागलपुर से पार्टी के सांसद अजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर टिकट बंटवारे में मनमानी का आरोप लगाते हुए सांसद पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। वहीं, दूसरी तरफ भागलपुर जिले के गोपालपुर से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने मुख्यमंत्री आवास पर धरना दिया। वह काफी देर तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की मांग करते रहे। जब मुख्यमंत्री उनसे मिलने नहीं आए तो मंडल अपने समर्थकों के साथ आवास के बाहर ही बैठ गए। यह नाटक काफी देर तक चला। अपने पत्र में सांसद अजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से त्यागपत्र देने की अनुमति मांगी है। उन्होंने लिखा कि वह पिछले 20-25 वर्षों से संगठन और जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हाल के महीनों में संगठन में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो पार्टी और उसके भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण की प्रक्रिया में स्थानीय सांसद होने के बावजूद उनसे कोई सलाह नहीं ली जा रही है।

'महागठबंधन' आज सीट बंटवारे का एलान कर सकता है

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी महागठबंधन के घटक दल सीट के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और इसका एलान बुधवार सुबह तक किया जा सकता है। यह जानकारी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने मंगलवार को दी। पत्रकारों से बातचीत में दुबे ने कहा, महागठबंधन के सभी दल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर सावधानीपूर्वक चर्चा कर रहे हैं। सीट बंटवारे की घोषणा बुधवार सुबह तक होने की संभावना है। भाजपा द्वारा अपने उम्मीदवारों की आंशिक सूची जारी किए जाने पर दुबे ने दावा किया कि इससे राजग के भीतर घमासान का संकेत मिलता है।

भाकपा (माले) लिबरेशन ने 18 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

बिहार में विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति अब तक नहीं बनी है। बावजूद इसके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन ने अपने 18 प्रत्याशियों के नाम तय करने के बाद नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पार्टी को उम्मीद है कि विपक्षी गठबंधन में कुछ और सीट मिलेंगी, जिसपर बातचीत जारी है। महागठबंधन के घटक दल भाकपा(माले) लिबरेशन ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सीट बंटवारे पर विपक्षी गठबंधन के इस फैसले से आपसी खींचतान को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पार्टी नेता ने गठबंधन में सब ठीक होने का दावा किया।

पेज 1 का बाकी

भारत में 15 अरब डालर का निवेश करेगी गूगल

में इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गूगल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ' भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके बहुत अच्छा लगा, हमने विशाखापत्तनम में पहले गूगल कृत्रिम मेधा केंद्र के लिए अपनी योजनाओं को साझा किया जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

'पिचाई ने लिखा, 'यह केंद्र गीगावाट स्तरीय कंप्यूटिंग क्षमता, एक नया अंतरराष्ट्रीय सब-सी गेटवे और विशाल ऊर्जा अवसंरचना को एक साथ लाता है। इसके माध्यम से हम अपनी उद्योग-अग्रणी प्रौद्योगिकी को भारत के उद्यमों एवं उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाएंगे जिससे कृत्रिम मेधा नवोन्मेषण में तेजी आएगी और देश भर में विकास को गति मिलेगी।' इसके अलावा अरबपति गौतम अडाणी के समूह की प्रमुख कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज ने कहा कि उसकी संयुक्त उद्यम कंपनी अडाणीकानेक्स और गूगल, विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम मेधा डेटा केंद्र परिसर और नई हरित ऊर्जा अवसंरचना विकसित करेंगे। गौतम अडाणी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अडाणी (समूह) को विशाखापत्तनम में भारत के सबसे बड़े कृत्रिम मेधा डेटा केंद्र परिसर के निर्माण के लिए गूगल के साथ साझेदारी करने पर गर्व है। इसे विशेष रूप से कृत्रिम मेधा से जुड़ी जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है।

गूगल ने विशाखापत्तनम में उद्देश्य-निर्मित, गीगावाट स्तरीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए भारती एअरटेल के साथ भी साझेदारी की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सुविधा भारत में जटिल कृत्रिम मेधा कार्यों को अंजाम दे सके। इस परियोजना के एक हिस्से के रूप में एअरटेल विशाखापत्तनम में एक अत्याधुनिक केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) स्थापित करेगी, जहां गूगल के नए अंतरराष्ट्रीय सब-सी केबल बिछाए जाएंगे। दूरसंचार सेवा प्रदाता परियोजना के एक हिस्से के रूप में लचीलापन एवं क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना के एक भाग के रूप में एक सुदृढ़, उच्च क्षमता, कम विलंबता वाला शहर के भीतर तथा शहर के बीच 'फाइबर नेटवर्क' बनाएगी तथा उसका प्रबंधन करेगी।

विशाखापत्तनम में गूगल का कृत्रिम मेधा केंद्र पांच वर्ष (2026-2030) में करीब 15 अरब अमेरिकी डालर का बहुआयामी निवेश है, जिसमें गीगावाट स्तरीय डेटा केंद्र संचालन शामिल है जो एक मजबूत सब-सी केबल नेटवर्क और स्वच्छ ऊर्जा द्वारा समर्थित है। इसका मकसद भारत में सबसे जटिल कृत्रिम मेधा कार्यों को अंजाम देना है।

कंपनी ने बयान में कहा कि इसे अडाणीकानेक्स और एअरटेल सहित परिवेश भागीदारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2014 से कई नीतिगत प्रणालियां शासन का हिस्सा रही हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू की सराहना करते हुए सीतारमण ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में दिखाया कि वह डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गूगल ने पहले 10 अरब डालर के निवेश की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 अरब डालर कर दिया गया है।

महाराष्ट्र में शीर्ष नक्सली भूपति समेत 61 ने आत्मसमर्पण किया

में से एक माना जाता था और उसने लंबे समय तक महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर प्लाटून अभियानों की निगरानी की थी। हालांकि, हाल के महीनों में उनके और शीर्ष नक्सली नेतृत्व के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण आंतरिक संघर्ष छिड़ गया।

सूत्रों ने कहा कि भूपति ने दावा किया था कि सशस्त्र संघर्ष विफल हो गया है और घटते जन समर्थन और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के हताहत होने का हवाला देते हुए शांति व संवाद की ओर रुख करने की अपील की थी। सूत्रों ने बताया कि उसके इस रुख का अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिन्होंने किसी अन्य नेता के नेतृत्व में लड़ाई जारी रखने का फैसला किया।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय नक्सली नेतृत्व के दबाव में, भूपति अंततः हथियार डालने के लिए तैयार हो गया, संगठन छोड़ने की घोषणा की और अपने समर्थकों के साथ गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हाल के महीनों में, गढ़चिरौली जिले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ रही है।

भूपति और 60 नक्सलियों के आत्मसमर्पण को राज्य में माओवादी आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में भूपति की पत्नी तारक्का ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। वह प्रतिबंधित आंदोलन की दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति की सदस्य थी। तीन अक्तूबर को राज्य पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि राज्य में नक्सल आंदोलन समाप्ति की ओर है। फडणवीस ने कहा था कि हम माओवाद को खत्म करने के करीब हैं। महाराष्ट्र में, यह कभी भी खत्म हो सकता है। इस महीने की शुरुआत में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से 49 पर एक करोड़ रुपए से अधिक का इनाम था।

आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए : राहुल ...तो आइपीएस नहीं बन पाएगा गरीब : चिराग

सदी में ऐसा होगा तो गरीब आइपीएस अधिकारी नहीं बन पाएगा। इस बीच, हरियाणा सरकार ने पूरन कुमार आत्महत्या मामले में विवाद बढ़ते हुए देख कर डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है और उनकी जगह आइपीएस ओमप्रकाश (ओपी) सिंह को हरियाणा का कार्यवाहक डीजीपी बना दिया है।कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं से देश के करोड़ों दलित परिवारों को यह गलत संदेश जाता है कि चाहे आप कितने भी सफल व सक्षम क्यों न हों, अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया और कुचला जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने परिवार से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को तमाशा बंद करना चाहिए और दिवगंत अधिकारी का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक होने दिया जाना चाहिए। बाद में राहुल गांधी ने बाद में एक्स पर लिखा कि पूरन कुमार की आत्महत्या हमारे समाज और 'सिस्टम' की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है। इससे पीड़ादायक क्या हो सकता है कि उनकी पत्नी एक सप्ताह से अपने पति का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने का इंतजार कर रही हैं। यह परिवार और उनका दर्द महसूस कर पा रहा पूरा दलित समाज जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है, इसकी कल्पना से ही मन विचलित हो रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि आइपीएस वाई पूरन कुमार के घटनाक्रम ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर किया है जिनमें यह दर्शाया गया है कि 21वीं सदी में भी जाति व मजहब के नाम पर भेदभाव हो रहा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में हुए घटनाक्रम में होने वाली कार्रवाई देश के लिए नजीर बनेगी। कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखा और बात की है। इस मामले में जितने भी आरोपी हैं अगर वह दोषी साबित होते हैं उन्हें कानूनन सजा मिलेगी। सरकार की तरफ से परिवार की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

सीट बंटवारे और टिकट बांटने को लेकर तनातनी

चयन को लेकर चल रहे विवाद के बीच पार्टी सांसद अजय कुमार मंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर गहरी नाराजगी जताई है। मंडल ने टिकट बंटवारे में मनमानी का आरोप लगाते हुए सांसद पद से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है और मुख्यमंत्री से त्यागपत्र देने की अनुमति मांगी है। जनता दल एकीकृत (जद(एकी)) के विधायक गोपाल मंडल ने मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास के बाहर टिकट की मांग को लेकर धरना दे दिया।

भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट से लगातार चार बार के विधायक मंडल ने पांचवीं बार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट मांगा है। वह दोपहर में अपने समर्थकों के साथ एक, अणे मार्ग, स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंचे और नारेबाजी करने लगे।

भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट से लगातार चार बार के विधायक मंडल ने पांचवीं बार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट मांगा है। वह दोपहर में अपने समर्थकों के साथ एक, अणे मार्ग, स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। उधर, महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी है। कांग्रेस अधिक सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। वामदलों में भाकपा माले, भाकपा और माकपा ने भी अधिक सीटों की दावेदारी की है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआइपी ने भी अधिक सीटों की मांग की है, इससे राजद के लिए मुश्किलें आ रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोमवार रात को पार्टी उम्मीदवारों को टिकट बांटने की प्रक्रिया उस समय रोक दी, जब उनके पुत्र और पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने हस्तक्षेप करते हुए यह याद दिलाया कि बिहार में 'इंडिया' गठबंधन की सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। देर रात दिल्ली से लौटे तेजस्वी यादव इस घटनाक्रम से नाराज बताए जाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी महागठबंधन के घटक दल सीट के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और इसका एलान बुधवार सुबह तक किया जा सकता है।

अपराध संक्षेप

कार ने साइकिल सवार को कुचला, मौत

नई दिल्ली। धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को कुचल दिया और चालक कार समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राधा कृष्ण मिश्रा (68), निवासी नांगल गांव, ईस्ट सागरपुर के रूप में हुई। घटना 9 अक्तूबर की बताई जा रही है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि फरार चालक की पहचान की जा सके। ब्यूरो

परिचित ने घर बुलाकर मोबाइल लूटा

नई दिल्ली। छावला इलाके में एक व्यक्ति ने अपने परिचित को घर बुलाकर मोबाइल लूट लिया। जानकारी के अनुसार, रोहन लांबा (28), रोशनपुरा, नजफगढ़ में परिवार के साथ रहता है और गोयला डायरी में वेल्डिंग मिस्त्री का काम करता है। उसके परिचित जितेंद्र ने 12 अक्टूबर को घर पर कुछ काम के बहाने बुलाया। वहां जितेंद्र एक अन्य युवक के साथ मौजूद था। बातचीत के दौरान जितेंद्र ने रोहन का मोबाइल देखा और उसे देने को कहा। रोहन के इन्कार करने पर जितेंद्र ने लाठी-डंडे से हमला कर पिटाई की, और साथी के साथ मिलकर उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गया। ब्यूरो

दो गैंग भिड़े, सात नाबालिग समेत नौ गिरफ्तार

नई दिल्ली। राजधानी के मोती नगर, बलजीत नगर, आनंद पर्वत और पांडव नगर क्षेत्रों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर नाबालिगों के दो गैंग आमने-सामने आ गए। भगत सिंह गैंग ने पहले सरकार गिरोह के सरगना शाहरुफ पर हमला किया, जिसके बाद बदले में सरकार गिरोह ने 10 अक्तूबर को भगत सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात में भगत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जांच में जुटी पटेल नगर थाना पुलिस ने सात नाबालिग समेत नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों की पहचान शाहरुफ (19) और हिमांशु कुमार झा (20) के रूप में हुई है, जबकि बाकी सात आरोपी 14 से 17 वर्ष की उम्र के हैं। मध्य जिला डीसीपी निधिन वल्सन के अनुसार दोनों गिरोहों के बीच पिछले कुछ समय से इलाके में वर्चस्व की जंग चल रही थी। ब्यूरो

शराब ठेका खोलने के विरोध में उतरे लोग

नई दिल्ली। स्वरूप नगर स्थित 60 फुटा रोड पर सरकारी शराब का ठेका खोले जाने के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। लोगों ने एसडीएम अलीपुर कार्यालय और जनप्रतिनिधियों के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और ठेका बंद करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले यहां स्कूल का बोर्ड लगाकर लोगों को गुमराह किया गया और फिर रातों-रात ठेका खोल दिया गया। महिलाओं ने ठेके के बाहर धरना देकर आरोप लगाया कि ग्राहक गलियों में बाइक खड़ी कर माहौल बिगाड़ रहे हैं। ब्यूरो

67 किलो अवैध पटाखों के साथ सप्लायर पकड़ा

नई दिल्ली। त्योहारों से पहले रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ ने कार्रवाई करते हुए एक सप्लायर को 67 किलो अवैध पटाखों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजकुमार उर्फ राजू (53), निवासी सेक्टर-20 रोहिणी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि वह लंबे समय से आसपास के दुकानदारों को अवैध पटाखे सप्लाई करता था। डीसीपी राजीव रंजन के अनुसार, टीम ने सूचना के आधार पर छापा मारकर आरोपी को पकड़ा। ब्यूरो

एमसीडी की लापरवाही पर मुख्यमंत्री और मंत्री दिखे नाराज

रेखा गुप्ता ने कहा, काम नहीं करेंगे तो सरकार से सहयोग की उम्मीद न रखें, सफाई फंड खर्च नहीं होने पर आशीष सूद भड़के

विनोद डबास

नई दिल्ली। एमसीडी की कार्यप्रणाली से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक नाराज हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने अलग-अलग बैठकों में एमसीडी के नेताओं और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। एमसीडी की निष्क्रियता, स्थायी समिति की बैठकों का नियमित न होना और सफाई व्यवस्था में सुधार की धीमी रफ्तार पर सरकार ने प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या एमसीडी अब केवल नाम की संस्था बनकर रह गई है। इसके पास किसी काम पर चर्चा करने लायक भी प्रस्ताव नहीं हैं? वहीं, मंत्री ने सफाई व्यवस्था के लिए जारी सरकारी फंड का उपयोग न होने पर अधिकारियों को कठघरे में खड़ा किया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्थायी समिति की बैठकों के टलते रहने को गंभीर लापरवाही करार दिया। उन्होंने कहा कि समिति की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए, ताकि नीतिगत निर्णय समय पर लिए जा सकें। अगर समिति निष्क्रिय रहेगी तो जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि दिल्ली के समग्र विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए एमसीडी ठोस योजनाएं तैयार करे और उन पर अमल सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि एमसीडी को उनकी सरकार सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए एमसीडी को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि काम सही ढंग से नहीं होगा तो दिल्ली सरकार से सहयोग की उम्मीद न करें। लिहाजा जनता के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने डीबीसी कर्मचारियों की समस्या दूर नहीं करने पर भी नाराजगी जताई।

सरकार चाहती है कि एमसीडी अपने स्तर पर निर्णय प्रक्रिया तेज करे। जनता के मुद्दों पर गंभीरता से काम करे। सरकार की इस सख्त रुख से एमसीडी के भीतर हलचल तेज हो गई है। इस कड़ी में उसने मंगलवार को डीबीसी कर्मचारियों की समस्या दूर करने की पहल की।

सफाई फंड पर मंत्री की फटकार

मुख्यमंत्री के बाद, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने भी एमसीडी के नेताओं व अधिकारियों की बैठक बुलाई और सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी को सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष फंड जारी किया था, लेकिन अब तक उसका उपयोग नहीं किया गया है। मंत्री ने पूछा कि जब संसाधन और बजट दोनों उपलब्ध हैं, तो बजट का उपयोग क्यों नहीं हो रहा और सफाई व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं दिख रहा? बैठक में पता चला कि एमसीडी ने अब तक सरकार से मिले फंड का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं किया है।

फंदा लगाकर रील बनाते हुए 14 साल के किशोर की मौत

टूल पर पैर लड़खड़ाने से फंदा गले में कसा, पूरी घटना वीडियो में कैद

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। केशवपुरम इलाके में फंदा लगाकर रील बना रहे 14 साल के छात्र की जान चली गई। रील बनाते हुए टूल पर छात्र का पैर लड़खड़ाने पर वह फंदे पर लटक गया। पूरी घटना वीडियो में कैद हो गई है। पुलिस को छात्र के मोबाइल से 40 मिनट का वीडियो मिला है। वीडियो में वह बार-बार फंदे को पंखे से लगाकर उसको गले में डालता हुआ दिख रहा है। इसी दौरान उसका पैर लड़खड़ा गया। जब परिवार वाले कमरे में पहुंचे तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस ने आशंका जताई है कि रील बनाने के दौरान घटना हुई है।

जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि घटना रविवार दोपहर तीन बजे की है। दीपचंद बंधु अस्पताल से केशवपुरम थाना पुलिस को एक 14 साल के लड़के के फंदे पर लटकने से मौत होने की सूचना मिली। पूछताछ में पता चला कि लड़का शांति नगर त्रिनगर में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार वालों ने बताया कि वह नौवीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता एक प्रॉपर्टी डीलर फर्म में काम करते हैं और उसकी मां गृहिणी हैं। मृतक की एक बड़ी बहन है जो 12वीं कक्षा में पढ़ती है।

पुलिस ने उस कमरे की छानबीन की, जिसमें छात्र ने खुदकुशी की थी। पुलिस को कमरे में पर्दे पंखे से बंधा मिला। परिवार वालों ने बताया कि छात्र इसी फंदे में लटका हुआ मिला। उसे फंदा से उतारकर अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

नौवीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र मोबाइल को दूर रखकर फंदे को गले में डालकर बना रहा था रील

40 मिनट का वीडियो मिला

पुलिस को कमरे में जांच के दौरान एक मोबाइल फोन मिला जिसमें वीडियो बन रहा था। जांच में पता चला कि वीडियो 40 मिनट का है। उसे देखने पर पता चला कि छात्र ने फंदा लगाने का रील बना रहा था। वह पर्दे के एक छोर को पंखे में बांधने के बाद दूसरे छोड़ को फंदा बनाया। उसके बाद वह बार बार टूल पर चढ़ने के बाद फंदे को अपने गले में डाल रहा था। एक बार उसका पैर लड़खड़ा गया और उसके गले में फंदा कस गया। जिससे वह फंदे पर लटक गया। कुछ देर बाद परिवार के सदस्य उस कमरे में आए और छात्र को फंदे पर लटकता देख उसे फंदे से उतारा और अस्पताल लेकर गए।

छात्रा ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप, एफआईआर दर्ज

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली में स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (एसएयू) की छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित छात्रा ने कहा कि उसके साथ परिसर में सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आरोपी चार लोग थे जो वहां निर्माण कार्य में लगे थे। दक्षिण जिले की मैदानगढ़ी थाना पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर मंगलवार को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

इस घटना के विरोध में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। एसएयू ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि वह अपने विद्यार्थियों के साथ खड़ी है। दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि छात्रा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज किए जाने के एक दिन बाद 13 अक्तूबर को वह परिसर में घायल अवस्था में पाई गई और उसके कपड़े फटे हुए थे। पीसीआर (पुलिस नियंत्रण कक्ष) को किए गए फोन पर बताया गया था कि दक्षिण दिल्ली के छतरपुर में एसएयू से लापता हुई छात्रा परिसर में घायलावस्था में मिली है। एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

उन्होंने बताया कि परिसर में तलाशी के बाद छात्रा विश्वविद्यालय सभागार के पास मिली। उसे मेडिकल जांच के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया। उसकी काउंसलिंग की जा रही है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसे सभागार के पास चार लोगों ने खींच लिया था।

कोटा से आई थी दिल्ली : छात्रा कोटा में एक साल बिताने के बाद पखवाड़े भर पहले ही एसएयू परिसर में आई थी। काउंसलिंग के दौरान छात्रा ने बताया कि माता-पिता के एक-दूसरे से अलग होने के बाद से वह अवसाद का इलाज करा रही है। उसके पिता बिहार में और मां मुंबई में रहती हैं।

दिल्ली की एसएयू में छात्रा यौन उत्पीडन का मामला

10 मिनट कैमरों की जद से बाहर रही

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीड़ित छात्रा सिर्फ 10 मिनट कैमरों की जद से बाहर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पीड़ित छात्रा रात 8 बजे हॉस्टल से निकली थी। वह रात 11.15 बजे वापस आकर अपने दोस्तों से मिली थी। इस दौरान वह सिर्फ 10 मिनट सीसीटीवी कैमरों की जद से बाहर रही। इस दौरान जिस जगह पर छात्रा थी उसी तरफ कोई आता-जाता नहीं दिखाई दिया।

यौन उत्पीड़न की घटना निंदनीय : एबीवीपी

नई दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना की निंदा की है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार से त्वरित एवं निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी दिल्ली के प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। एबीवीपी पीड़िता के साथ खड़ी है। ब्यूरो

महिला से लाखों की ठगी, आरोपी के चीनी नागरिक से लिंक मिले

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को शाहदरा जिला साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रजिब दत्ता के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से आईफोन बरामद किया, जिसमें चीनी नागरिक से चैट और लिंक मिले हैं। जांच में आरोपी के बैंक खाते में 50 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन का पता चला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि शाहदरा निवासी शिखा गुप्ता सोशल मीडिया के जरिये कुछ लोगों के संपर्क में आई थीं। उन्हें विदेशी कंपनी में निवेश कर मोटा मुनाफा देने का लालच दिया गया। पीड़िता ने करीब 2.90 लाख रुपये निवेश किए। बाद में आरोपियों ने फर्जी मुनाफे के स्क्रीनशॉट भेजकर विश्वास दिलाया और फिर अधिक पैसों की मांग करने लगे। संदेह होने पर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दी।

जांच में पता चला कि ठगी की रकम एक निजी बैंक खाते में गई थी। पुलिस ने उस खाते से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जांच की। सुरागों के आधार पर टीम ने उत्तराखंड में छापेमारी कर पश्चिम बंगाल निवासी रजिब दत्ता को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी के फोन और खाते की जांच में सीधे चीनी नागरिक से संबंध मिलने की पुष्टि हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे गिरोह के नेटवर्क और विदेशी कड़ी का पता लगाने में जुटी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इससे पहले गिरोह के बदमाश कितने लोगों को ठगा है। जांच के बाद खुलासा होने की उम्मीद है।

शाहदरा पुलिस ने गिरोह के एक बदमाश को दबोचा, खाते में 50 लाख से अधिक का लेनदेन

लखनऊ का युवक गिरफ्तार, फोन से मिले आपत्तिजनक फोटो

नई दिल्ली। पश्चिम जिला साइबर सेल ने सोशल मीडिया पर महिला बनकर महिलाओं से दोस्ती करने और फिर ब्लैकमेल कर उगाही करने के आरोपी लखनऊ निवासी मनोज वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर महिलाओं से संपर्क करता था। वह उनसे निजी तस्वीरें और वीडियो हासिल कर उन्हें वायरल करने या परिचितों को भेजने की धमकी देकर पैसे मांगता था।

21 सितंबर को एक महिला ने आरोपी के खिलाफ ब्लैकमेल और उगाही की शिकायत की थी। जांच में मिले मोबाइल नंबर, यूपीआई ट्रेल और आईपी लॉग से आरोपी की पहचान हुई। दिल्ली पुलिस ने लखनऊ में स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें अश्लील तस्वीरें, वीडियो और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट लॉग इन मिले। पूछताछ में उसने अपराध कबूल किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी पीड़ितों पर दबाव बनाने के लिए उनकी तस्वीरों से नए फर्जी अकाउंट बनाता था। उसके सहयोगियों की तलाश जारी है। ब्यूरो

डीबीसी कर्मचारियों के समर्थन में आप पार्षदों ने किया हंगामा

नई दिल्ली। एमसीडी की सदन बैठक में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स (डीबीसी) और कॉन्ट्रेक्ट फील्ड वर्कर्स (सीएफडब्ल्यू) कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की मांगों और उनके साथ हो रहे अन्याय को लेकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराई। उनके शांत नहीं होने पर महापौर राजा इकबाल सिंह को एक बार बैठक 10 मिनट तक स्थगित करनी पड़ी। पुनः बैठक शुरू होने पर सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला।

बैठक में आते ही आप पार्षदों ने डेंगू-मलेरिया नियंत्रण में लगे डीबीसी व अन्य कर्मचारियों के हक में नारेबाजी शुरू की। इस कारण बैठक की कार्यवाही बाधित हो गई। महापौर ने उनको कई बार शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वह नारेबाजी करते रहे। इस दौरान आप पार्षदों ने कहा कि मच्छर योद्धा कहलाने वाले ये कर्मचारी कई दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। एमसीडी प्रशासन और सत्ता पक्ष उनकी सुध नहीं ले रहा। हंगामा बढ़ने पर महापौर राजा इकबाल सिंह को कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

एमसीडी की बैठक में मांगों को लेकर प्रदर्शन करते विपक्षी सदस्य। अमर उजाला

समस्या के समाधान केलिए नौ सदस्यीय समिति गठित

बैठक दोबारा शुरू होने पर आप के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों के दम पर दिल्ली डेंगू-मलेरिया से सुरक्षित रहती है, वही आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच महापौर ने सदन में बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए नौ सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगी। इस घोषणा के बाद विपक्षी पार्षद शांत हुए, लेकिन बहस का दौर जारी रहा।

दिवाली और छठ पर दिल्ली होगी जगमग और स्वच्छ

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। एमसीडी ने दिवाली, छठ पूजा और गुरुनानक जयंती के मद्देनजर राजधानी में रोशनी और सफाई की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। सफाई के लिए साढ़े 12 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सदन की बैठक में महापौर राजा इकबाल सिंह की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

बैठक में कहा गया कि दिवाली, छठ पूजा और गुरुनानक जयंती जैसे पर्वों पर लाखों लोग श्रद्धा और आस्था के साथ भाग लेते हैं, इसलिए दिल्ली में स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महापौर ने कहा कि दिवाली दीपों का पर्व है, ऐसे में पूरे शहर को रोशनी से जगमग करना निगम की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि एमसीडी ने सभी पार्षदों को 50-50 स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ताकि प्रत्येक वार्ड में डार्क स्पॉट खत्म किए जा सकें।

जिन इलाकों में अंधेरा रहता है, वहां स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएं और मंदिरों के आसपास पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। नेता सदन प्रवेश वाही ने आयुक्त से यह सुनिश्चित करने को कहा कि दिवाली से पहले सभी खराब लाइटों की मरम्मत पूरी कर ली जाए और नई लाइटें लगाने का कार्य तेज किया जाए।

छठ पूजा के मद्देनजर सदन ने सभी छठ घाटों की विशेष सफाई, सुरक्षा और नावों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गुरुनानक जयंती के अवसर पर जिन मार्गों से गुरु नानक देव की झांकी निकलेगी, वहां सफाई और प्रकाश व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की बात कही गई।

सदन ने निर्णय लिया कि निगम के सभी विभाग मिलकर त्योहारों के दौरान राजधानी को स्वच्छ, रोशन और सुरक्षित बनाने के लिए संयुक्त अभियान चलाएंगे।

एमसीडी सदन ने पास किया प्रस्ताव, आयुक्त को दिए निर्देश

दिल्ली में वांछित गैंगस्टर जारा अमृतसर से गिरफ्तार

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात सलमान त्यागी-सद्दाम गौरी गैंग के प्रमुख सदस्य तलविंदर सिंह उर्फ जारा को अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 2019 से फरार था और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के एक मामले में घोषित अपराधी था।

डीसीपी कृष्ण कुमार के अनुसार, आरोपी तलविंदर सिंह पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर का निवासी है, 2019 से फरारी काट रहा था। उसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम इंस्पेक्टर मनेंद्र सिंह, नीरज कुमार और संदीप यादव की टीम काम कर रही थी। एक इनपुट के आधार पर अपना नाम बदलकर रह रहे आरोपी तलविंदर को सुल्तानविंड कॉलोनी, अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। यहां उसने अपनी पहचान गुरदास बताई हुई थी। उसने बताया कि वह दिल्ली के अशोक नगर में जन्मा और आठवीं तक पढ़ा है। 2013 में हरिनगर थाना क्षेत्र में अपने साथियों सलमान त्यागी, मनीष उर्फ बुंडा, मनीष उर्फ सनी और प्रिंस उर्फ नकली के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर चाकू और पिस्टल से हमला किया था। आरोपी तलविंदर पश्चिमी दिल्ली में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है।

गुरदास नाम से छिपा था, सलमान त्यागी-सद्दाम गौरी गैंग का सदस्य, 2019 से था फरार

डकैती में वांछित बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में हुई डकैती के मामले में वांछित बदमाश साहिल उर्फ पहलवान (26), निवासी सुलेमान नगर, किराड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी राजौरी गार्डन इलाके में हुई गोलीबारी में शामिल रहा है। डकैती के बाद साहिल फरार हो गया था और बार-बार ठिकाना बदल रहा था। डीसीपी, अपराध शाखा हर्ष इंदौरा ने बताया कि सुल्तानपुरी निवासी जान मोहम्मद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 12 सितंबर को उसकी दुकान पर साहिल सुल्तानपुरिया, ऋषभ उर्फ अम्मा और रोहित उर्फ बहादुर आए। उन्होंने जान मोहम्मद और उसके साथी सलमान पर हमला कर घायल कर दिया। ब्यूरो

डीटीसी की देवी बस ने स्कूल वैन समेत तीन वाहनों को मारी टक्कर

नई दिल्ली। शाहदरा जिले के फर्श बाजार इलाके में मंगलवार दोपहर एक डीटीसी की देवी बस ने स्कूल वैन, बाइक और ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस चालक ने वाहन नहीं रोका और तीनों वाहनों को लगभग 30 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया।

दुर्घटना में स्कूल वैन में सवार आठ साल का बच्चा, बाइक सवार दो युवक और ई-रिक्शा चालक दिनेश घायल हुए। सभी को हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम ने बताया कि घटना काली माता मंदिर, विश्वास नगर के पास हुई। देवी बस आगे चल रही बाइक, ई-रिक्शा और मारुति वैन से टकरा गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चालक सतीश बस पर नियंत्रण खो बैठा था। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

स्कूल वैन में सर्वोदय बाल विद्यालय, सूरजमल विहार के छात्र सवार थे। वैन चालक दिनेश भी हादसे में घायल हुआ। बच्चे का एक दांत टूट गया, जबकि अन्य छात्र सुरक्षित रहे। हादसे के बाद मौके पर भीड़ एकत्र हो गई और कुछ लोगों ने बस का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित कर बस जब्त कर ली। दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ब्यूरो

फर्श बाजार में हादसा, आठ साल के बच्चे समेत चार घायल

नाले में मिला युवक का शव, गले में लिपटी थी रस्सी

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर स्थित अंकुर विहार में मंगलवार सुबह एक युवक का शव नाले में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव पर चोटों के निशान थे और गले में रस्सी लिपटी मिली। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने क्राइम और एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया। शव को बाहर निकालकर पहले जग प्रवेश चंद्र अस्पताल और बाद में जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी भेजा गया। डीसीपी (उत्तर-पूर्व) आशीष मिश्रा ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच है और उसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के थानों में जानकारी जुटा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो

भलस्वा डेयरी हत्या मामले में वांछित बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भलस्वा डेयरी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में वांछित आरोपी प्रिंस चौहान (30) को गिरफ्तार किया है। वह गांव पबसेरा, थाना कुंडली, जिला सोनीपत (हरियाणा) का निवासी है। अदालत ने उसे शाहीनबाग हत्या और नरेला औद्योगिक क्षेत्र में हथियारबंद डकैती के मामलों में भगोड़ा घोषित कर रखा था।

डीसीपी पंकज कुमार के अनुसार, 15 अक्तूबर 2024 को शिकायतकर्ता नासिर पहलवान अपने घर के पास खड़ा था, जब शकील नामक युवक वहां गाली-गलौज कर रहा था। नासिर के टोकने पर शकील अपने साथ प्रिंस चौहान, वकील और अन्य साथियों को लेकर लौटा और फायरिंग कर दी। गोलीबारी में शाहरूख उर्फ आसिफ और नौशाद घायल हुए थे। दोनों को बीजेआरएम अस्पताल, जहांगीर पुरी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान नौशाद की मौत हो गई।

जांच में पुलिस ने अब तक जुबेर, अंकित उर्फ विक्की, शकील और शिवम उर्फ शुभम उर्फ शिबू को गिरफ्तार किया था, जबकि प्रिंस चौहान फरार था। टीम ने तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर प्रिंस चौहान को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो

अदालत ने शाहीनबाग हत्या और नरेला डकैती केस में भी भगोड़ा घोषित किया था

हादसे में स्कूटी सवार महिला घायल

नई दिल्ली। दिल्ली कैंट इलाके में एनएच 48 सड़क पर गड्ढे की वजह से स्कूटी सवार महिला घायल हो गई। हादसे में घायल महिला की पहचान सुनीता देवी (45) के रूप में हुई है। उनके बेटे अमित कुमार (26) ने एनएचएआई के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।

डीसीपी (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने बताया कि लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अमित के अनुसार, 8 अक्तूबर की सुबह करीब आठ बजे वह अपनी मां को स्कूटी पर बिठाकर कापसहेड़ा से जहांगीरपुरी जा रहे थे। दिल्ली कैंट स्थित एनएच 48 पर एक गहरे गड्ढे में स्कूटी का पहिया फंस गया। स्कूटी का संतुलन बिगड़ने से उनकी मां सड़क पर गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। राहगीरों की मदद से अमित ने मां को आरआर अस्पताल पहुंचाया, जहां से एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। ब्यूरो

दिल्ली कैंट में एनएच 48 पर हादसा, परिजनों ने एनएचएआई पर लापरवाही का लगाया आरोप

पुलिस ने हथियार गिरोह का भंडाफोड़ कर गैंगवार को रोका

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर संभावित गैंगवार को टाल दिया है। स्पेशल सेल ने इस गिरोह के दो हथियार तस्करों मोहित व मंजय को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 4 अर्ध-स्वचालित पिस्तौल, 4 अतिरिक्त मैगज़ीन, आपत्तिजनक सोशल मीडिया चैट वाले मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं।

भटगांव मालियान, जिला सोनीपत हरियाणा निवासी मोहित (28) ने अपने सहयोगी सलीमसर माजरा, जिला-सोनीपत, हरियाणा निवासी मंजय (28) के साथ मिलकर अपने मामा और परिवार के दो अन्य सदस्यों की हत्या का बदला लेने के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश से ये पिस्तौल खरीदी थीं।

स्पेशल सेल पुलिस उपायुक्त अमित कौशिक ने बताया कि 16 सितंबर को मोहित के बारे में सूचना मिली थी कि वह अपने साथियों के साथ प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों को खत्म करने के लिए हथियार खरीदने मध्य प्रदेश पहुंचा है। पुलिस टीम ने आरोपी मोहित और उसके साथी मंजय को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया।

स्पेशल सेल ने दो हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार

बदला लेने के लिए हथियार खरीदा

मोहित का जन्म और पालन-पोषण सोनीपत (हरियाणा) जिले के भटगांव गांव में हुआ। इसने वर्ष 2017 में अपने गांव के दीपक के ऊपर विवाद में गोलियां चला दीं। उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। वर्ष 2020 में उसके मामा की स्थानीय बदमाशों ने हत्या कर दी। बाद में उसके दूसरे मामा और चचेरे भाई की भी अदालत में गवाही देने जाते समय हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु के बाद वह बदला लेने के इरादे से अपने मामा के परिवार के साथ रहने लगा। 2022 में उसे गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में गिरफ्तार किया गया और दो साल तक जेल में रहा। रिहाई के बाद, बदला लेने के लिए उसके चाचा ने उसे हथियारों का इंतजाम करने को कहा। चाचा की सलाह पर वह हथियार खरीदने मध्य प्रदेश गया।

घरेलू कलह में चाकू से गला रेतकर पत्नी की हत्या का शक

नई दिल्ली। मुनिरका इलाके में घरेलू कलह की वजह से आरोपी ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मृतका थेम्पी खोंगसाई की गर्दन पर घातक चोट के अलावा फेफड़ों में भी चोटें आई थीं। इस कारण वह बेहोश हो गई और फिर उसका गला काट दिया गया।

फिलहाल आरोपी थंगजाम विनी का अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज चल रहा है और वह बयान देने की हालत में नहीं है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि पुलिस ने मृतका की बहन एल्विना लुंकिम से पूछताछ की है। उसने बताया कि मृतका थेम्पी खोंगसाई उसकी बड़ी बहन थी। वह थंगजाम के साथ पिछले तीन साल से मुनिरका गांव में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। ब्यूरो

पोस्टमार्टम में फेफड़ों में चोट से महिला के बेहोश होने के बाद गला रेते जाने की बात आई सामने

राजनेता एक जैसे होते हैं, वे उन जगहों पर पुल बनाने का वायदा करते हैं, जहां नदी भी नहीं होती। -निकिता ख्रुश्चेव

दलित समुदाय से आने वाले हरियाणा कैडर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की आत्महत्या वाकई झकझोरने वाली है। सियासी दलों की सक्रियता स्वाभाविक है, लेकिन इस मामले में अभी कई सवालों के जवाब अनुत्तरित हैं।

आत्महत्या और सवाल

हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या झकझोरने वाली तो खैर है ही, लेकिन जिन परिस्थितियों में यह कदम उठाया गया, उससे कई सवाल उठते हैं, जो अब तक अनुत्तरित हैं। गौरतलब है कि वाई पूरन कुमार मूलतः आंध्र प्रदेश के एक गरीब दलित परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिनके माता-पिता ने काफी कुछ सहते हुए उन्हें इंजीनियर बनाया, बाद में वह आईपीएस बने। अपनी पत्नी, जो खुद एक आईएएस अधिकारी हैं, को लिखे सुसाइड नोट में उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव, मानसिक प्रताड़ना, फर्जी एफआईआर और प्रोन्नति में अनियमितता के आरोप लगाए। ये आरोप काफी गंभीर हैं, जिनकी जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए, लेकिन सवाल उन परिस्थितियों पर भी है, जिनमें कोई सरकारी उच्चाधिकारी उस बिंदु पर पहुंच जाता है, जब उसके सामने आत्महत्या के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। जब एक उच्च शिक्षित अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी की बात ही क्या की जाए? दरअसल, यह मामला उस जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है, जो भारतीय समाज में गहरे तक जड़ें जमाए हुए है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस व्यवस्था से हम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की उम्मीद करते हैं, वह खुद कई बार इनका शिकार बनती हुई दिखती है। हरियाणा सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है, लेकिन ऐसी सतही कार्रवाईयां व्यवस्था में ठोस सुधार का आश्वासन नहीं देतीं। पूरन कुमार की आत्महत्या ने न केवल पुलिस विभाग, बल्कि पूरे समाज को आईना दिखाया है। यह समाज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, जहां समानता के सांविधानिक आदर्श कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। एक पुलिस अधिकारी, जो मुश्किल परिस्थितियों से लड़कर पदसोपान में ऊपर तक पहुंचा हो, अगर व्यवस्था के भीतर ही अपमान व दबाव का शिकार बन जाए, तो यह उन लाखों युवाओं के सपनों को भी कमजोर

करता है, जो मेहनत और लगन से अपने लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। इस मामले में नया मोड़ तब आया, जब रोहतक में तैनात एक एएसआई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में वाई पूरन कुमार पर कई आरोप लगाए। दरअसल, एक दलित पुलिस अधिकारी की आत्महत्या की खबर पर सियासी दलों की सक्रियता स्वाभाविक है, लेकिन इस मामले में अभी कई सवालों के जवाब मिलने शेष हैं। सरकार को चाहिए कि सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से पूरे मामले की जांच कराए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि दोषियों को ऐसी सख्त सजा मिले, जो मिसाल बन सके।

वादे हैं, वादों का क्या

बिहार की राजनीति ने लोगों को जातियों के विभाजनकारी गणित में फंसाकर अंधेरे में छोड़ दिया है। प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी, शिक्षा इत्यादि के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि बिहार कहां खड़ा है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के वायदों ने राज्य को राजनीतिक विरोधाभासों की जीवंत प्रयोगशाला बना दिया है।

बिहार एक ऐसा राज्य है, जो आकांक्षाओं से लबालब होने के बावजूद अभावों की तस्वीर पेश करता है। वहां की राजनीति ने लोगों को जातियों के विभाजनकारी गणित में फंसाकर अंधेरे में छोड़ दिया है। बिहार इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 25 वर्ष से कम आयु की सबसे युवा आबादी का घर है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीडीपी के पैमाने पर यह अपनी युवा जनसांख्यिकी से काफी नीचे है। बिहार में 13 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जो भारत की आबादी का लगभग दसवां हिस्सा है। भारत की 331 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग 3.2 प्रतिशत या मौजूदा कीमतों पर 10.97 लाख करोड़ रुपये है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में कर्नाटक शीर्ष पर है, जहां प्रति व्यक्ति आय 3.80 लाख रुपये सालाना है, राष्ट्रीय औसत 2.35 लाख रुपये है, जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय सालाना 66,828 रुपये है, जो राष्ट्रीय औसत के एक-चौथाई और कर्नाटक की प्रति व्यक्ति आय के छठे हिस्से से भी कम है। बिहार में भी शिवहर, मधुबनी और अररिया जिलों की स्थिति और भी खराब है, जहां प्रति व्यक्ति आय राज्य के औसत का एक-तिहाई है।

शंकर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

प्रगति के मार्ग पर आज बिहार कहां खड़ा है? आज राज्य की प्रति व्यक्ति आय उतनी ही है, जितनी 2012–13 में भारत की थी। 13.1 करोड़ से ज्यादा की आबादी के साथ बिहार ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त आबादी जितना बड़ा है। वास्तव में, बिहार मेक्सिको के साथ, जिसकी जीडीपी 18 खरब डॉलर है, 11वें सबसे बड़े देश के रूप में गिना जाएगा। लेकिन लगभग 125 अरब डॉलर के साथ, यह जीडीपी रैंकिंग में इक्वाडोर और प्यूर्टो रिको के साथ साठ के दशक में होगा।

बिहार की यह स्थिति कई जटिल कारणों से है। राज्य में कराए गए जाति सर्वेक्षण के अनुसार, मुश्किल से 15 फीसदी लोगों ने दसवीं उत्तीर्ण की है और मात्र छह फीसदी लोग ही स्नातक हैं। स्कूलों तक पहुंच पर संसदीय रिकॉर्ड में इसका एक कारण स्पष्ट है। बिहार के एक-तिहाई

गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, 40 फीसदी गांवों में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, मात्र 8.5 फीसदी गांवों में माध्यमिक स्कूल हैं और मात्र पांच फीसदी गांवों में उच्च माध्यमिक स्कूल हैं। विकास के मामले में नीति आयोग ने बिहार को राज्यों में 28वें स्थान पर रखा है और पांच वर्षों में उसे मात्र 255 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है।

बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, मात्र 6.7 फीसदी श्रमिक सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत हैं। आप सोचेंगे कि इतनी युवा आबादी वाला राज्य कौशल विकास के लिए धन का उपयोग कर सकता है। जुलाई, 2024 में केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि उसने कौशल भारत अभियान के तहत बिहार को कौशल विकास योजना के लिए 128.66 करोड़ रुपये आवंटित किए। उसमें से मात्र 36.82 करोड़ रुपये ही जारी किए गए, जिनमें से मुश्किल से 5.96 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया गया! वर्ष 2015 से 2022 के बीच, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 7.59 लाख लोगों में से केवल 1.27 लाख लोगों को ही नौकरी मिली।

विडंबना यह है कि बिहार की विपत्तियां हर सरकार में कायम रही हैं। बिहार में 1989 से 'कांग्रेस-मुक्त' और 2005 से 'जंगलराज-मुक्त' शासन रहा है। लगभग दो दशकों से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में हैं, फिर भी बिहार की स्थिति बदहाल है। चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीख घोषित कर दी है। यही वह मौसम है, जब धूल-गर्मी, शोर-शराबे और बयानबाजी के बीच पार्टियां अपने वायदों का पिटारा खोल देती हैं। राजग और राजद के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन के बीच आगामी चुनावी मुकाबला, असल में योजनाओं की होड़ है। दरअसल, पार्टियों के चुनावी घोषणापत्र अक्सर राजनीतिक अर्थव्यवस्था की हालत का एक जबर्दस्त सबूत होते हैं।

नीतीश कुमार ने तीन बड़े वायदे किए हैं। अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नए रोजगार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपये की नकद राशि, जिसके बाद, आगे भी राशि हस्तांतरित की जाएगी, और स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को दो साल तक 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, 1.6 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा भी किया गया है।

राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन भी इसमें पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 2,500 रुपये, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, रियायती दर पर गैस सिलिंडर देने का वायदा किया है। यह अब चुनावों में आम बात हो गई है। हालांकि तेजस्वी ने राज्य के हर परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने वाला कानून बनाने का वायदा करके अपनी रणनीति और भी तेज कर दी है। वायदा है कि शपथ ग्रहण के 20 दिनों के भीतर ऐसा कानून पारित किया जाएगा और 20 महीनों में नौकरियां दी जाएंगी!

ये वायदे हकीकत और कल्पना का मिश्रण हैं। अपने 2025-26 के बजट में, बिहार सरकार ने कुल व्यय 2.94 लाख करोड़ रुपये रखा है। केंद्र सरकार से विभिन्न मदों में 1.5 लाख करोड़ रुपये के हस्तांतरण से केंद्रीय वित्त पोषण पर उसकी निर्भरता स्पष्ट होती है। अनुमान है कि बिहार में लगभग 2.76 करोड़ परिवार हैं। अगर यह मानें कि कम से कम 1.5 करोड़ लोगों को नौकरियां देने के बाद न्यूनतम 20,000 रुपये वेतन दिए जाएंगे, तो रोजगार सृजन बनाम वित्त पोषण का यह गणित हैरान करने वाला है! एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा के एक शोध में बताया गया है कि बिहार चुनाव-पूर्व वायदों पर अपने जीडीपी (जीएसडीपी) का 2.9 फीसदी खर्च करेगा, जो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी का उच्च स्तर उतना ही चिंताजनक है, जितना कि राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे काल्पनिक वायदे।

बिहार वाकई राजनीतिक विरोधाभासों की जीवंत प्रयोगशाला है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन दरारों का प्रतीक है, जो भारत के उत्थान में बाधक हैं। यहां राजनीतिक गुणवत्ता इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों का जीवन जुड़ा है। राष्ट्र को निष्क्रियता की जो कीमत चुकानी पड़ेगी, वह राजनीतिक दलों द्वारा टाली जा रही लागत से कहीं ज्यादा होगी!

edit@amarujala.com

जीवन धारा

तोबियास बेक

हमें अपने अतीत के साथ जीने की भी जरूरत है। पुराने अनुभव हमें आकार देते हैं और उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन हर वक्त अतीत में डूबे रहना समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है।

जीवन हर पल नया आकार ले रहा है

अक्सर लोग अपने बीते समय के बारे में बात करते हैं और उसे मौजूदा समय से बेहतर बताते हैं। क्या वाकई ऐसा है? लोग अपने बीते समय का बखान इस तरह करते हैं, जैसे-वे स्वर्ग में या किसी और ग्रह पर रहते रहे हों। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग इसे स्वचालित रूप से करता रहता है? समय के साथ, हम नकारात्मक यादों को मिटा देते हैं और केवल अपने शानदार अनुभव को ही याद रखते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने पुराने रिश्तों के बारे में बात करते हैं, जिन्हें वे अब भी भुला नहीं पाए हैं। अचानक, दिमाग हर चीज को एक गुलाबी रोशनी से ढंक देता है और सारी कड़वाहट गायब हो जाती है।

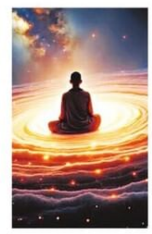

कुछ लोग अब भी पुरानी तस्वीरों को निहारते हैं, अपने पूर्व साथी के पसंदीदा गाने सुनते हैं, न जाने कितनी तरह से उसकी यादों में अपना समय गंवाते हैं। मेरा मानना है कि यह बहुत सुंदर काम नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है, इसे दुखों पर ध्यान देने और ऊर्जा बर्बाद करने में नष्ट नहीं किया जा सकता। संयोग से, पाषाण युग में लोगों के पास ऐसी बकवास करने के लिए समय नहीं था। दरअसल, उनके लिए अपने अस्तित्व को बचाए रखने का नाम ही जीवन था। ऐसा क्यों है कि नकारात्मक स्मृतियां दब जाती हैं और सकारात्मक कायम रहती हैं। कल्पना करें कि आप पाषाण युगीन मानव हैं और शिकार के लिए अपनी गुफा से निकलते वक्त अचानक आपको एक दिन पहले का किसी शिकारी जानवर के पंजे से बच निकलने का मंजर याद आ जाता है। यह विचार एक व्यवधान उत्पन्न करेगा और इस प्रकार उस समय का आदर्श वाक्य बना होगा : 'खाओ या खा लिए जाओ।' यह हमारे दिमाग का सबसे युवा हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कोरटेक्स यानी हमारे माथे वाला हिस्सा, यह हमारे सुरक्षात्मक मैकेनिज्म के लिए जिम्मेदार है और मुझे खुशी है कि यह मौजूद है। हालांकि हमें अपने अतीत के साथ जीने की भी जरूरत है, हमारे पुराने अनुभव हमें आकार देते हैं और उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। पुरानी खस्ताहाल कारों की तरह हम दुनिया की राहों से गुजरते हैं, खरोंचे और ठोकरें खाते हैं, लेकिन इंजन हमेशा चालू रखते हैं। इसके अलावा, ये खरोंचें और निशान हमारे अपने होते हैं, जो हमें अद्वितीय बनाते हैं। मैं आपकी खरोंचों को पूरी तरह समझता हूं और मुझे लगता है कि इसी वजह से हम यहां हैं। हम सभी अपनी पीठ पर चिंताओं, समस्याओं और चुनौतियों के बोझ की आभासी गठरी लादे घूमते रहते हैं। ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गठरी को खोलकर बोझ निकाला जाए और उसका समाधान किया जाए, बजाय इसके कि हर किसी को बताया जाए कि आपकी पीठ पर कितना बोझ है। खुद को अपने अतीत से परिभाषित करना बंद करें। आज से और अभी से हर पल का आनंद लें, क्योंकि आपका जीवन हर पल नया आकार ले रहा है।

('अनबॉक्स योर लाइफ' के अनूदित अंश)

अतीत से सिर्फ सीख लें

सूत्र

हमें अपने जीवन के व्यक्तिगत पाठ्यक्रम का पता करने के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। अपने उतार-चढ़ाव, वक्र इत्यादि का सूक्ष्म मुआयना करते रहें। अपने मित्रों से चर्चा करें और सुनिश्चित करें कि आज से आपके जीवन का पैमाना ऊपर की तरफ जाएगा। अहम बात यह है कि अतीत में डूबे रहने के बजाय उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ना ही जीवन का सार है।

दूसरा पहलू

एक परिवार बीती एक सदी से उसी मकान में अब भी रह रहा है, जो चार अलग-अलग देशों की सीमा में रह चुका है।

चार देश, चार पीढ़ियां और एक मकान

इसी गर्मी में कुछ समय पहले तीस वर्षीय इंजीनियर एलेक्स जिगांते ने मुझसे कहा, 'आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे परिवार में सभी लोग चार अलग-अलग देशों से आए हैं।' उनकी परदादी एंजेला, ऑस्ट्रिया-हंगरी में पैदा हुई थीं। उनकी 90 वर्षीय दादी मारिया इटली में पैदा हुई थीं। उनके 61 वर्षीय पिता एल्डो यूगोस्लाविया में पैदा हुए थे, जबकि एलेक्स का जन्म और पालन-पोषण स्लोवेनिया में हुआ है। फिर भी, वे सभी अपना जीवन यहीं पोर्टोरोज में बिताते हैं, जो दक्षिण-पश्चिमी स्लोवेनिया में एक समुद्र तटीय गांव है, जहां परिवार की जड़ें सदियों पुराने वेनिस साम्राज्य तक जाती हैं, और जहां उनका साधारण तीन मंजिला घर हमेशा बदलते मानचित्र पर स्थिर रहा है।

शेनन सिम्स

एलेक्स जिगांते का घर स्थिर रहा, लेकिन उसके चारों ओर सीमाएं बदलती रहीं तथा सेनाएं आती-जाती रहीं।

एलेक्स कहते हैं, 'हमारा घर तब भी स्थिर रहा, जब दुनिया बदल रही थी।' यहां इस्त्रियन प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर, जहां एड्रियाटिक सागर इटली को मध्य यूरोप से अलग करता है, एक सदी के युद्धों और क्रांतियों ने एक ऐसे समुदाय को पीछे छोड़ दिया है, जिसके लिए राष्ट्रीय पहचान अक्सर सिर्फ राजनीति का विषय होती है। क्रोएशिया के रिजेका विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर मिला ओरलिक कहती हैं कि 20वीं सदी में यहां सत्ता में आने वाले हर राष्ट्र ने लोगों पर नए रीति-रिवाज और कानून थोपे। लेकिन स्थानीय आबादी परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए अपनी पहचान बचाने में सफल रही। एलेक्स जिगांते का घर स्थिर रहा, लेकिन उसके चारों ओर सीमाएं बदलती रहीं तथा सेनाएं आती-जाती रहीं। शीत युद्ध के दौरान पैदा हुआ एल्डो जिगांते घर पर इस्त्रियन बोली, स्कूल में इतालवी और शहर में स्लोवेनियाई भाषा बोलता था। लेकिन पोर्टोरोज के ज्यादातर घरों में ऐसा ही है। इनमें से ज्यादातर घरों का इतिहास अनुमान से कहीं ज्यादा पुराना है। 19वीं शताब्दी के दौरान, परिवार ने यहां एक साधारण-सा घर बनाया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद साम्राज्य इटली के साम्राज्य के अधीन हो गया, फिर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान एक जर्मन कब्जा क्षेत्र में, फिर कुछ समय के लिए यूगोस्लाव कट्टरपंथियों के अधीन, फिर एंग्लो-अमेरिकन और यूगोस्लाव सैन्य कब्जा, फिर अल्पकालिक मुक्त क्षेत्र ट्राइस्टे, फिर वापस इटली, फिर यूगोस्लाविया और अंततः साम्यवादोत्तर स्लोवेनिया में। 1990 के दशक तक इस परिवार को देशों के विभाजन, सीमाओं के बदलाव और भाषाई संघर्ष में कई कष्ट सहने पड़े। फिर भी, जिगांते परिवार खुश है कि सब कुछ बदल गया, लेकिन उनका पुश्तैनी मकान पीढ़ी-दर-पीढ़ी उन्हें शरण दिए हुए है।

शीत युद्ध के दौरान पैदा हुआ एल्डो जिगांते घर पर इस्त्रियन बोली, स्कूल में इतालवी और शहर में स्लोवेनियाई भाषा बोलता था। लेकिन पोर्टोरोज के ज्यादातर घरों में ऐसा ही है।

©The New York Times 2025

आंकड़े

खतरनाक शहर

यूरोप के कुछ शहर ऐसे हैं, जिनके आधे से ज्यादा नागरिक अपराध सूचकांक में अपने शहर को ज्यादा खतरनाक मानते हैं।

ब्रैडफोर्ड	67.1
मार्सिले	65.3
कॉवेंट्री	65
बर्मिंघम	64.4
नैपल्स	62.8

आंकड़े अपराध सूचकांक में शहरों की स्थिति | स्रोत : Numbeo, as of August 2025

भक्त जैसा दूध का काम करते थे। एक दिन उन्होंने भूखे होने के बावजूद अपने हिस्से का भोजन महात्मा को दे दिया। इसके बाद उनकी किस्मत ही बदल गई।

सच्चा दान

आंबेर के पहाड़ के पीछे भूतेश्वर महादेव मंदिर में स्वामी मंगलवन नाम के तपस्वी योगी रहते थे। वह बड़े ही विनम्र और महायोगी थे। जिस पर उनकी कृपादृष्टि हो जाती, उसका कल्याण हो जाता। बताते हैं कि नांगल के एक धनकुबेर जैसा बोहरा को स्वामी मंगलवन की कृपा से ही लक्ष्मी जी की सिद्धि हुई।

जैसा पहले दूध का काम करते थे। वह महाराज जी को मंदिर में दूध दे आया करते थे। कभी-कभी वहां पर भोजन का प्रबंध भी कर देते थे। एक दिन जैसा और उनके दो भाइयों ने भोजन बनाया। जैसा जंगल में चले गए। इसी बीच एक महात्मा आए और उन्होंने भोजन मांगा, भाइयों ने कहा, 'जैसा साधु-संतों को लुटाता है, वह आकर देगा।' जैसा के आने से पहले भाइयों ने अपने हिस्से का भोजन खा लिया। वह लौटे, तो महात्मा बैठे मिले और भोजन मांगा। जैसा ने तेज भूख लगने पर भी अपने हिस्से का भोजन महात्मा को दे दिया। महात्मा बोले, 'इस पर कपड़ा ढक दो।' इसके बाद उस भोजन में महात्मा जी, जैसा और आने-जाने वाले कई लोगों ने भोजन किया, फिर भी भोजन खत्म नहीं हुआ। महात्मा जी ने जैसा को आशीर्वाद देकर कहा, 'आज तुमने सच्चा दान किया है। वह इन्सान सच्चा दानी होता है, जो अपने से पहले दूसरों की भूख मिटाता है।' उन महात्मा के वेश में स्वामी मंगलवन ही जैसा के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए आए थे। इसके बाद जैसा का कारोबार इतना बढ़ा कि वह राजा-महाराजाओं तक को धन उधार देने लगे।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 15 अक्तूबर, 1954

भारत ने एकतरफा कार्यवाही पर भी पाकिस्तान को पानी दिया

भारत ने एक तरफा कार्यवाही होने पर भी पाकिस्तान को पानी दिया

विश्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि भारत ने नहरी पानी पर विश्व बैंक के फैसले को स्वीकार कर लिया, पर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। एकतरफा कार्यवाही के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को पानी देना नहीं रोका।

ग्रीन हाइड्रोजन : उम्मीद या छलावा?

जिस ग्रीन हाइड्रोजन को पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान माना जा रहा है, उसका सफर मुश्किलों से भरा है, पर भारत के लिए यह अवसर भी है।

कुमार सिद्धार्थ | मुद्दा

दुनिया जिस तीव्रता से जलवायु संकट की ओर बढ़ रही है, उसके बीच 'ग्रीन हाइड्रोजन' को एक ऐसे ईंधन के रूप में देखा गया, जो भविष्य की ऊर्जा-व्यवस्था को नया स्वरूप दे सकता है—जो न तो प्रदूषण फैलाता है, न ही सीमित भंडारों पर निर्भर है। लेकिन जैसे-जैसे योजनाएं धरातल पर आईं, यह सपना कठिन और महंगा साबित होने लगा। जो हाइड्रोजन पर्यावरण बचाने का प्रतीक मानी जा रही थी, वही अब तकनीकी जटिलताओं, भारी लागत और अनिश्चित नीतियों के बोझ तले हांफती दिख रही है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर उत्साह की लहर अब थोड़ी ठंडी पड़ गई है। कई दिग्गज कंपनियां अपनी प्रस्तावित परियोजनाओं से पीछे हटने लगी हैं।

रायटर्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ऑस्ट्रेलिया की 55 अरब डॉलर की विशाल परियोजना को रोक दिया, फोर्टेस्क्यू मेटल्स ग्रुप ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रयोग स्थगित कर दिए, और शेल जैसी ऊर्जा कंपनियां निवेश घटाने लगीं।

इसका सबसे बड़ा कारण यही बताया गया कि उत्पादन लागत अब भी बाजार के अनुकूल नहीं है। इससे न केवल 2030 के वैश्विक उत्सर्जन लक्ष्यों पर असर पड़ेगा, बल्कि ऊर्जा संक्रमण की गति भी धीमी पड़ जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा अवरोध इसकी लागत है। एक किलो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की कीमत 3.5 से छह डॉलर के बीच आती है।

ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की प्रक्रिया बेहद जटिल है। इसमें पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है, और इसके लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए। यदि यह बिजली सौर या पवन ऊर्जा स्रोतों से न मिले, तो उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। फिर प्रत्येक किलो हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए लगभग दस से तीस लीटर तक स्वच्छ जल चाहिए, जो एक नई चुनौती है। तैयार हाइड्रोजन का भंडारण और परिवहन भी आसान नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत हल्की और ज्वलनशील गैस है, जिसे ऊंचे दबाव या अत्यधिक ठंडे तापमान पर रखना पड़ता है। इन सबके बावजूद ग्रीन हाइड्रोजन का भविष्य पूरी तरह अंधकारमय नहीं है। कई देश अब भी इसे ऊर्जा-क्रांति की दिशा में पहला ठोस कदम मान रहे हैं। ग्लोबल न्यूज वायर की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक उत्पादन लागत में 60–80 फीसदी तक की कमी संभव है। यदि यह घटकर 1–2 डॉलर प्रति किलोग्राम तक पहुंचती है, तो यह जीवाश्म ईंधनों से प्रतिस्पर्धा कर सकेगी।

चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए यह अवसर भी है। देश अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का लगभग एक-चौथाई हिस्सा आयातित पेट्रोलियम उत्पादों से पूरा करता है। यदि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़े, तो इससे न केवल ऊर्जा-आयात पर निर्भरता घटेगी, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र को भी नई गति मिलेगी। इसलिए केंद्र सरकार ने 2023 में 'राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2030 तक पचास लाख टन वार्षिक उत्पादन हासिल करना और भारत को इस क्षेत्र का वैश्विक केंद्र बनाना है।

इस दिशा में देश में शुरुआती प्रयोग पहले ही शुरू हो चुके हैं। लेह में एनटीपीसी ने विश्व की सबसे ऊंचाई पर हाइड्रोजन बसें चलाकर इतिहास रचा है। दिल्ली और फरीदाबाद में हाइड्रोजन बसों का ट्रायल सफल रहा है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी हाइड्रोजन ट्रेन ने अपनी पहली परीक्षण यात्रा पूरी की है। इंडियन ऑयल और टोयोटा की 'मिराई' कार सड़कों पर उतर चुकी है। ये पहलें भले सीमित स्तर पर हों, पर ये भारत की ऊर्जा नीति में बदलाव का संकेत देती हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों ने अरबों रुपये के निवेश की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश की 35 हजार करोड़ रुपये की परियोजना देश की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन इकाई होगी, जहां पूरी प्रक्रिया सौर और पवन ऊर्जा से संचालित होगी। इसका उद्देश्य केवल घरेलू मांग पूरी करना नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए भारत को तैयार करना है।

एक ओर जहां विकसित देश निवेश घटा रहे हैं, दूसरी ओर विकासशील देश (विशेषकर भारत) इसे अवसर के रूप में देख रहे हैं। फिर भी, कुछ बुनियादी सावधानियां बरतना अनिवार्य है। जल उपयोग पर सख्त निगरानी होनी चाहिए, ताकि हाइड्रोजन उत्पादन नए पर्यावरण संकट का कारण न बने। सुरक्षा मानकों का पालन सर्वोपरि हो, क्योंकि दुर्घटना इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। साथ ही, इलेक्ट्रोलाइजर जैसे उपकरणों का स्वदेशी निर्माण बढ़ाया जाए, ताकि तकनीकी निर्भरता कम हो और लागत नियंत्रित रहे।

ग्रीन हाइड्रोजन का भविष्य केवल आर्थिक गणनाओं पर नहीं, बल्कि पर्यावरणीय विवेक और तकनीकी नवाचार पर निर्भर करता है। यह दुनिया को जीवाश्म ईंधनों से दूर ले जाने की वह संभावना है, जो समय के साथ साकार हो सकती है। यह सिर्फ एक तकनीकी या औद्योगिक विकल्प नहीं, बल्कि मानवता के स्वच्छ भविष्य की अनिवार्यता है।

न्यूज डायरी

चिकित्सा शोध के लिए दान किया शरीर

ग्रेटर नोएडा। नोएडा के सेक्टर 45 स्थित ए-टू-जेड फाउंडेशन (निराश्रित गृह) नलगारा एक 75 वर्षीय महिला रजनी देवी के निधन के उपरांत उनकी अंतिम इच्छानुसार शरीर चिकित्सा शोध कार्यों के लिए दान कर दिया है। 14 अक्तूबर को उनकी मृत्यु हो गई। फाउंडेशन के पदाधिकारियों की सहमति अनुसार ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में देहदान किया है। संवाद

चेन छिनैती करने वाले को मुठभेड़ में दबोचा

गाजियाबाद। वसुंधरा के एटीएस एडवांटेज सोसायटी निवासी इंजीनियर राजीव गुप्ता की पत्नी के गले से चेन खींचकर भागने वाले को पुलिस ने 13 अक्तूबर की देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिल्ली के शाहदरा निवासी सोनू है और उसके खिलाफ शाहदरा में लूट और स्नैचिंग के 11, इंदिरापुरम में तीन, शालीमार गार्डन में दो और साहिबाबाद में एक मुकदमा दर्ज है। ब्यूरो

कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले को पकड़ा

ग्रेटर नोएडा। कासना कोतवाली क्षेत्र में कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर स्वाट टीम की मदद से मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से मंगलवार को आरोपी सुमंत कुमार सिंह (37) को बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गुरजिन्दर बिहार एडब्ल्यूएचओ कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो

सोसाइटी का पोस्टर वॉर पहुंचा थाने, 11 पर केस

दनकौर। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-17ए में स्थित सुपरटेक अपकंट्री सोसायटी में अवैध रूप से चल रहे पीजी और हॉस्टल में प्रवेश रोकने को लेकर अपकंट्री वेलफेयर एसोसिएशन और मेंटेनेंस विभाग द्वारा दो दिन पहले पोस्टर लगाए गए थे। आरोप है कि अवैध रूप से संचालित हॉस्टल और पीजी संचालकों ने पोस्टर फाड़ दिए थे और विरोध पर गाली-गलौच की। पुलिस ने चार नामजद समेत 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। संवाद

किशोर की मौत, डॉक्टर गिरफ्तार

दादरी। जारचा कोतवाली क्षेत्र के निजी अस्पताल में किशोर की मौत हो गई थी। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने डॉक्टर ने गिरफ्तार कर लिया है। प्यावली गांव स्थित अस्पताल में 4 अक्टूबर को नंगला उदयरामपुर गांव निवासी रजत (16) को बुखार आने पर भर्ती कराया गया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अन्य अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। संवाद

गाजियाबाद में गैंगस्टर ने गोली मारकर की पत्नी की हत्या

पत्नी पर भी लगा था गैंगस्टर एक्ट, हत्या के मामले में दोनों गए थे जेल

संवाद न्यूज एजेंसी

रूबी

विकास अहलावत

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में मंगलवार सुबह गैंगस्टर विकास अहलावत ने गोली मारकर अपनी गैंगस्टर पत्नी रूबी (34) की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को डायनिंग हॉल से खींचकर रसोई में ले गया और दरवाजा लगाकर भाग गया। बताया जा रहा है कि जमानत के लिए प्रभावी पैरवी न करने से वह पत्नी से नाराज था। फिलहाल पत्नी और बच्चों को छोड़कर विदेश भागने की फिराक में था। पत्नी इसका विरोध कर रही थी।

घटना की सूचना पर नंदग्राम थाना पुलिस के साथ डीसीपी सिटी धवल जायसवाल और एसीपी नंदग्राम उपासना पांडे मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। डीसीपी सिटी ने बताया कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला विकास मंगलवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे दो माह बाद फ्लैट पर पहुंचा था। मुख्य दरवाजे की जाली उखाड़ने के बाद कुंडी खोलकर अंदर दाखिल हो गया।

विकास की बेटी नव्या (14) ने पुलिस से बताया कि पिता ने मां रूबी से पासपोर्ट और आधार कार्ड मांगे। इन्कार करने पर दोनों में विवाद होने लगा। इस पर विकास ने नव्या को दूसरे कमरे में जाने के लिए बोलकर रूबी के गले से तमंचा सटाकर गोली चला दी। खून से लथपथ रूबी डायनिंग हॉल में गिर गई। विकास उसे खींचकर रसोई में ले गया और दरवाजा लगा दिया। गोली की आवाज सुनकर बाहर आई नव्या ने पिता को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह तमंचा लेकर फ्लैट से भाग गया।

नव्या ने आसपास के लोगों से मां को गोली लगने की बात बताई। सोसायटी के लोग रूबी को संजयनगर स्थित जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नंदग्राम पुलिस ने शव का मेडिकल परीक्षण कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मां की हत्या के बाद स्कूल से लौटी बड़ी बेटी काव्या (18) ने पिता विकास अहलावत के खिलाफ नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। डीसीपी सिटी ने बताया कि हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। सीडीआर निकाली गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

रूबी ने पति के साथ रची थी हत्या की साजिश

रूबी मूल रूप से मोदीनगर के तिबड़ा की रहने वाली थी। 17 अप्रैल 2019 को रूबी के भाई दीपेंद्र उर्फ दिप्पन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कैंटीन के विवाद में तिबड़ा निवासी अक्षय सांगवान पर उसकी हत्या का आरोप था। पुलिस ने अक्षय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इलाज के लिए जमानत पर छूटकर आए अक्षय की 24 अगस्त 2020 की शाम घर में जन्मदिन मनाते समय हत्या कर दी गई थी। मृतक अक्षय के पिता जितेंद्र ने दीपेंद्र के जीजा विकास अहलावत, बहन रूबी, दोस्त सप्पू समेत आठ लोगों को नामजद किया था। इसी मामले में रूबी और विकास को जेल भेजा गया था।

जेवर : फर्जी रजिस्ट्री से जमीन हड़पने में 30 पर मुकदमा दर्ज

यमुना सिटी। जेवर में एक करोड़ से अधिक मूल्य की आवासीय जमीन को फर्जी तरीके से हड़पने का मामला सामने आया है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने 20 नामजद व 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

भाजपा जिला संयोजक रविन्द्र शर्मा, जेवर मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह उर्फ संजय रावत, प्रदीप जैन और लवकेश शर्मा का आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी खरीदी गई जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। प्रारंभिक शिकायत पर कार्रवाई न होने से उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने क्रेता, विक्रेता और गवाह समेत करीब 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे।

पीड़ित पक्ष के अनुसार, उन्होंने जेवर निवासी केला देवी से 499 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था, जिसकी सरकारी दर से कीमत 1,33,70,000 आंकी गई थी। पीड़ितों ने साढ़े छह लाख रुपये स्टांप शुल्क जमा कर 5 जुलाई को जमीन अपने नाम कराई थी। आरोप है कि मूलचंद, वीरपाल, कौशल देवी, श्रीचंद, पींटी सैनी, किरनदेई, बादामी, चमन सैनी सहित कई लोगों ने फर्जी कागजात तैयार कर जमीन को विरासत के आधार पर आगे बेच दी। संवाद

अयोध्या में खुलेगा छठा एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर : शाह

गृहमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अनुशासन एवं परिचालन उत्कृष्टता को सराहा

अमर उजाला ब्यूरो

मानेसर में हथियारों की प्रदर्शनी को देखते केंद्रीय गृहमंत्री। स्रोत : विज्ञप्ति

गुरुग्राम। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए छठा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) ट्रेनिंग सेंटर अयोध्या में खोला जाएगा। मानेसर में मंगलवार को एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की। गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं बची है।

गृहमंत्री शाह ने कहा कि इससे पहले चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद में ट्रेनिंग सेंटर खोले जा चुके हैं। ऑपरेशन अक्षरधाम, मुंबई हमला और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कमांडो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश की सुरक्षा की। उन्होंने एनएसजी की भूमिका को फोर्स ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में रेखांकित करते हुए बल की आतंकवाद रोधी, बंधक मुक्ति, विमान अपहरण रोधी और निकट सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा की।

ईपीई से 130 मीटर रोड को जोड़ेगा नया क्लोवर लीफ फ्लाईओवर

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर सड़क सीधे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) से जुड़ेगी। सिरसा के पास ईपीई पर नया क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बनाकर इसे जोड़ने की योजना है। इसके लिए ग्रेनो प्राधिकरण ने एनएचएआई को प्रस्ताव भेजा है। एनएचएआई इसकी फिजीबिलिटी को परख रहा है। क्लोवर लीफ फ्लाईओवर के बनने से चला आ रहा 130 मीटर सड़क के लिए जरूरी जमीन विवाद खत्म होगा। ब्यूरो

डीएनडी से सेक्टर-57 तक नहीं बनेगा एलिवेटेड रोड

नोएडा। डीएनडी फ्लाईवे से मास्टर प्लान रोड एक होते हुए सेक्टर-57 चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने की योजना सेक्टर-16 चौराहे पर फंस गई है। प्राधिकरण की तरफ से करवाए गए फिजिबिलिटी सर्वे में सामने आया है कि यहां एलिवेटेड रोड बनाना मुमकिन नहीं है।

सेक्टर-16 चौराहे के ऊपर से गुजरने वाला ब्लू लाइन मेट्रो कॉरिडोर और नीचे अंडरपास के कारण बीच से एलिवेटेड रोड नहीं निकल पाएगा। अब प्राधिकरण इस परियोजना के लिए दूसरे विकल्प तलाशेगा। वहीं, सर्वे रिपोर्ट आने के बाद आईआईटी रुड़की को बतौर सलाहकार चयन की प्रक्रिया भी रोक दी गई है। अब सेक्टर-3 के सामने से एलिवेटेड रोड का निर्माण करने का विकल्प बचा है।

दरअसल, डीएनडी से सेक्टर-12-22-56 के आगे सेक्टर-57 चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने की परियोजना की सुगबुगाहट कई बार हो चुकी है। योजना की लागत 600 करोड़ रुपये तक रहने का अनुमान था।

परियोजना के प्रारूप को विस्तार देते हुए एलिवेटेड रोड सीधे डीएनडी से शुरू कराने का प्रारूप तैयार करवाया गया था। शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए प्राधिकरण ने योजना बनाई थी। प्राधिकरण ने अपनी सलाहकार एजेंसी से फिजिबिलिटी सर्वे करवाया था। ब्यूरो

नोएडा एयरपोर्ट के कार्गो हब तक आसानी से पहुंचेंगे ट्रक

मालवाहक वाहनों को कार्गो हब में अलग रूट से प्रवेश दिया जाएगा

यमुना सिटी। नोएडा एयरपोर्ट के कार्गो हब तक पहुंचने के लिए ट्रकों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मालवाहक वाहनों को कार्गो हब में प्रवेश करने के लिए अलग रूट से प्रवेश दिया जाएगा जिससे यातायात भी सुगम रहेगा और वाहनों को मालवाहक वाहनों को भी आसानी रहेगी।

87 एकड़ के क्षेत्रफल में एयरपोर्ट का कार्गो हब तैयार हो रहा है। इस अत्याधुनिक कार्गो हब के माध्यम से देश-विदेश तक उत्पाद भेजे जा सकेंगे। इससे उद्यमी और किसान वैश्विक बाजार से जुड़ेंगे। कार्गो हब में सब्जियों, फल से लेकर तमाम उत्पाद आयात-निर्यात किए जा सकेंगे।

ऐसे में उत्पादों को लाने-ले जाने वाले मालवाहक वाहनों के लिए कार्गो हब में विशेष रूट से प्रवेश दिया जाएगा ताकि यातायात प्रभावित न हो। यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते से ही मालवाहक वाहन एयरपोर्ट परिसर में बने कार्गो हब तक पहुंच सकेंगे। ब्यूरो

उधार की शराब न मिली तो वाइन शॉप पर की अंधाधुंध फायरिंग

ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र के सैनी सुनपुरा गांव में उधार शराब देने को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने वाइन शॉप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।

सैनी गांव में वाइन शॉप के मैनेजर नितिन ने बताया कि रविवार रात दुकान पर सेल्समैन मोहित, प्रिंस, गोलू मौजूद थे। दुकान बंद करने के समय रात करीब 9:30 बजे स्थानीय गुड्डू नामक युवक 500 रुपये देकर 1,400 रुपये की शराब की बोतल मांगने लगा। कम पैसे में शराब देने में विवाद करने लगा। कुछ देर बाद युवक साथियों के साथ पहुंचा और दुकान के शटर पर लात मारने लगा। सेल्समैन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की ओर से मामले में दो युवकों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई। आरोप है कि सोमवार रात 8 बजे कुछ नकाबपोश बदमाश गाड़ी से दुकान पर पहुंचे और 7-8 राउंड फायरिंग की। ब्यूरो

तनिष्क ने पेश की गोल्ड एक्सचेंज पहल, 'मृगांका' कलेक्शन लांच

व्यावसायिक गतिविधि

नई दिल्ली (वि)। त्योहारी सीजन में टाटा समूह के आभूषण रिटेल ब्रांड तनिष्क ने गोल्ड एक्सचेंज पहल के साथ सोने के आदान-प्रदान का समर्थन किया है। त्योहारों पर तनिष्क ने ''''मृगांका'''' कलेक्शन पेश किया है। नवीनतम मृगांका कलेक्शन पौराणिक दुनिया और कल्पनाशील क्षेत्रों से प्रेरित कलेक्शन है। पूर्व मिस वर्ल्ड और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर जो मृगांका कलेक्शन की भावना को बखूबी साकार करती हैं। त्योहारों की खुशियां लाने के लिए पहली बार तनिष्क उपभोक्ताओं को 21 अक्तूबर, 2025 तक सभी कैरेट (9 कैरेट से कम) के सोने के एक्सचेंज पर जीरो प्रतिशत की कटौती की पेशकश कर रहा है। देश के सबसे बड़े गोल्ड एक्सचेंज अभियानों में से एक का तनिष्क नेतृत्व कर रहा है। तनिष्क ने विश्वास और अखंडता के राष्ट्रीय प्रतीक सचिन तेंदुलकर के साथ साझेदारी की है, ताकि इस आंदोलन के मूल मूल्यों का प्रतिनिधित्व किया जा सके। टाइटन कंपनी लिमिटेड के आभूषण प्रभाग के सीईओ अजय चावला ने कहा कि हर बार जब कोई परिवार लॉकर के सोने का एक ग्राम भी एक्सचेंज करता है, तो वह न केवल अपने लिए मूल्य अनलॉक करता है, बल्कि आयात को कम कर राष्ट्र के लिए भी योगदान करता है। यही सोने के आदान-प्रदान की शक्ति है। कंपनी के मुख्य डिजाइन अधिकारी रेवती कांत ने कहा कि हम 'मृगांका' पेश कर प्रसन्न हैं, जो हमारे सपनों की कल्पनाशील दुनिया का एक उत्सव है।

दिल्ली में रुपये ट्रांसफर कराने वाले फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा

गुरुग्राम। साइबर अपराध थाना पश्चिम की पुलिस ने दिल्ली के अक्षरधाम क्षेत्र में बने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दबिश देकर कॉल सेंटर से दो महिलाओं सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से आठ मोबाइल, चार सिम कार्ड और दो डायरी बरामद की हैं। जालसाज बैंक कर्मचारी बनकर व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेजकर रुपये ट्रांसफर कराते थे।

आरोपियों की पहचान दिल्ली के उत्तम नगर निवासी ज्ञानेंद्र, अमर उर्फ बंटा, दिल्ली के राजा पार्क मोहन गार्डन निवासी अमन, उत्तम नगर के सी ब्लॉक निवासी अमिता, उत्तम नगर के नन्हे पार्क निवासी यासना के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी अमिता व यासना को मामले में शामिल कर अनुसंधान किया गया। वहीं, आरोपी ज्ञानेंद्र, अमर व अमन को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी अमर उर्फ बंटा ने बताया कि उसके गारमेंट्स का बिजनेस में काफी नुकसान हो गया था। इसी दौरान अमर उर्फ बंटा की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो क्रेडिट कार्ड रिचार्ज और अन्य फ्रॉड किया करता था। ब्यूरो

लुलु मॉल में मना वेडिंग उत्सव सीजन-3, शो का आकर्षण रहीं हिमांशी खुराना

व्यावसायिक गतिविधि

लखनऊ (वि)। लुलु मॉल (लखनऊ) ने एक बार फिर वार्षिक 'लुलु वेडिंग उत्सव' के तीसरे संस्करण का 09 से 12 अक्तूबर तक आयोजन किया। इसमें वेडिंग फैशन व स्टाइल की दुनिया की शानदार झलक दिखी। हल्दी, मेहंदी, वेडिंग डे और एक बेहद खास 'व्हाइट वेडिंग' थीम भी देखने को मिली। लुलु वेडिंग उत्सव के प्रेजेंटिंग पार्टनर नीरूज के वेडिंग कलेक्शन लोगों को पसंद आए। शो का आकर्षण रहीं सेलिब्रिटीज हिमांशी खुराना, जिन्होंने "बैंड-बाजा-बारात" थीम के साथ रॉयल एंट्री ली और नीरूज के ब्राइडल लुक में रैंप पर वॉक किया। एथनिक्स बाई रेमंड, वेन ह्यूजेन और लुईस फिलिप ने क्लासिक और मॉडर्न मेल कलेक्शंस से वेडिंग थीम को स्टाइलिश टच दिया। वहीं तनेरिया और लिवास के ट्रेडिशनल ड्रेसेज ने हल्दी और मेहंदी फंक्शन के लिए खास प्रभाव छोड़ा। टसवा, मोहनलाल एंड संस, मीना बाजार, ग्रीनवेज, एस्टेल ब्रांड की फैशन ज्वेलरी, गीतांजलि सलोन इवेंट में शामिल रहे। लुलु मॉल के रीजनल मैनेजर समीर वर्मा ने हम हर साल कुछ नया और अनुभव देने की कोशिश करते हैं।

आईटीआरए के स्थापना दिवस पर सम्मेलन आज से

नई दिल्ली (वि)। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर की स्थापना दिवस पर त्रिदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'आयुर जेरियाकॉन-2025' का आयोजन 15 अक्तूबर से किया जा रहा है। गुजरात में पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान की निदेशक प्रो. तनुजा नेसरी करेंगी। देश-विदेश के आयुष और अन्य चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े लगभग 26 संस्थानों के प्रमुख और विशेषज्ञ ऑफलाइन तथा ऑनलाइन (वर्चुअल माध्यम से) जुड़ेंगे।

Lowest Gold Rate in all over Delhi
₹113500 Per 10g*
Today's B.I.S. Hallmark 91.6/22CT Gold Rate
8% Making on all items
Gold Testing Machine Available
KAPIL JEWELLERS SINCE 2010.
F-24/35-36, Sec-7 Rohini
9999889969, 9891417720

अमर उजाला

यदि आपको अमर उजाला की प्रति नियमित या समय से नहीं मिल रही है तो कृपया टोल फ्री नंबर या ई-मेल के माध्यम से हमें बताएं। हम शीघ्र ही उसे समय से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

अपना अखबार शुरू करवाने के लिए संपर्क करें
1800 121 1166
सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक
circulation@amarujala.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

72वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2024
प्रविष्टि हेतु सूचना
फ़िल्मों और सिनेमा पर लेखन
पात्रता
❖ फ़ीचर और गैर फ़ीचर फ़िल्म
केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित
फ़िल्में अंग्रेजी सब-टाइटल के साथ
❖ सिनेमा पर प्रकाशित
पुस्तकें एवं लेख/समीक्षाएँ
01/01/2024 – 31/12/2024
(दोनों दिन शामिल)
किसी भी जानकारी के लिए फोन करें – 011-26499370/86
(सुबह 09:30 – शाम 05:00 बजे तक)
विनियम की विस्तृत जानकारी और आवेदन करने के लिए कृपया www.mib.gov.in पर जाएं
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 31/10/2025 (शाम 5 बजे तक)
सभी अपेक्षित दस्तावेज़ नीचे दिए गए पते पर भेजें:
राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार सेल
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सिरी फोर्ट सभागार परिसर, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली-110049
ई-मेल : nfa.mib.gov.in | 72nfa2024@gmail.com
वेबसाइट: www.mib.gov.in
CBC 22201/11/0016/2526

उजाला हाट
उत्तम क्वालिटी की मजबूत फूल झाड़ू
SURAJ BRAND® BROOMS

झाड़ू लगाने की आदत,
हो हर इंसान को,
झुकना जहाँ जब आ गया,
मिल गया वो राम को।
सफाई है वहाँ.....
हरी राम गुलाब राय
.......की सूरज ब्राण्ड फूल झाड़ू है जहाँ
नक्कालों से सावधान
रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क "सूरज ब्राण्ड" देखकर ही झाड़ू खरीदे
For wholesale Enquiry Contact - 011-45545686

पावरग्रिड POWERGRID
पावरग्रिड युवा प्रोफेशनलों को देश के विद्युत भविष्य से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक महारत्न उपक्रम, अधिकारी प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के लिए प्रतिभाशाली युवा स्नातकों को आमंत्रित करता है।

क्रम सं.	पद का नाम	रिक्त पद
1	अधिकारी प्रशिक्षु (वित्त)	17+02*
2	अधिकारी प्रशिक्षु (कंपनी सचिव)	01*

*बैकलॉग रिक्तियां

पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या आदि के विवरण के लिए, कृपया www.powergrid.in के करियर अनुभाग में उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन देखें [Careers > Job Opportunities > Executive Positions on All India Basis > Recruitment of Officer Trainee (Finance) & Officer Trainee (CS) – 2025 विज्ञापन संख्या सीसी/05/2025 दिनांक 15.10.2025]

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और पावरग्रिड वेबसाइट पर आवेदन जमा करना होगा।

पावरग्रिड में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत	15.10.2025
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	05.11.2025

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट सं.–2, सेक्टर–29, गुरुग्राम, हरियाणा–122001
पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
सीआईएन L40101DL1989GOI038121 | www.powergrid.in
पर हमें फॉलो करें
एक महारत्न पीएसयू

दीपावली सजावट पुरस्कार समारोह एक नवम्बर को

नवज्योति, जयपुर। अन्तर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन, राजस्थान की ओर से जयपुर के बाजारों की सामूहिक लाइटिंग और सजावट के लिए व्यापारिक संगठनों, मॉल्स के प्रतिनिधियों एवं दुकानदारों को सर्वश्रेष्ठ सजावट पुरस्कार दिया जाएगा। इस वर्ष भी यह सम्मान राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे द्वारा एक नवम्बर को दिया जाएगा। राज्य प्रभारी ध्रुवदास अग्रवाल ने मंगलवार को यहां बताया कि दीपावली सजावट को देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है। अधिकांश होटल पूर्ण रूप से बुक हो चुके हैं। व्यापारिक संगठनों ने इस वर्ष पहली बार 18 से 23 अक्टूबर तक छह दिन की सजावट करने की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष एन.के.गुप्ता ने बताया कि इस बार सभी बाजारों में विशेष रौनक है। प्रदेश महामंत्री गोपाल गुप्ता एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेश कालानी ने बताया कि जयपुर को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जिसमें चार दिवारी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र (पूर्व) और बाहरी क्षेत्र (पश्चिम) शामिल हैं। तीनों क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ बाजार, प्रतिष्ठान एवं मॉल को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार देकर राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सजावट के चयन के लिए तीन संयोजक नियुक्त किए गए हैं, जो दीपावली के दौरान विभिन्न बाजारों का निरीक्षण करेंगे। इनमें सोहनलाल तांबी को चार दिवारी क्षेत्र, सुरेश कालानी को बाहरी क्षेत्र (पश्चिम), सुधीर जैन को बाहरी क्षेत्र (पूर्व) और दिनेश गुप्ता को समन्वयक सदस्य को नियुक्त किया गया है।

दीपावली पर्व पर जयपुर के एमआई रोड स्थित पांच बत्ती चौराहे पर सजावट के लिए लगाई गई छतरियां।

दीपावली पर सीएनजी स्टेशनों की सुरक्षा सख्त होगी

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने कोटा, नीमराणा और कूकस में संचालित सीएनजी स्टेशनों पर सुरक्षा मानकों की दीपावली पर सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम नागरिकों से भी आग्रह किया है कि पटाखे आदि ज्वलनशील उत्पाद चलाते समय गैस पाइपलाइन से दूरी बनाए रखने के साथ ही गैस रिसाव या इस तरह की अनहोनी घटना की स्थिति में तत्काल टोल फ्री नंबर 18001806135 पर सूचित करें। डीजीएम सीएनपी विवेक श्रीवास्तव व डीजीएम मार्केटिंग विवेक रंजन ने डीपीएनजी व सीएनजी एरिया में लिक डिटेक्शन टेस्ट कराने को कहा। कोटा डीजीएम ओएडएम सीपी चौधरी और डीजीएम प्रोजेक्ट आनन्द आर्य ने विस्तार से सुरक्षा मानकों की पालना के संबंध में तैयारियों की जानकारी दी।

दिवाली पर यातायात पुलिस और व्यापारियों की बैठक में परस्पर सहयोग पर बल

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। दीपावली त्योहार को लेकर मंगलवार को यातायात पुलिस और जयपुर व्यापार महासंघ, व्यापार मण्डलों की बैठक का आयोजित की गई। पुलिस उपायुक्त यातायात सुमित मेहरड़ा ने बताया कि बैठक में दीपावली पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इस पर उनके सुझाव मांगे गए। इस दौरान जयपुर व्यापार महासंघ, व्यापार मण्डलों के पदाधिकारियों से उनके बाजारों में आ रही यातायात सम्बन्धित समस्याओं के बारे में सुना व उपस्थित पदाधिकारियों को यातायात संचालन में अपेक्षित सहयोग के लिए कहा। बैठक में व्यापारियों ने आश्वासन दिया कि वे बाजारों को अतिक्रमण

से मुक्त रखेंगे, खुद के वाहनों को रामनिवास बाग पार्किंग में पार्क करेंगे एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष हर बाजार में पांच-पांच व्यक्ति यातायात व्यवस्था में सहयोग के लिए उपलब्ध कराएंगे। बैठक में जयपुर व्यापार महासंघ, बगरू वालों का रास्ता, मनिहारों का रास्ता, गणगौरी बाजार, पानीपेच बाजार, लालकोठी, जौहरी बाजार, चांदी की टकसाल, न्यू सांगानेर रोड सोडाला, विद्याधर नगर, इन्दिरा बाजार, संजय बाजार, बापू बाजार, खजाने वालों का रास्ता, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, घी वालों का रास्ता, रेडियो मार्केट, सीकर रोड, टोंक रोड, सिन्धी कैम्प, सांगानेर, झोटवाडा, राजापार्क, वैशाली नगर, रानी बाजार, कालवाड रोड व्यापार मण्डल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

भ्रष्टाचार प्रकरण की न्यायिक जांच में मुनेश गुर्जर पाई गई दोषी

हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्थान सरकार द्वारा करवाई गई न्यायिक जांच

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। भ्रष्टाचार के जुड़े मामले की न्यायिक जांच में नगर निगम हेरिटेज की तत्कालीन महापौर मुनेश गुर्जर पर आरोप साबित हुए है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार द्वारा न्यायिक जांच करवाई गई है। इस जांच में दोषी वह पाई गई।

मुनेश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के तीन आरोप लगाए गए थे जो कि जांच में बिल्कुल सत्य पाए गए। जांच के दौरान मुनेश गुर्जर स्वयं अपने वकील के साथ पेश हुई थीं। राज्य सरकार की ओर से विभागीय अधिवक्ता विष्णु दयाल शर्मा ने पैरवी की। मुनेश गुर्जर पट्टों की एवज में साइन के बदले पैसों में लिप्त होने सहित पट्टों में बिना पैसे साइन नहीं करने के आरोप में दोषी पाई गई है। मुनेश गुर्जर के निवास से 41 लाख रुपए की रकम बरामद हुई थी, जिसका मुनेश गुर्जर जवाब देने में पूरी तरह असमर्थ रही। दोनों दलाल अनिल दुबे एवं नारायण सिंह भी प्रकरण में लिप्त पाए गए हैं।

कांग्रेस के दिग्गज नेता आज अंता में जुटेंगे

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। अंता विधानसभा उपचुनाव में बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के नामांकन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी दिग्गज शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट सहित कई वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद और पदाधिकारी नामांकन रैली में शामिल होंगे। रैली से पहले रंधावा सर्किट हाउस में वरिष्ठ नेताओं के साथ रायशुमारी करेंगे। सभी नेताओं से उपचुनाव जीत की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया भी नामांकन रैली में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस भी भाया की स्थानीय स्तर पर पकड़, पूर्व में चुनाव लड़ने के अनुभव और कांग्रेस के जातिगत व सामाजिक समीकरणों के आधार पर जीत हासिल करने पर काम कर रही है। दिग्गज नेताओं ने अपने समर्थकों को स्थानीय मुद्दों जैसे पानी की कमी, किसान कर्जमाफी, महिलाओं के लिए योजनाएं और महिला अपराध जैसे मुद्दों पर मुखर होने के निर्देश दिए हैं।

लोकरंग महोत्सव: लंगा गायन में गूंजे थार के स्वर

नवज्योति, जयपुर। जेकेके में चल रहे 28वें लोकरंग महोत्सव के आठवें दिन मंगलवार को देश के विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकारों ने अपनी सजीव प्रस्तुतियों से भारत की लोक परंपराओं की अनूठी झलक पेश की। कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के भंवरू खां लंगा व समूह के सुरमयी गायन से हुई। सिंधी सारंगी, खड़ताल, मोरचंग और अलगोजा की धुनों पर हो भला रे, जियो भला रे... गीत ने वातावरण को सूफियाना बना दिया। सुंदर गोरी गीत ने मंच पर रुमानियत का माहौल रच दिया। हरियाणा से आए कलाकारों ने ननदी के बीरा... गीत पर पारंपरिक घूमर नृत्य प्रस्तुत कर हरियाणवी संस्कृति की झलक दी। डीग, राजस्थान के कलाकारों ने श्री राधा रमण जी के जन्मोत्सव पर किया जाने वाला चरकुला नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें 108 दीपों से सजे चरकुला और राधा-कृष्ण की महाआरती ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। अमित गमेती व समूह ने गवरी नृत्य के माध्यम से पौराणिक कथाओं और देव-लोक परंपराओं को मंच पर जीवंत किया। मध्यप्रदेश के कलाकारों ने गणगौर और करमा नृत्य के जरिए पारंपरिक लोक श्रद्धा और फसल उत्सव का उल्लास बिखेरा। तमिलनाडु से आए कलाकारों ने मरुद्धम कलाई कजुहू में देवी दुर्गा और काली माता की आराधना पर आधारित आदिवासी नृत्य शैली प्रस्तुत की, जबकि महेश्वरन थपट्टा कलाई नृत्य ने अंतिम प्रस्तुति के रूप में दक्षिण भारत की ऊर्जा से दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

डीओआईटी के पूर्व संयुक्त निदेशक के खिलाफ प्रसंज्ञान आदेश रद्द करने से इनकार

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने योजना भवन के बेसमेंट की अलमारी में मिली दो करोड़ रुपए से अधिक नकदी और एक किलोग्राम सोने से जुड़े ईडी के मामले में डीओआईटी के तत्कालीन संयुक्त निदेशक आरोपी वेद प्रकाश यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अलमारी में राशि और सोना रखते समय अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा था। ऐसे में अभियोजन स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं थी। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश वेद प्रकाश यादव की याचिका को खारिज करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि ईडी मामलों की विशेष अदालत ने उसके खिलाफप्रसंज्ञान लेते समय इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि मामले में अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई है। जबकि राज्य सरकार कर्मचारी के खिलाफ बिना अभियोजन स्वीकृति लिए अभियोजन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसे में ईडी कोर्ट के 21 मार्च, 2024 के प्रसंज्ञान आदेश को रद्द किया जाए। जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने कहा कि डीओआईटी कार्यालय की अलमारी में भारी मात्रा में नकदी और सोने की ईंट रखने का कृत्य आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया गया कार्य नहीं है। ऐसे में इसके लिए अभियोजन स्वीकृति की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि 19 मई, 2023 को योजना भवन के बेसमेंट में रखी अलमारी से 2.31 करोड़ रुपए की नकदी और एक किलोग्राम सोना बरामद हुआ था। प्रारंभिक जांच के बाद डीओआईटी के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद ईडी ने अलग से प्रकरण दर्ज कर वेद प्रकाश को गिरफ्तार किया था।

पूर्ण पारदर्शिता के साथ किसानों को खाद का वितरण: कलक्टर

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि किसानों को रबी के मौसम में फसल बुबाई के लिए डीएपी और उर्वरकों का पूर्ण पारदर्शिता के साथ वितरण किया जा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में रबी के मौसम में जयपुर जिले की डीएपी एवं उर्वरक की उपलब्धता के संबंध में मंगलवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलक्टर डॉ. सोनी ने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूर्ण सवेंदनशीलता एवं किसानों को डीएपी/उर्वरकों का वितरण कर रही है। उन्होंने उर्वरक आपूर्ति संस्थाओं को अधिकाधिक डीएपी आपूर्ति किसानों को जारी करने के निर्देश दिए। डॉ. सोनी ने जिला प्रशासन, सहकारिता एवं कृषि विभाग को संयुक्त रूप से अपनी निगरानी में डीएपी तथा उर्वरकों का सुचारू रूप से पूर्ण पारदर्षिता के साथ वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (उत्तर) मुकेश कुमार मूण्ड को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। बैठक में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक केसी मीणा ने बताया कि माह अक्टूबर में यूरिया की मांग 9 हजार मैट्रिक टन यूरिया के विरूद्ध 12 हजार 241 मैट्रिक टन उपलब्ध है। डीएपी 6 हजार मैट्रिक टन की मांग के विरूद्ध 7 हजार 49 मैट्रिक टन उपलब्ध है।

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए मीडिया पर विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन की अनिवार्यता

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव तथा 6 राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के आठ विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस क्रम में आयोग ने 9 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। प्रत्येक पंजीकृत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और प्रत्येक उम्मीदवार को सोशल मीडिया सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले संबंधित मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) से अनिवार्य रूप से पूर्व प्रमाणन प्राप्त करना होगा।

रेल मंत्री कल आएंगे जयपुर, 100 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण

नवज्योति, जयपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 16 अक्टूबर को जयपुर दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों-जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर के 65 स्टेशनों पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। रेल मंत्री अपने एक दिवसीय दौरे में खातीपुरा स्टेशन से जयपुर-असारवा ट्रेन में नई सुविधा की शुरुआत करेंगे। इसके तहत एसी कोच यात्रियों को बेडरोल अब पैक कवर में दिया जाएगा। यह पहल उत्तर पश्चिम रेलवे में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जा रही है, जिससे गंदे या बिना धुले बेडरोल मिलने की शिकायतें समाप्त होंगी।

ये सभी छोटे स्टेशन हैं जिन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन यात्रियों की जरूरत को देखते हुए यहां सुधार व विकास कार्य कराए गए हैं। इन कार्यों में प्लेटफॉर्म सुधार, शेड, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जैसी सुविधाएं शामिल हैं। विकास कार्यों में जयपुर मंडल के 11, जोधपुर मंडल के 20, अजमेर मंडल के 3 और बीकानेर मंडल के 31 स्टेशन शामिल हैं। प्रमुख स्टेशनों में खातीपुरा, चाकसू, सांदरी, नावां सिटी, रानीवाड़ा, श्रीडूंगरगढ़, पीलीबंगा, नपासर, गजसिंहपुर, सादुलशहर और सरूपसर जैसे स्टेशन शामिल हैं।

नए आपराधिक कानूनों की जीवंत झलक

जेईसीसी में 10 स्टेज में दिखी कानून की सरल और तेज प्रक्रिया

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को लेकर आयोजित प्रदर्शनी आमजन के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गई है। यह प्रदर्शनी 13 अक्टूबर से शुरू हुई है और दीपावली तक चलेगी। यहां अपराध की सूचना मिलने से लेकर न्यायालय के अंतिम निर्णय तक की प्रक्रिया को 10 चरणों में लाइव मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में डायल 112 पर कॉल रिसीविंग, ई-एफआईआर, फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह, मेडिकल जांच, अभियोजन, समयबद्ध ट्रायल, जेल सुधार और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा तक की झांकी दी गई है। एडीजी एस सेंगथिर और आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य नए कानूनों को आमजन तक सरल, तकनीकी और प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। नागरिकों को अब पारदर्शी जांच, वैज्ञानिक साक्ष्य और समयबद्ध न्याय प्रक्रिया की जानकारी मिल रही है, जिससे न्याय व्यवस्था में विश्वास और जागरूकता दोनों बढ़े हैं।

गॉसिप गलियारा

रेडी, स्टीडी, फायर-मिर्ची लगने वाली है...

अनटाइटल्ड-अपकमिंग बॉबी-देओल की फिल्म जिनका विलेन-लुक वायरल है। उस मूवी से अब एक्ट्रेस श्रीलीला का पोस्टर भी सामने आया है। जिसे खुद पुष्पा-2 की किसिक-गर्ल श्रीलीला ने शेयर कर संकेत दे दिया है कि उनका रोल जबरदस्त होने वाला है।

केजीएफ-3 का फाइनल-ड्राफ्ट

केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इंस्टाग्राम पर केजीएफ-3 की स्क्रिप्ट की झलक दिखाई है, जो थोड़ी जली नजर आ रही है। उन्होंने लिखा फाइनल ड्राफ्ट। इससे साफ जाहिर होता है कि ये केजीएफ फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होगी।

अमिताभ पर भी चढ़ा लबूबू-डॉल का खुमार

सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इंटरनेट पर छाए रहते हैं और जो उनके मन में होता है, उसे देर रात भी फैंस के साथ शेयर करते हैं। बीते दिनों लबूबू-डॉल का काफी ट्रेंड चला था।

फिल्म पहेली-601

सलमान खान और रणबीर कपूर ने किस फिल्म में साथ काम किया है।

इस फिल्म पहेली का जवाब हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। 7849914249

फिल्मी पहेली क्रमांक-600 का उत्तर

रश्मिका मंदाना ने फिल्म मिशन मजनू से बॉलीवुड में डेब्यू किया था।

यार ने ही लूट लिया घर यार का: ज्वेलरी लूट का मास्टरमाईंड निकला पीड़ित का दोस्त, 7 गिरफ्तार

नवज्योति,जयपुर। हरमाड़ा थाना पुलिस ने मंगलवार को लूट के सात आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से करीब 35 लाख रुपए की लूटी गई ज्वेलरी बरामद की है। आरोपियों ने इलाके में 11 अक्टूबर को एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास गणेश नगर में हुई दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित की रिपोर्ट के अनुसार पांच बॉक्स में रखी ज्वेलरी की कीमत पुलिस ने 35 लाख रुपए बताई है, पुलिस ने स्कूटी समेत पूरा माल बरामद कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि इस लूट की साजिश पीड़ित के पुराने परिचित ने ही रची थी। पुलिस उपायुक्त पश्चिम हनुमान प्रसाद ने बताया कि आरोपी अमित जांगिड़ उर्फ बिट्टू (38) मुरलीपुरा, जयवर्धन सिंह जोधा उर्फजेपी (24), सरदारपुरा, हरमाड़ा, लक्ष्य वर्मा (18), खोराबिसल, जयपुर, अजय यादव उर्फ अज्जू (18), शाहपुराए , अध्ययन राजावत उर्फमोनू (19), करधनी, जयपुर, नवीन शर्मा (20), करधनी, और देवराज सिंह (19) विद्याधर नगर को गिरफ्तार किया है ।

यह था मामला

पुलिस के अनुसार 11 अक्टूबर को परिवादी प्रीतेश वर्मा ने हरमाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि तीन लोगों ने चाकू की नोक पर उनके पास रखा 35 लाख रुपए की पांच सोने के ज्वेलरी सेट से भरा बैग छीन लिया। पुलिस आरोपियों के कब्जे से लूट में प्रयुक्त स्कूटी और ज्वैलरी बरामद की गई।

दोस्त ने रचा सारा चक्रव्यूह, मलबे में छुपाया लाखों का आभूषण

डीसीपी हनुमान ने कहा कि मुख्य आरोपी अमित जांगिड़ उर्फबिट्टू है, जो परिवादी प्रीतेश वर्मा का करीब पांच साल पुराना दोस्त है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूट का चक्रव्यूह रचा।

भगवान महावीर स्वामी का निर्वाणोत्सव 21 को

नवज्योति, जयपुर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2552वां निर्वाणोत्सव 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर भट्टारक जी की नसियां में राजस्थान जैन सभा जयपुर की ओर से तथा शहर के दिगम्बर जैन मंदिरों में विशेष आयोजन होंगे। राजस्थान जैन सभा जयपुर के अध्यक्ष सुभाष चन्द जैन ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम नारायण सिंह सर्किल स्थित भट्टारक जी की नसियां में होगा। प्रातः 8.15 बजे से भगवान महावीर की संगीतमय पूजा-अर्चना के बाद प्रातः 9.15 बजे मंत्रोच्चार के साथ निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त शहर के 250 से अधिक दिगम्बर जैन मंदिरों में पूजा अर्चना होगी।

दिगंबर जैन महासमिति पश्चिम संभाग का हुआ अभिनंदन समारोह

नवज्योति, जयपुर। दिगंबर जैन महासमिति पश्चिम संभाग की ओर से महासमिति के स्वर्णिम वर्ष एवं स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के एक निजी होटल में अभिनंदन समारोह एवं स्वास्थ्य परिचर्चा हुई। समारोह में राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र कुमार पांड्या, जस्टिस एन.के.जैन, डॉ.राजेंद्र जैन, राजेश बड़जात्या, सुनील बज सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष निर्मल कुमार संघी के नेतृत्व में कार्यक्रम का संचालन हुआ। इस अवसर पर पश्चिम संभाग की 18 इकाइयों के अध्यक्षों व मंत्रियों को सम्मान पत्र, माला, दुपट्टा व साफा पहनाकर सम्मानित किया।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की पत्नी की तबीयत में सुधार

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की पत्नी की तबीयत में अब सुधार है। चिकित्सकों के अनुसार संभवतया बुधवार को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि चक्कर आने की समस्या के चलते एहतियातन मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन अब उनकी तबीयत में सुधार है और सभी जरूरी जांचें कर ली गई है। वहीं मंगलवार को भी अस्पताल में कुशलक्षेम पूछने वालों का तांता लगा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह कई बीजेपी नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर कुशलक्षेम जानी।

श्री नहर के गणेशजी महाराज का मंगल पुष्य पर किया दूर्वा मार्जन से पंचामृत अभिषेक

नवज्योति, जयपुर। ब्रह्मपुरी माऊण्ट रोड स्थित अतिप्राचीन दाहिनीं सूंड़ दक्षिणमुखी श्री नहर के गणेशजी महाराज के मंदिर में प्रथम पूज्य गणपतिजी महाराज का मंदिर परिवार ने मंगलवार को दूर्वा मार्जन से पंचामृत अभिषेक किया। मंदिर युवाचार्य पं.मानव शर्मा ने बताया कि दीपावली से पूर्व में पुष्य नक्षत्र होने से प्रातः शुभ मुहूर्त में मंदिर महंत पं.जय शर्मा के सान्निध्य में प्रभु गजानंद जी का मंदिर परिवार द्वारा दूर्वा मार्जन से पंचामृत अभिषेक किया गया।

दुबई की फ्लाइट लेट

नवज्योति,जयपुर। जयपुर से दुबई जाने वाली फ्लाइट मंगलवार को देरी से संचालित हुई। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्पाइसजेट की फ्लाइट जयपुर से सुबह 9.30 बजे दुबई जाती है। मंगलवार को यह फ्लाइट दोपहर 3.15 बजे रवाना हुई। इस दौरान यात्री एयरपोर्ट पर ही परेशान होते रहे। यह फ्लाइट 28 सितंबर से लगातार देरी से संचालित हो रही है।

दो न्यायाधीशों का तबादला, एक की वापसी

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों का तबादला किया गया है। एक न्यायाधीश को वापस राजस्थान हाईकोर्ट भेजा गया है। केंद्र सरकार ने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता और अवनीश झिंगन का दिल्ली हाईकोर्ट तबादला किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत जस्टिस अरुण मोंगा का तबादला कर राजस्थान हाईकोर्ट भेजा गया है। जस्टिस मोंगा का गत जुलाई माह में राजस्थान हाईकोर्ट से दिल्ली तबादला किया गया था।

अंता में दूसरे दिन दो नामांकन भरे

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। बारां जिले की अंता विधानसभा में उपचुनाव के लिए मंगलवार को दूसरे दिन दो अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए। जिला निर्वाचन अनुभाग के अनुसार धर्मवीर ने निर्दलीय और नरेश कुमार मीणा ने निर्दलीय नामांकन रिटर्निंग अफसर अंता को पेश किया।

जैसलमेर बस घटना पर कांग्रेस नेताओं ने दुख जताया

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगने की घटना में कई लोगों की मरने की खबर पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने दुख जताया है। इन नेताओं ने घटना को चिंताजनक बताते हुए हादसे में मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

पीजी की चौथी मंजिल से गिरे छात्र की मौत

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। शिप्रापथ थाना इलाके में स्थित रिद्धि-सिद्धि चौराहा इलाके में सोमवार रात करीब साढ़े बारह बजे 17 वर्षीय छात्र शुभम की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। करीब तीन बजे इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुभम को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शुभम बीते छह महीने से जयपुर में एक निजी संस्थान से आईआईटी की तैयारी कर रहा था। परिजनों को सुबह 3 बजे पीजी से कॉल आया कि शुभम नीचे गिर गए हैं। झोटवाड़ा निवासी मामा जय सिंह ने आरोप लगाया कि पीजी की चौथी मंजिल की बालकनी में सुरक्षा जाली नहीं लगी थी। सीसीटीवी में शुभम के गिरने से पहले और बाद की फुटेज मिली लेकिन गिरने की स्पष्ट स्थिति रिकॉर्ड नहीं हो पाई। शिप्रापथ थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सक्षम जयपुर अभियान के तहत आमेर के खोरा मीणा में हुआ नारी चौपाल

जयपुर। सक्षम जयपुर अभियान एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिले के प्रत्येक उपखंड पर नारी चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत मंगलवार को आमेर के खोरा मीणा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में नारी चौपाल कार्यक्रम उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हजारों महिलाओं एवं बालिकाओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। मारवाड़ी गीत, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक, आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसी विविध गतिविधियों की जानकारी दी गई।

संपादकीय

हमसे जुड़ने के लिए QR Code स्कैन करें

दैनिक नवज्योति
आपके लिए, आपके साथ
dainiknavajyoti.com
जयपुर, बुधवार, 15 अक्टूबर, 2025

90 YEARS since 1936 विश्वसनीयता के dainiknavajyoti.com

पुलिसकर्मियों की आत्महत्याओं से उपजे सवाल

हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई.पूरन कुमार के आत्महत्या प्रकरण की सुर्खियां अभी सूखी भी नहीं थी कि कुमार के खिलाफ एक मामले की जांच कर रहे उपनिरीक्षक संदीप कुमार ने भी आत्महत्या कर ली है। इस घटना के बाद मामले की गुत्थी और उलझ गई है। देश की राजनीति अलग गरमा रही है। संदीप कुमार ने आत्महत्या से पूर्व एक तीन पृष्ठों का नोट लिख छोड़ा है जिसमें कुमार के खिलाफ जांच का हवाला दिया गया है। दूसरी ओर आईपीएस अधिकारी कुमार की ओर से लिखे गए आठ पृष्ठों वाले पत्र में जिन 13 वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाए गए थे, अब उनकी जांच शुरू हो गई है। मामले की जांच के लिए उनका लेपटॉप लिया गया है। राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। तो रोहतक पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया को पद से हटा दिया गया। उनकी जगह सुरिंदर भोरियो को कार्यभार सौंपा गया है। बिजारनिया को फिलहाल कोई पद नहीं दिया गया है। यह प्रशासनिक कदम दिवंगत पुलिस अधिकारी की पत्नी आईएएस अधिकारी श्रीमती अमनीत पूरन कुमार द्वारा पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज करने के बाद उठाया गया है। आज कुमार के परिजनों से विपक्ष के नेता राहुल गांधी, इससे पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मिलेंगे। लेकिन इस प्रकरण के जरिए यह तथ्य सामने आ रहे हैं कि वर्तमान दौर में हमारे प्रशासनिक तंत्र से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को किस तरह मानसिक, प्रशासनिक यातनाओं के दौर से गुजरना पड़ता है।

जाति आधारित भेदभाव, सार्वजनिक अपमान जैसे लक्षित उत्पीड़न और अत्याचारों से अलग जूझना पड़ता है। ऐसे में पूरे प्रशासनिक तंत्र को अब अपनी कार्यशैली में सुधार के लिए आत्मचिंतन और निरीक्षण करने की जरूरत है। इन दो आत्महत्याओं की घटना ने पुलिस सेवा के भीतर कार्यप्रणाली व्याप्त मानसिक दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप और संस्थागत असंतुलन से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना कानून व्यवस्था के रक्षक माने जाने वाले अधिकारियों के मनोवैज्ञानिक हालात पर एक बार फिर रोशनी डालती है। हाल के वर्षों में पुलिस विभाग पर राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है। अधिकारियों को नीतिगत फैसलों से अधिक राजनीतिक इच्छाओं के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इससे उनके आत्मसम्मान और पेशेवर स्वतंत्रता को ठेस पहुंचती है। कई बार ईमानदार अधिकारियों को तबादलों और अनुचित आदेशों का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। लगातार ड्यूटी, तनावपूर्ण माहौल और सामाजिक अपेक्षाओं का दबाव अधिकारियों को निजी रूप से प्रभावित करता है। भारतीय पुलिस व्यवस्था में मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम लगभग न के बराबर है। अधिकारी किसी मनोवैज्ञानिक परामर्श या काउंसलिंग की सुविधा नहीं लेते जिससे तनाव अंदर की अंदर बढ़ता जाता है। यह दोनों घटनाएं बताती है कि देश की पुलिस व्यवस्था को केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी सुधारने की आवश्यकता है। दोनों आत्महत्या प्रकरणों की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है।

मचाडो को शांति नोबेल मानवता की जीत का प्रतीक

मचाडो को नोबेल दिया जाना स्वागत योग्य

सामयिक

मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की एक प्रमुख राजनीतिक नेता, इंजीनियर और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्हें लोकतंत्र की लौ जलाए रखने वाली महिला और विरोधी एकजुटकर्ता कहा गया है। उन्होंने वर्षों से अपने देश में तानाशाही शासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया है।

हाल ही में वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार 58 वर्षीय मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की एक प्रमुख राजनीतिक नेता, इंजीनियर और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्हें लोकतंत्र की लौ जलाए रखने वाली महिला और विरोधी एकजुटकर्ता कहा गया है। उन्होंने वर्षों से अपने देश में तानाशाही शासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया है। वेनेजुएला में लोकतंत्र, मानवाधिकार और शांति की स्थापना के लिए अहिंसक संघर्ष के लिए, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। मचाडो को नोबेल दिया जाना वास्तव में बहुत ही सुखद व स्वागत योग्य है। वेनेजुएला में एक लंबे समय से तानाशाही शासन था, मचाडो ने इस तानाशाही शासन के विरोध में लोकतंत्र बहाली का अभियान चलाया। दरअसल, उन्होंने महिलाओं और युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं उन्होंने मानवाधिकार हनन, मीडिया दमन और चुनावी धांधली के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार अपनी आवाज उठाई।

अहिंसा और जनशक्ति

कई बार गिरफ्तार और धमकाया गया, लेकिन उन्होंने अहिंसा और जनशक्ति के बल पर अपने संघर्ष को जारी रखा। उन्हें राजनीतिक उत्पीड़न तक का सामना करना पड़ा, तथा उन्हें संसद से बरखास्त किया गया और उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। नोबेल समिति ने उनके बारे में यह बात कही है कि मारिया कोरिना मचाडो ने साहस, नैतिक दृढ़ता और अहिंसक संघर्ष के माध्यम से वेनेजुएला में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की लौ जलाए रखी। बहरहाल, यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि यह पुरस्कार लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों के लिए एक प्रेरणा है। मचाडो ने यह दिखाया कि शांति और परिवर्तन के लिए हिंसा नहीं, बल्कि साहस और सत्य की आवश्यकता होती है। मचाडो सदैव शांति और लोकतंत्र के पक्ष में समर्पित रहीं हैं। यदि हम यहां पर उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें, तो मारिया कोरिना मचाडो का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को वेनेजुएला में हुआ था।

स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता

जिस दौर में अधिकतर सत्ताधारी नेता तानाशाही करने लगे हैं, उस दौर में मारिया जैसे कुछ स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता भी हैं, जो लोकतंत्र का झंडा बुलंद किए हुए हैं। मचाडो को नोबेल पुरस्कार दिए जाने से दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों को निश्चित ही बल मिलेगा, क्यों कि उन्होंने अपनी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से लड़ी। उनको पुरस्कार दिए जाने से विशेष रूप से अमन-चैन के पक्ष में महिलाओं का मनोबल भी कहीं न कहीं बढ़ेगा। मचाडो ने इस पुरस्कार को वेनेजुएला के लोगों की स्वतंत्रता की लड़ाई और बलिदान की मान्यता बताया है, जिन्होंने तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने कठिन समय में उनके संघर्ष का समर्थन किया और लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना समर्थन दिया। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने 10 अक्टूबर, जब नोबेल सम्मान की खबर सुनी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पूरा श्रेय स्वयं न लेते हुए कहा कि यह नोबेल शांति पुरस्कार पूरे आंदोलन और समाज की जीत है।

विपक्ष की प्रमुख नेता

मचाडो ने एंड्रेस बेलो कैथोलिक यूनिवर्सिटी से औद्योगिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में वित्त विषय में स्नातकोत्तर किया। उनके राजनीतिक जीवन और संघर्ष की बात करें तो वे वेनेजुएला में लोकतंत्र सपोर्टर और विपक्ष की प्रमुख नेता हैं। उन्होंने 2002 में सुमाते नामक नागरिक समूह की सह-स्थापना की, जो चुनाव की निगरानी और मताधिकार की रक्षा करने के लिए काम करती थी। 2013 में उन्होंने वेंटे वेनेजुएला नामक राजनीतिक दल की स्थापना की और इसका नेशनल समन्वयक बनीं। 2011-2015 के बीच वह वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की सदस्य भी थीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2023 की विपक्षी प्राथमिक चुनावों में उन्होंने स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनने से रोका गया। जब उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया, उन्होंने एडमंडो गोंजालेज उरुतिया का समर्थन किया, जो बाद में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मचाडो को आयरन लेडी की उपाधि दी गई है।

लोकतंत्र का सम्मान

यह बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में सवा तीन सौ से अधिक लोग और संगठन शांति प्रयासों में लगे हैं, और उनके प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व शांति की दिशा में अच्छे प्रयास किए हैं और उन्हें यह चाहिए कि वे इस दिशा में और तेजी तथा ईमानदारी लाएं। विशेषकर उन्हें यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे आतंकी पोषक देश की निगाह में शांति दूत होना वास्तव में खुद को धोखा देने के समान है। बहरहाल, वेनेजुएला जैसे देश में जहां तानाशाही ताकतें लोकतंत्र को उभरने का कोई मौका नहीं देना चाहतीं, वहां मचाडो जैसी विपक्ष को एकजुट करने वाली शख्सियत को शांति पुरस्कार के लिए चुनना निस्संदेह स्त्री के संकल्प, सत्य और लोकतंत्र का सम्मान है। मचाडो को शांति नोबेल मानवता की जीत का प्रतीक है। यह संवाद, सद्भाव और सहयोग की नई दिशा दिखाती है। वास्तव में, उनकी जीत विश्व में अहिंसा और सह-अस्तित्व के मूल्यों की पुनर्स्थापना है।

-सुनील कुमार महला
यह लेखक के अपने विचार हैं।

जीवन बोध

संसार की माया

संसार की माया संसार का वही रुतबा है, लेकिन भक्त इस संसार से कहीं ऊंचे हो जाते हैं। इस कारण इन सभी सिलसिलों को तुच्छ मानते है। सूरज चढ़ आता है तो दीपक की क्या औकात रह जाती है। अन्धकार में तो दीपक हमें विशेष नजर आता है। लेकिन कड़कती धूप में आप बाहर दीपक को रख दें तो नजर भी नहीं आएगा, कि जल भी रहा है या नहीं। जिस माया धन-दौलत, संसार का हम जिक्र करते हैं ऐसा नहीं कि उसकी कोई विशेषता नहीं है। उसकी विशेषता जरूर है। इसीलिए तो इंसान इस तरफ अग्रसर होता है। लेकिन इस राब के होते हुए जैसे ऊंची-ऊंची इमारतों की अक्सर मिसाल देते हैं, लेकिन इमारत ऊंची है, उसकी जितनी ऊचाई है उतनी ही है। जिस तरह से संसार का सिलसिला है, उसका वैसे ही है। लेकिन इतनी ऊंची इमारत, देखने के लिए जब प्रयास करता है, इन्सान तो गर्दन टेढ़ी होती है, लेकिन पास वाले एयरपोर्ट पर जा कर हवाई जहाज पर चढ़ जाएं। वहां से जब वो हवाई जहाज उड़ता है और ऊंची इमारतों पर से गुजरता है, तो वहां से इन्सान को यह ऊंचे-ऊचे खिलौने दिखते हैं।

- निरंकारी बाबा

जल तरंग

ज्ञानवादियों के राजा का दर्द

ज्ञान की राजधानी में बैठकर एक दिन ज्ञानवादियों के राजा ने ज्ञान के सभी अधिष्ठाताओं की एक बैठक बुलाई। जब सभी अधिष्ठाता अपने निर्धारित आसन पर बैठ गए, तो ज्ञानवादियों के राजा ने उन सभी के चेहरों की तरफ गौर से देखकर कहा- देश में अज्ञान बढ़ता जा रहा है। अविद्या और अध्यास के कारण लोग नास्तिक हो रहे हैं। गत ग्यारह वर्षों से हम लोग देश में ज्ञान का दीपक जला रहे है। देश को विश्वगुरू का दर्जा दिलाने का भरसक प्रयत्न कर रहे है। रामराज्य लाने की कथा सुना रहे है। जनकल्याणकारी योजनाओं की गंगा बहा रहे है फिर भी लोग न जानें क्यों बगावत करने पर तुले हुए है? लोगों के बगावती तेवर को देखकर ऊपर बैठे आकाश में ज्ञान के देवता भी हमारे से नाराज हो रहे है। सुना है देवी मिनर्वा भी इन दिनों हम पर कुपित है। सब कुछ ठीक चलते हुए भी अकस्मात् उल्टा-पुल्टा हो रहा है। लोग शासन के विरोध में धरना-प्रदर्शन कर रहे है, चोरी का आरोप लगा रहे है, युवाओं को भड़का रहे है। जगह-जगह जेन-जी और जेन जेड जैसे तबके खड़े हो गए है। धर्म की ग्लानि हो रही और अधर्म की वृद्धि हो रही है। आखिर तुम लोग वातानुकूल कमरों में बैठे किस अवतार का इंतजार कर रहे हो? यदि ऐसा है तो यह तुम्हारी भंयकर भूल होगी। अवतार के प्रकट होने पर तुम लोगों को सचिवालय में बैठने की सुविधा भी नहीं मिलेगी। तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली जाएगी। आज चहुंओर तुम्हारे नाम की जो जय-जय कार हो रही है ना। कल यदि अवतार का प्राकट्य होता है, तो उनके लिए तुम्हें जय जयकार करनी ही पड़ेगी। ज्ञानवादियों के राजा की बात सुनकर ज्ञान के एक वरिष्ठ अधिष्ठाता बोला- महाभाग, मैंने शास्त्र पढेहैं अभी अवतार होने में थोड़ी देर बाकी है, किंतु यह बात सत्य है कि इस समय देश के भीतर और बाहर के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। देश के बाहर डोनाल्ड ट्रंप डंक लगा रहा है और भीतर उपद्रवी लोग नाहक ही सिर उठा रहे हैं। ऊपर आसमान से कोई उतरे न उतरे देश के हालात ऐसे ही रहे, तो देश के भीतर से कोई भीमकाय नास्तिक अवश्य जाग जाएगा। ज्ञान के अधिष्ठाता की बात सुनकर ज्ञानवादियों का राजा बोला- ज्ञान के वरिष्ठ अधिष्ठाता के साथ-साथ तुम कूटनीति के कुलभूषण हो, जोड़-तोड़ विद्या के कुलवीर भी तो अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? वह बोला- अपनी शक्तियों को पुनः जागृत करना ही होगा। नास्तिकों की नाक में नकेल डालने के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई इत्यादि केंद्रीय जांच एजेंसियों को अधिक क्रियाशील करने की जरूरत है साथ ही प्रांतीय शासन पर शिकंजा कसने के लिए एक-दो और बुलडोजर बाबा की आवश्यकता है। किसी बड़े प्रांत में उन जैसे किसी बाबा को पदासीन करना होगा।

-डॉ. मनमोहनसिंह यादव
यह लेखक के अपने विचार हैं।

आज का विचार

अपनी वसीयत में लिखें कि मरणोंपरांत आपके नेत्रदान अवश्य करें। मिट्टी को मिट्टी में मिलाने से पहले, यदि हम नेत्रदान कर देंगे तो मरकर भी दुनिया को उजाला देते रहेंगे।

-श्री चंद्रप्रभ जी

विंडो टू द वर्ल्ड

मणिपुर की लोकटक झील

लोकटक झील मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो अपनी तैरती हुई वनस्पति द्वीपों, जिन्हें फुमदी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है।

हेल्थ इज वेल्थ

सेहत बनाने के लिए रोज सुबह टहलें, ताकि शरीर फिट और एक्टिव रहे। पैदल चलना घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए बेहद फायदेमंद है।

- यह घुटने की क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स जैसी मांसपेशियों को सक्रिय करता है।
- इन्हें स्थिरता और मजबूती प्रदान करता है।
- लेकिन यदि आप सही जूते नहीं पहनते हैं, कठोर सतह पर चलते हैं या फिर आपके चलने का तकरीका सही नहीं है, तो आपके घुटनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
- इससे घुटनों में दर्द, सूजन या फिर घुटनों से संबंधी अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाती हैं।
- हो सकता है कि यह परेशानी लंबे समय तक बनी रहें।
- ऐसे में मॉर्निंग वॉक करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
- इसके लिए सही जूते का चयन करें, सही जूते आपके घुटनों को सपोर्ट और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

अपनों से अपनी सी बात

कर्म बनाम भाग्य

कर्म बड़ा या भाग्य यह बहस दुनिया में सदियों से चली आ रही है। कर्म और भाग्य में बड़ा कौन है, यह प्रश्न सदियों से मानव मन में उभरता रहा है। कर्म को मानने वाले कर्मवादी लोग कहते हैं, कि कर्म ही सब कुछ है और भाग्य कुछ नहीं होता। वहीं भाग्यवादी लोगों का कहना है कि भाग्य ही सब कुछ है और मनुष्य चाहें जो कुछ कर ले, अन्तत होगा वही जो भाग्य में, किस्मत में लिखा होगा। वस्तुतः सत्य क्या है, कर्म बड़ा है या भाग्य, कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य, कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य, कर्म और भाग्य एक दूसरे के विरोधी है या पूरक, ये प्रश्न हमारे मन में अक्सर उठते हैं, पर वास्तव में सच क्या है, कर्म ही प्रधान है। कर्म अच्छा है, तो भाग्य भी अच्छा होगा और कर्म बुरा है, तो भाग्य भी बुरा ही होगा। क्यों, क्योंकि कर्म ही भाग्य के रूप में परिणत होता है। कर्म ही भाग्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। कर्म यदि बीज है, तो भाग्य उस बीज से प्रकट हुआ वृक्ष है। यदि बीज बबूल का है, तो बीज से बबूल का वृक्ष ही प्रकट होगा और यदि बीज आम का है, तो उस बीज से आम का वृक्ष ही प्रकट होगा। उसी प्रकार अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, शुभ कर्म ही अच्छे भाग्य के रूप में व्यक्त होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, परिणत होते हैं, प्रकट होते हैं। भाग्य और कुछ भी नहीं, बल्कि अतीत में या वर्तमान में हमारे द्वारा किए गए कर्मों की ही अभिव्यक्ति है। वही हमारे कर्मों की छाया है, हमारे कर्मों का प्रतिबिम्ब है, हमारे कर्मों का प्रतिफल है। जहां पौरुष है, पुरषार्थ है, दृढ़ इच्छाशक्ति है, प्रचण्ड मनोबल है, आत्मबल है वहीं विजयश्री है, वहीं जीत है, वहीं सफलता है, वहीं जय जयकार है और जहां आलस्य है, अकर्मणयता है, प्रमाद है, वहीं हार है, वहीं असफलता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कर्म करने को ही, पुरषार्थ करने को ही महत्वपूर्ण माना गया है।

-ललित अकिंचन

Feedback@dainiknavajyoti.com

पर्यावरण चिंतन

प्रकृति और मानव हितैषी एजेंडे पर काम करें

बेहद गंभीर समस्या है ग्लोबल वार्मिंग

सुखदेव सिंह

ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वायु, घटते और प्रदूषित जल संसाधन, मिट्टी का क्षरण और उत्पादकता में कमी, खाद्य गुणवत्ता में गिरावट, वनों की आग, बाढ़ और सूखा, समुद्री अम्लीकरण, समुद्री तूफानों की तीव्रता और प्रचंडता में वृद्धि, निरंतर वनों की कटाई, बढ़ता मरुस्थलीकरण, जैव विविधता का ह्रास आदि के रूप में हम देख रहे हैं।

कॉरपोरेट पूंजीवादी व्यवस्था ने वैश्विक स्तर पर हमारे सामने दो बेहद गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी हैं। इनमें से पहली है पर्यावरण क्षरण की समस्या, जो जलवायु परिवर्तन के रूप में हमारे सामने है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वायु, घटते और प्रदूषित जल संसाधन, मिट्टी का क्षरण और उत्पादकता में कमी, खाद्य गुणवत्ता में गिरावट, वनों की आग, बाढ़ और सूखा, समुद्री अम्लीकरण, समुद्री तूफानों की तीव्रता और प्रचंडता में वृद्धि, निरंतर वनों की कटाई, बढ़ता मरुस्थलीकरण, जैव विविधता का ह्रास आदि के रूप में हम देख रहे हैं। दूसरी समस्या अमानवीयकरण से जुड़ी है, जिसका सामना हम गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, भुखमरी, महंगाई, अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई, भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का अभाव, बढ़ती बीमारियों का प्रकोप, बेहद खराब जीवन-स्थिति आदि के रूप में कर रहे हैं। इन सबके कारण आम जनता हताश और निराश है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें।

कॉरपोरेट व्यवस्था

लोगों की इसी स्थिति का फायदा उठाकर सत्ताधारी शक्तियां उनमें नफरत के बीज बोती हैं। घुसपैठ, हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जैसी बातें कहना इसी तरह, अमीर देशों के लोगों को अप्रवासियों के खिलाफ भड़काना कि वे आपकी नौकरियां छीन रहे हैं और आपकी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, अश्वेत लोगों को अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाना, वगैराह वगैराह। कॉरपोरेट व्यवस्था चलाने वाली सरकारें, पार्टियां और कॉरपोरेट कंपनियां खुद को विकास के निर्माता और जनहितैषी बताकर अपना चरित्र छिपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कभी-कभी ये लोगों के गुस्से का शिकार हो जाती हैं। दक्षिण एशिया की हालिया घटनाएं इसकी पुष्टि करती हैं। सार्क देशों, पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और हाल ही में नेपाल में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन इसका स्पष्ट प्रमाण हैं। इन देशों के लोगों, खासकर युवाओं के त्याग और बलिदान का मूल्य तभी आंका जा सकता है, जब सभी नागरिक समय की मांग के मुताबिक प्रकृति-हितैषी और मानव-हितैषी एजेंडे पर काम करें और विकास के कॉरपोरेट मॉडल को नकारकर प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों के विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत करें।

भ्रष्टाचार को रोकना

यहां हम अपनी समझ के अनुसार कुछ बातें दुनिया भर के लोगों, खासकर सार्क देशों, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे। बांग्लादेश और नेपाल में जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं। यहां चुनावों का निष्पक्ष और जन-हितैषी होना अति आवश्यक है। राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, चुनावों को धनबल और बाहुबल से अलग रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए, चुनाव सरकारी खर्च पर होने चाहिए और किसी भी उम्मीदवार, पार्टी या उनके समर्थकों के निजी खर्च पर रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरा उम्मीदवारी की जमानत राशि नकद नहीं होनी चाहिए, बल्कि जमानत संसद के लिए पांच हजार और विधानसभाओं के लिए एक हजार मतदाताओं के हस्ताक्षर के रूप में होनी चाहिए, यह संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तीसरा, उम्मीदवार के लिए कम से कम 50प्रतिशत वोट प्राप्त करना अनिवार्य किया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए दूसरे दौर का चुनाव ही क्यों न कराना पड़े। चौथा, जनता को सीधे चुने गए उम्मीदवार को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए, यानि जब उसके निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम 25प्रतिशत मतदाता उसके खिलाफ लिखित शिकायत करें, तो उसे बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।

जनता के प्रति जवाबदेह

किसी भी उम्मीदवार को दो बार से ज्यादा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। चुने गए उम्मीदवारों को पारदर्शी तरीके से जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ऐसा करके हम राजनीतिक सत्ता आम लोगों के हाथों में ले सकेंगे, जिससे लोगों का सशक्तिकरण होगा। इन सार्क देशों में सरकार बनने के बाद उसे कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, ताकि पूंजी से ज्यादा महत्व प्रकृति, पर्यावरण को दिया जाए। हमारा पहला सुझाव है कि पूरे सार्क और उसमें शामिल प्रत्येक देश में प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, जैसे वायु प्रदूषण रोकना, जल क्षरण और प्रदूषण रोकनाय भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण रोकना, जैव विविधता के विरुद्ध चल रहे सभी कार्यों और गतिविधियों को रोकने के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करना। इन पर्यावरणीय संसाधनों की पुनर्प्राप्ति, विकास और सुरक्षा के लिए एक कार्ययोजना संबंधित सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जानी चाहिए, जिसमें हर प्रदूषणकारी तकनीक को रोकना शामिल हो, चाहे वह कितनी भी उत्पादक और लाभदायक क्यों न लगे। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, जिसके तहत सभी सामाजिक संस्थाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं को 50प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

यह लेखक के अपने विचार हैं।

...पधारो सा म्हारे भरतपुर: घना में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू

भरतपुर। विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में गुलाबी सर्दी शुरू होने के साथ ही प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है, इसे लेकर पर्यटकों में उत्साह है। चित्र में मंगलवार को घना पहुंचा डेसोसाइल क्रेन का झुंड।

जैसलमेर बस हादसा

आग लगते ही बंद हुआ दरवाजा लोग अन्दर जलते, चीखते रहे

सेना ने जेसीबी से तोड़ा गेट, फायर ब्रिगेड 50 मिनट देर से पहुंची

जैसलमेर / जोधपुर। जैसलमेर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग मंगलवार दोपहर मानव त्रासदी का गवाह बना। निजी ट्रावेल्स की चलती एसी स्लीपर बस में अचानक आग लगी और कुछ ही मिनटों में वह चलता हुआ ताबूत बन गई। बस में 57 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 लोग जिंदा जलकर राख हो गए और 15 से अधिक गंभीर रूप से झुलस गए।थईयात गांव के पास दोपहर 3:30 बजे लगी आग का कारण बताया जा रहा है - एसी यूनिट की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट। यह वही बस थी जिसे सिर्फ पांच दिन पहले सामान्य बस को मॉडिफाई कर एसी में बदला गया था। आग सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं थे, न फायर एक्सटिंग्विशर, न इमरजेंसी एग्जिट, न ऑटो-कट सिस्टम।आग लगते ही बस का दरवाजा इलेक्ट्रिक लॉक हो गया, और अंदर बैठे लोग बाहर नहीं निकल सके। खिड़कियां सील्ड थीं और भीतर की फाइबर और फोम सामग्री ने लपटों को और भड़का दिया। ड्राइवर और कंडक्टर किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकले, लेकिन बाकी यात्री चीखते-चिल्लाते मौत के हवाले हो गए। थईयात गांव के शराब ठेकेदार कस्तूर सिंह ने बताया कि बस में आग लगते ही चारों ओर चीखें गूंज उठीं। हम अपने साथियों के साथ दौड़े, लेकिन लपटें इतनी भयानक थीं कि पास नहीं जा सके। तभी एक पानी का टैंकर दिखा, उसे आर्मी कैंट से निकालकर आग बुझाने की कोशिश की। इसी दौरान सेना की जेसीबी पहुंची और उसने गेट तोड़ा, तब जाकर लाशें बाहर निकालीं। कस्तूर सिंह ने बताया कि फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन वह करीब 45 से 50 मिनट देर से पहुंची। हमने अपने सामने 16 लोगों को बाहर निकाला। अंदर दर्जनों लोग पूरी तरह जल चुके थे। कुछ यात्री गैलरी में बैठे थे, जो निकल नहीं पाए।

चश्मदीदों के अनुसार, जब गेट खुला तो बस के अंदर सिर्फ राख, जले कपड़े और पिघले शरीर थे। बच्चों और महिलाओं की पहचान मुश्किल थी। ग्रामीणों और सेना ने घंटों की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाले।

- बस का इंटीरियर फाइबर और फोम से बना था।
- खिड़कियां पूरी तरह कांच की और बंद थीं।
- दरवाजा इलेक्ट्रिक लॉक से नियंत्रित था, जो आग लगते ही जाम हो गया।

पुत्री से दुष्कर्म, पिता को 20 वर्ष का कठोर कारावास

अजमेर। पोक्सो प्रकरण की विशिष्ट न्यायालय संख्या दो की न्यायाधीश अलका शर्मा ने 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पिता को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि एक महिला ने 13 सितम्बर 2024 को किशनगढ़ के गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्जकर पुलिस को बताया कि 6 महीने से ससुराल वाले मानसिक प्रताड़ना देने के साथ ही उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। पति ने पिता होने के बावजूद उसकी 15 वर्षीय बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं पति उसके पांच बच्चों को भी प्रताड़ित कर रहा है।

छोटे को बाइक दिलाने से खफा बड़ा भाई टैंक में कूदा

कोटा। रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में मंगलवार को छोटा सोगरिया में एक युवक के ओवरहेड वाटर टैंक में कूदने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाइश कर टंकी से बाहर निकाला और थाने लेकर आए । पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस निरीक्षक रामस्वरूप मीणा ने बताया कि महेन्द्र कुमार पुत्र नाथूलाल निवासी रामदेव जी मंदिर के पास छोटा सोगरिया शराब के नशे में पानी की बड़ी टंकी पर चढ़ गया था। जिसे पुलिस टीम ने समझाइश कर नीचे उतारा था। उन्होंने बताया कि युवक के पिता ने उसके छोटे भाई को बाइक दिलवाई थी। इससे वह नाराज हो गया। नाराज होकर वह वह पानी सप्लाई के ओवरहेड टैंक में दोपहर 1.25 बजे चढ़ गया और उसमें कूद गया।

आरबीआई के नए सिस्टम से अटके 15 हजार चेक

जोधपुर। आरबीआई के नए रियल टाईम क्लीयरिंग सिस्टम से मंगलवार को जोधपुर की 200 बैंक शाखाओं के अरबों रुपए के लेनदेन के करीब 15 हजार चेक अटके हुए हैं। यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के संयोजक राजन गहलोत ने बताया, आरबीआई ने बिना तैयारी के नया सिस्टम चालू कर दिया और ना ही जरूरी तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर दिए। जिसके चलते दीपावली की सीजन में जहां पैसों के अभाव में ग्राहक परेशान हो रहे हैं, वहीं व्यापारियों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। पैसे नहीं मिलने पर ग्राहकों का गुस्सा बैंक कर्मचारियों पर फूट रहा है। जबकि बैंक पहले से ही स्टॉफ की कमी से जूझ रहे हैं।

युवक की संदिग्ध मौत, सड़क किनारे मिला शव

भुसावर। खेड़ली मोड़ थाना क्षेत्र के पथेना-खेड़ली सड़क मार्ग पर स्टेट मेगा हाईवे 45 स्थित एक पेट्रोल पंप के पास एक 45 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर खेड़ली मोड़ थाना पुलिस और भुसावर सीओ धर्मेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान पथेना गांव निवासी 45 वर्षीय ज्ञान सिंह पुत्र दामोदर जाट के रूप में हुई है। हत्या की आशंका जताए जाने के बाद, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जैन साध्वी हर्ष प्रभा का देवलोकगमन

उदयपुर। शहर में जैन साध्वी डॉ. हर्ष प्रभा का संथारापूर्वक देवलोकगमन हो गया। वे 71 वर्ष की थी। तारक गुरु जैन गंथालय के महामंत्री रमेश खोखावत ने बताया कि उपाध्याय पुष्कर मुनि व आचार्य देवेंद्र मुनि की सुशिष्या व वर्तमान आचार्य शिवमुनिजी की आज्ञानुवर्तिनी साध्वी डॉ. हर्ष प्रभा पिछले 35 वर्ष से उदयपुर के तारक गुरु जैन ग्रंथालय परिसर में स्थिरवास थी। रात करीब 12.50 बजे उनके देवलोकगमन हो गया था। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेशलाल गोखरू ने बताया कि साध्वीजी के पार्थिव देह की डोल यात्रा मंगलवार दोपहर 12.15 बजे शास्त्री सर्कल स्थित तारक गुरु जैन ग्रंथालय से अशोक नगर मोक्षधाम तक निकली।

जेनेटिकली मोडिफाइड फूड के निर्माण, बिक्री पर रोक

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) फूड यान आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थो के लिए केन्द्र सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को छह माह में विस्तृत नियम बनाने और उन्हें लागू करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने नियम नहीं बनने तक किसी भी जीएम फूड के निर्माण, बिक्री, वितरण और आयात की मंजूरी नहीं देने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि विदेश से आयात होने वाले हर फूड के लिए जीएम फ्री प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश कृतेश ओसवाल व अन्य की जनहित याचिका पर दिए। खंडपीठ ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि खाद्य उत्पादों में जेनेटिकली मोडिफाइड का मामला एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने अभी तक प्रासंगिक नियमों को ही अंतिम रूप नहीं दिया है और ना ही इन्हें अधिसूचित ही किया है।

हाइपरसोनिक उड़ान, पानी और शीतलन की नई तकनीक

आईआईटी जोधपुर में रॉकेट को हल्का और पुनः प्रयोग योग्य बनाने पर शोध, धमाकों से मिलेगी सुरक्षा

नवज्योति/जोधपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर के वैज्ञानिकों ने हाइपरसोनिक प्रणोदन, जल शुद्धिकरण, शीतलन और धमाका-रोधी सुरक्षा तकनीकों के क्षेत्र में अभिनव शोध कर नई दिशा दिखाई है।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग एवं स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च डिवीजन के सहायक प्रो. डॉ. अरुण कुमार के निर्देशन में शॉक वेव्स एंड हाई-स्पीड फ्लो लैब में चल रहा शोध भारत की तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहा है। डॉ. कुमार की टीम ऐसे स्क्रैमजेट इंजन विकसित कर रही है जो वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, जिससे भारी ऑक्सीजन टैंकों की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसमें हाइपरसोनिक प्रणोदन से हल्के और सस्ते रॉकेट बनाए जा रहे हैं। इस नवाचार से रॉकेट अधिक हल्के, किफायती और तीव्र गति से उड़ने में सक्षम होंगे।

कल्पना नहीं, ठोस समाधान

डॉ. अरुण कुमार ने कहा, हमारा शोध भविष्य की कल्पनाएं नहीं, बल्कि ठोस समाधान है। चाहे हाइपरसोनिक उड़ान हो, पानी व शीतलन की समस्या हो, या नागरिकों की सुरक्षा। यह भारत को तकनीकी नेतृत्व की दिशा में अग्रसर करेगा और विकसित भारत के सपने को साकार करेगा।

शोध डीआरडीओ और एआरडीबी की ओर से समर्थित

यह शोध डीआरडीओ और एआरडीबी की ओर से समर्थित है और सीधे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ा है। आईआईटी जोधपुर की टीम रॉकेट को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की दिशा में भी कार्यरत है जो अंतरिक्ष अभियानों की लागत को काफी कम करेगा। इसके साथ ही, धमाकों से उत्पन्न शॉक वेव्स से सुरक्षा को लेकर विशेष सुरक्षात्मक पदार्थ और ढांचे तैयार किए जा रहे हैं, जो रक्षा और नागरिक सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में उपयोगी होंगे। संस्थान की दूसरी बड़ी पहल सौर ऊर्जा आधारित संयुक्त समुद्री जल शुद्धिकरण व शीतलन प्रणाली है। एएनआरएफ और एआरजी की ओर से समर्थित इस परियोजना के तहत ऐसी तकनीक विकसित की गई है जो एक साथ पेयजल और ठंडक प्रदान कर सकती है। इसका प्रयोगशाला स्तर पर सफल परीक्षण किया जा चुका है और अब इसका प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है। यह तकनीक विशेष रूप से पानी और बिजली की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकती है।

आरपीएससी अभ्यर्थी 28 से कर सकेंगे आवेदन

सांख्यिकी अधिकारी के 113 पदों के लिए निकाली भर्ती

अजमेर। आरपीएससी ने मंगलवार को सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 113 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर से 26 नवम्बर तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी की आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयोग ने इन पदों के लिए पूर्व में वर्ष 2023 में विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद इन पदों के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इसलिए जो अभ्यर्थी 1 जनवरी 2026 को अधिक आयु के होते हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

बेंजीन फ्यूल भरा था, हाईवे पर लंबा जाम लगा

चलते टैंकर में आग से दो घंटे अफरा-तफरी

बांदरसिंदरी। हाइवे स्थित दूदू-दातरी क्षेत्र में मंगलवार शाम जयपुर से अजमेर जा रहे बेंजीन फ्यूल से भरे टैंकर के पिछले टायरों में अचानक आग लग गई । आग लगते ही हाइवे पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दूदू और किशनगढ़ से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान हाइवे पर दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े। टैंकर में करीब 25 हजार लीटर बेंजीन फ्यूल भरा हुआ था जो इंडियन ऑयल रिफाइनरी पानीपत से बड़ौदा रिफाइनरी की ओर जा रहा था। आग लगने के दौरान चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे रोक दिया और समय रहते खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दमकलकर्मियों ने सावधानी से कूलिंग कर टैंकर को ठंडा किया। राहत की बात रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करना उद्देश्य

सीबीएसई: छात्र पढ़ेंगे ई-पत्रिका 'सपनों की उड़ान'

अजमेर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के छात्र एनसीईआरटी की ई-पत्रिका 'सपनों की उड़ान' पढ़ेंगे। बोर्ड ने बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाते हुए स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों को नियमित रूप से सपनों की उड़ान पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बोर्ड सचिव के अनुसार एनसीईआरटी द्वारा विकसित मासिक ई-पत्रिका सपनों की उड़ान के 5वें अंक का विमोचन हुआ है। इसका शीर्षक 'भारत का गौरवशाली अतीत और विरासत है'। यह ई पत्रिका युवाओं को पठन के आनंद के बारे में प्रेरित और शिक्षित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य छात्रों में आजीवन पठन की आदत विकसित करना है।

इस पहल के माध्यम से, हम छात्रों की पठन और लेखन दक्षता को बढ़ाने के साथ कम उम्र से ही उनकी रचनात्मकता, कल्पनाशीलता, आलोचनात्मक सोच और शब्दावली का पोषण करने का प्रयास कर सकते हैं। स्कूल छात्रों को आनंददायक और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए इसे पठन संवर्धन गतिविधियों में शामिल करें।

मंत्री के काफिले में शामिल कार की चपेट में आए बच्चे ने दम तोड़ा

नवज्योति/कोटा । दो दिन पहले कोटा से जयपुर जाते समय देवली थाना क्षेत्र में ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर के काफिले में शामिल एक कार के चपेट में आए पांच वर्षीय बालक की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जबकि अन्य घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। देवली पुलिस ने कार चालक मनरुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थानाधिकाधिकारी दौलत सिंह ने बताया कि रविवार शाम टोंक में गोपीपुरा के निकट कोटा से जयपुर जाते समय ऊर्जा मंत्री नागर के काफिले में चल रही कार के आगे 5 वर्षीय बालक आ गया था। घटना में कार पलट गई थी। जिससे बालक सहित पांच जने घायल हो गए थे। नागर रविवार को सीएम भजनलाल शर्मा के साथ होने वाली मीटिंग में जा रहे थे।

बेटे के प्रेम प्रसंग का खामियाजा भुगतना पड़ा, चार युवक हिरासत में

बाइक सवार युवकों की चौराहे पर फायरिंग, पिता घायल

न्यूज सर्विस/नवज्योति, शाहपुरा। कस्बे में सोमवार देर रात प्रेम प्रसंग को लेकर हुई फायरिंग की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। शहर के प्रमुख चौराहे त्रिमूर्ति चौराहे पर मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी अनुसार फायरिंग की यह घटना बेटे के प्रेम प्रसंग के चलते उसके पिता से रंजिश का नतीजा है।

जानकारी अनुसार कस्बा निवासी सलीम खान (42) त्रिमूर्ति चौराहे पर भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज सुगन्धी से कुछ बात कर रास्ते में छोड़ देने की बात बोल उन्हीं की बाइक पर बैठा ही था कि अचानक एक बाइक पर सवार युवकों ने उस पर फायर कर दिया। गोली लगने से सलीम खान वहीं गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फायरिंग की जड़ में सलीम खान के बेटे का एक लड़की से प्रेम प्रसंग है, जो उसी के समाज से संबंधित है। पुलिस ने मामले में चार संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। इस मामले को लेकर देर शाम तक कुछ स्थानों पर दबिश दी है। पुलिस ने घायल सलीम खान के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

घर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास, रिपोर्ट दर्ज

बच्ची को टॉपी का झांसा देकर साथ ले गया

न्यूज सर्विस/नवज्योति, भरतपुर। शहर के कोतवाली क्षेत्र में पड़ौसी द्वारा सात वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर मंगलवार सुबह पीड़िता की मां ने कोतवाली थाने में शिकायत में बताया कि सोमवार दोपहर 1 बजे बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि इस दौरान पड़ौसी युवक जॉनी शर्मा उम्र 25 वर्ष बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने घर ले गया और घर अंदर से बंद कर बच्ची से अश्लील हरकत करने लगा। इस दौरान बच्ची जोरों से रोने लगी। बच्ची की आवाज सुनकर परिजन बाहर दौड़े तो पता चला कि आवाज पड़ौस के घर से आ रही है। इसके पड़ौसी के दरवाजे को खटखटाया तो लगभग 15 मिनट बाद युवक ने दरवाजा खोला, तब बच्ची भागकर परिजनों के पास आ गई। वह काफी डरी हुई थी तथा रो रही थी। मां ने बताया कि घटना के बाद शाम को युवक के घर उल्हाना देने को गए तो परिजनों ने उनके साथ मारपीट की। वहीं पुलिस का कहना है कि पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दी है जिसमें जांच की जाएगी।

कर्ज से परेशान मार्बल व्यवसायी ने किया सुसाइड

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर। सुखेर थाने के पीछे स्थित अपनी फैक्ट्री में एक मार्बल व्यवसायी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में पांच सूदखारों से परेशान होकर यह कदम उठाने की जानकारी दी है। थानाधिकारी रविन्द्र चारण ने बताया कि मृतक रवि भट्ट ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें 5 लोगों के नाम का उल्लेख करते लिखा है कि इनसे रुपए उधार लेकर बड़ी भूल कर दी। इनको मूल से भी ज्यादा ब्याज दे दिया। अब भी नोंचते रहते हैं। मेरे इस कदम के लिए यही लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। अब स्थिति बहुत ही विकट हो चुकी है।

अब मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। परिवार वालों, मित्रों, परिचितों सभी से रुपया उधार ले लिया और किसी को भी लौटा नहीं पाया। पिछले 5 सालों से कर्ज में डूबता ही गया। अमरजीत सिंह कंडा, अमन कंडा, जतिन कंडा, सनत सिकलीकर और टीटू सरदार को मूल से भी ज्यादा ब्याज दे दिया। इनकी ब्याज दर 7.50 से 18 प्रतिशत तक है और देरी होने पर पेनल्टी की रेट तो अनाप-शनाप है।

बाइक के पहिए में महिला की ओढ़नी फंसी, मौत

पाली। बैंक से रुपए निकाल कर पति-पत्नी वापस बाइक से अपने घर लौटते समय रास्ते में महिला अचानक बाइक से नीचे गिर गईं। हादसे में महिला के सिर में गंभीर चोट लगने पर उसे बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां जांचके बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार बिरामी गांव निवासी सीतादेवी (35) पत्नी देवाराम बाइक से सांडेराव बैंक से रुपए निकालने गई थी। वापस आते समय मनवार होटल के पास सीता अचानक बाइक से नीचे गिर गईं। बताया जा रहा है कि उसकी ओढ़नी बाइक के पहिए में आ गई थी। इससे उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ी। जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई।

झीलों की नगरी एक बार फिर रचने जा रही इतिहास

राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन का आगाज: भारत में वैश्विक पर्यटन की उड़ान

प्रधानमंत्री के वन स्टेट- वन ग्लोबल डेस्टिनेशन विजन पर होगा आधारित

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर। झीलों की नगरी एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के तत्वावधान में मंगलवार को यहां होटल मेरिएट में दो दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें देश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर आगे बढ़ाने की एक नई दिशा तय होगी। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया तथा राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर देश के सभी राज्यों के पर्यटन मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पर्यटन सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण पर आधारित था, जिसमें प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुसार एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है।

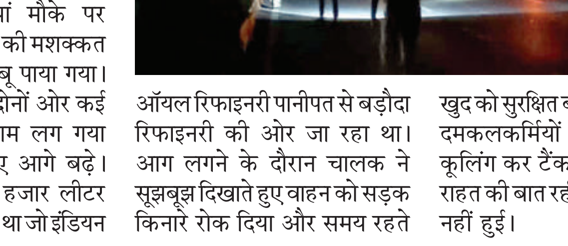

भारत बनेगा पर्यटन का वैश्विक अग्रदूत: शेखावत

उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत ने कहा कि भारत में वैश्विक स्तर की पर्यटन क्षमता है। सरकार का लक्ष्य भारत को वर्ल्ड ट्यूरिज्म इंडेक्स (डब्ल्यूटीआई) में शीर्ष 10 देशों में शामिल करना और जीडीपी में पर्यटन का योगदान 10 प्रतिशत तक बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में लगभग 2 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए, जबकि घरेलू पर्यटन में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। कोविड के बाद भारत ने पर्यटन पुनर्जीवित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में भारत डब्ल्यूटीआई में39वें स्थान पर है, और इसमें 18-20 प्रतिशत पैरामीटर्स केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, बाकी राज्यों की नीतियों पर निर्भर हैं।

हर किला, हर महल कहानी कहता है: दिया कुमारी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान का हर किला, महल और धरोहर अपनी एक अलग कहानी कहता है। राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, विविध रंगों से भरी संस्कृति और कला विश्वभर में प्रसिद्ध है। राजस्थान अपने आप में एक आइकोनिक ट्यूरिज्म डेस्टिनेशन है।

मेवाड़ धरा परंपरा और प्रकृति का संगम: कटारिया

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मेवाड़ क्षेत्र कोप्रकृति और परंपरा का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने आग्रह किया कि वे उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थानीय पर्यटन की संभावनाओं पर सुझाव दें।

कुएं से निकाले मां-बेटे के शव

भीलवाड़ा। जिले के सोदानपुरा गांव में कुएं में गिरे महिला व उसके पुत्र के शव देर रात अजमेर से आई एसडीआरएफ की टीम ने ढूंढ निकाले। दोनों शवों का मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम करवा दिया गया। उधर पति ने पुलिस को रिपोर्ट में घटना को हादसा बताया है। मांडल थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि सोदानपुरा निवासी राजू भील की पत्नी लक्ष्मी उम्र 30 व 10 साल का बेटा दिलखुश सोमवार दोपहर गांव के नजदीक ही मानसी नदी के किनारे स्थित कुएं में गिर गए थे। देर रात अजमेर से पहुंची एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। अथक प्रयास के बाद पहले दिलखुश व बाद में लक्ष्मी का शव कुएं से बाहर निकाला, जिन्हें मांडल अस्पताल भिजवा दिया।

वित्तीय शेयरों में कमजोरी

बाजार में गिरावट बरकरार

रॉयटर्स
मुंबई, 14 अक्टूबर

भारत के शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही। वित्तीय शेयरों के पिटने की वजह से शेयर बाजार लुढ़के मगर उन्होंने अधिकांश एशियाई बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक टकराव गहराने से दुनिया के कई बाजारों में निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता पर असर पड़ा है।

निफ्टी 50 सूचकांक 0.32 फीसदी टूटकर 25,145.5 पर आ गया। सेंसेक्स 0.36 प्रतिशत गिरकर 82,029.98 पर आ गया। शुक्रवार को अमेरिका द्वारा चीन के खिलाफ नए टैरिफ की धमकी के बाद जहां दोनों बेंचमार्क दो सत्रों में लगभग 0.6 फीसदी गिरे वहीं अन्य एशियाई बाजारों में 1.9 फीसदी की गिरावट आई। हालांकि तब से अमेरिका का रुख नरम हुआ है। लेकिन एशियाई बाजारों में गिरावट जारी है। एसएमसी ग्लोबल में रिटेल इक्विटी के सहायक उपाध्यक्ष सौरभ जैन ने कहा, 'टैरिफ अनिश्चितता की ताजा धमकी के बीच भारत अन्य एशियाई बाजारों की तुलना में अच्छी स्थिति में रहा है।'

उन्होंने कहा, 'सरकारी कर कटौती और सहायक मौद्रिक नीति के कारण, वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आय में सुधार की उम्मीद ने इसका असर कम करने में मदद की है। फिर भी, जब तक आय में सुधार के स्पष्ट संकेत नहीं मिलते, तब तक बाजार एक दायरे में बने रहेंगे।' इस सप्ताह मामूली गिरावट से पहले शुक्रवार को प्रमुख सूचकांकों ने तीन महीनों में अपना सर्वश्रेष्ठ सप्ताह दर्ज किया था। स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में क्रमशः लगभग 0.9 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई।

सभी 16 प्रमुख सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई। वित्तीय और बैंक शेयर लगभग 0.2 फीसदी टूटे जबकि निजी ऋणदाताओं और सरकारी बैंकों में क्रमशः 0.3 फीसदी और 1.5 फीसदी की कमी हुई। मुनाफावसूली के कारण तीन सत्रों की बढ़त के बाद सूचकांक गिरावट का शिकार हुए।

शेयरों की बात करें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (जो बेंचमार्क का हिस्सा नहीं है) अपने निर्गम मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुआ। 2021 में इटरनल के बाद से एक अरब डॉलर के आईपीओ के लिहाज से यह सबसे शानदार लिस्टिंग रही। एलजी का शेयर 48.2 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ। सितंबर तिमाही के मुनाफे में बढ़ोतरी के साथ वेल्थ मैनेजमेंट फर्म आनंद राठी वेल्थ में 7.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

अन्य एशियाई बाजारों के मुकाबले प्रदर्शन बेहतर

- अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक टकराव बढ़ने से निवेशकों की जोखिम क्षमता पर असर
- सेंसेक्स और निफ्टी में दो सत्रों में आई लगभग 0.6 फीसदी की गिरावट
- निफ्टी 50 सूचकांक 0.32 फीसदी टूटकर 25,145.50 पर आ गया
- सेंसेक्स 0.36 प्रतिशत गिरकर 82,029.98 पर आ गया

सोना पहुंचा 4,100 डॉलर के पार

रॉयटर्स
बेंगलूरु, 14 अक्टूबर

मंगलवार को सोने की कीमतें 4,100 डॉलर से ऊपर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। इसकी मुख्य वजह इस महीने अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदें और दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच नए सिरे से व्यापारिक टकराव के बाद सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग है।

11.38 बजे तक हाजिर सोना 0.5 फीसदी बढ़कर 4,129.16 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। सत्र के शुरू में यह 4,179.48 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। दिसंबर डिलिवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4,147.10 डॉलर हो गया।

इस साल सोने की कीमतों में अब तक 57 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को पहली बार यह 4,100 डॉलर का अहम स्तर पार कर गया। भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों, केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीदारी और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों में शानदार निवेश आने की वजह से यह बढ़त हासिल हुई है।

नेमो डॉट मनी के मुख्य बाजार विश्लेषक हान टैन ने कहा, 'वैश्विक व्यापार टकराव की नई चिंताओं ने सोने को 4,100 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर पहुंचा दिया है।' अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसंट ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अक्टूबर के अंत में दक्षिण कोरिया में चीनी नेता शी चिनफिंग से मिलने के लिए तैयार हैं।

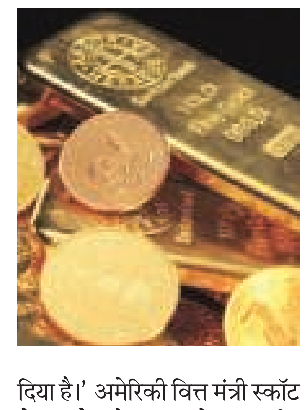

हालांकि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता तेज हो गई है। लेकिन दोनों देश समुद्री शिपिंग कंपनियों पर बंदरगाह शुल्क लगाना शुरू कर देंगे जो हॉलिडे टॉय से लेकर कच्चे तेल तक सब कुछ पहुंचाती हैं। बैंक ऑफ अमेरिका और सोसियाते जेनेराली के विश्लेषकों का अनुमान है कि 2026 में सोना 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएगा।

सोने और हाजिर बाजार की तंगी को समर्थन देने वाले इन्हीं कारकों की वजह से हाजिर चांदी 1.6 फीसदी गिरकर 51.49 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। इससे पहले यह 53.60 डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी।

एमसीएक्स ने सोने और चांदी पर मार्जिन बढ़ाया

एमसीएक्स की क्लियरिंग शाखा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन (एमसीएक्ससीसीएल) ने कीमती धातुओं में बढ़ती वैश्विक अस्थिरता के मद्देनजर सोने के अनुबंधों पर मार्जिन में 1 प्रतिशत और चांदी पर 1.5 प्रतिशत की वृद्धि की है। एक बयान में एमसीएक्स और एमसीएक्ससीसीएल ने कहा कि वे डेरिवेटिव अनुबंधों की गहन निगरानी कर रहे हैं और नियामकीय मानदंडों के अनुरूप निष्पक्ष और पारदर्शी कारोबार सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। एमसीएक्स 30 किलोग्राम और 5 किलोग्राम चांदी के वायदा और विकल्पों में सौदों के साथ-साथ 1 किलोग्राम चांदी के वायदा सौदों की पेशकश करता है। एक्सचेंज ने वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमतों में हाल में तेज उतार-चढ़ाव दर्ज किया। एक्सचेंज में कारोबार वाले चांदी के अनुबंधों की कीमतों और स्थानीय बाजारों में कीमतों के बीच बढ़ते अंतर से यह जाहिर हुआ है। *बीएस*

रुपये में फिर आई गिरावट

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव में थोड़ी नरमी आने के बावजूद दुनिया भर में जोखिम से बचने की धारणा कमजोर पड़ने से मंगलवार को रुपये में गिरावट आई। डीलरों ने बताया कि मंगलवार को रुपया 88.80 प्रति डॉलर के नए निचले स्तर पर बंद हुआ।

रुपया पिछले बंद भाव 88.68 प्रति डॉलर के मुकाबले 12 पैसे टूटकर बंद हुआ। चालू वित्त वर्ष में अब तक इसमें 3.75 फीसदी की गिरावट आई है और इस साल अब तक यह 3.59 फीसदी तक टूट चुका है। डीलरों ने बताया कि इस महीने रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास चल रहा है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के कारण इसमें कम उतार-चढ़ाव रहा। बाजार की नजर अब इस बात पर है कि केंद्रीय बैंक विनिमय दर को 89 या उससे पार कब जाने देगा।

एक सरकारी बैंक के डीलर ने कहा, 'रिजर्व बैंक रुपये 88.80 प्रति डॉलर के स्तर का बचाव कर रहा है। अगर यह स्तर टूटता है तो अगला पड़ाव 89 और 89.50 प्रति डॉलर होगा।' उल्लेखनीय है कि इस महीने रुपये में अब तक 0.1 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। आईएफए ग्लोबल के संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी अभिषेक गोयनका ने कहा, 'रुपया आज हल्के दबाव में रहा और डॉलर के मुकाबले लगभग 12 पैसे गिरा। अमेरिका-चीन व्यापार तनाव में कुछ कमी के बावजूद वैश्विक जोखिम धारणा बनी रही। सुरक्षित निवेश की नई मांग के चलते डॉलर में फिर से मजबूती आई। रुपये ने कुछ समय के लिए अपने रिकॉर्ड निचले स्तर को छुआ मगर केंद्रीय बैंक के संभावित हस्तक्षेप से उसे समर्थन मिला। *बीएस*

मूल कंपनी से अधिक हुआ एलजी इंडिया का मूल्यांकन

समी मोडक और
समीर मुलगांवकर
मुंबई, 14 अक्टूबर

सूचीबद्धता के बाद शेयर मूल्य में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि के बाद एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का मूल्यांकन अब लगभग 13 अरब डॉलर हो गया है, जो उसकी दक्षिण कोरियाई पैतृक कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक के 9.4 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण से 37 प्रतिशत अधिक है।

इस आईपीओ में सोल में मुख्यालय वाली मूल कंपनी ने 15 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 1.3 अरब डॉलर (करीब 11,607 करोड़ रुपये) जुटाए। शेष 85 फीसदी हिस्सेदारी का मूल्यांकन करीब 11 अरब डॉलर है जो एलजी के स्वयं के बाजार पूंजीकरण से करीब 17 फीसदी अधिक है। एलजी अब मारुति सुजूकी इंडिया के साथ अपनी मूल कंपनी के मूल्यांकन को पीछे छोड़ने वाली कंपनी बन गई है। भारत की सबसे बड़ी यात्री कार निर्माता कंपनी मारुति का मूल्यांकन 57.5 अरब डॉलर है, जो सुजूकी मोटर कॉर्प के 28.3 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा है। सुजूकी के पास अपनी भारतीय सहायक कंपनी में 58.28 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

हालांकि घरेलू स्तर पर सूचीबद्ध ज्यादातर बहुराष्ट्रीय सहायक कंपनियां अपनी मूल कंपनियों के बाजार पूंजीकरण से आगे नहीं निकल पातीं, फिर भी वे आम तौर पर ऊंचे मूल्यांकन प्रीमियम पर कारोबार करती हैं। ऐसी 11 कंपनियों के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 12 महीनों के कीमत-आय (पी/ई) मल्टीपल उनकी मूल कंपनियों की तुलना में दो से छह गुना ज्यादा हैं।

इस रुझान ने एलजी और ह्युंडै जैसी कंपनियों को भारत में सूचीबद्धता की राह पर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू बाजारों पर एलजी की दमदार शुरुआत कई अन्य दिग्गजों को भारत में लिस्टिंग के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

टाटा का पीवी कारोबार 1.45 लाख करोड़ रु. का

सिराली गुप्ता
मुंबई, 14 अक्टूबर

टाटा मोटर्स के यात्री वाहन (पीवी) व्यवसाय का विलय के बाद मूल्यांकन अब 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो विलय-पूर्व मूल्यांकन से लगभग 40 प्रतिशत कम है। इस व्यवसाय में इलेक्ट्रिक वाहन और जगुआर लैंड रोवर व्यवसाय भी शामिल हैं। वहीं इसकी वाणिज्यिक वाहन (सीवी) इकाई (जिसके लगभग एक महीने में अलग से सूचीबद्ध होने की उम्मीद है) का मूल्यांकन भी लगभग इतना ही रहने की संभावना है।

विलय के बाद, वैश्विक वित्तीय सेवा समूह नोमूरा ने सीवी व्यवसाय के लिए 365 रुपये और पीवी इकाई के लिए 367 रुपये का कीमत लक्ष्य निर्धारित किया है।

बीएसई पर टाटा मोटर्स (पीवी) का शेयर 0.88 प्रतिशत की गिरावट के साथ 395.5 रुपये पर बंद हुआ। इसकी तुलना में, सेंसेक्स 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,029.98 पर बंद हुआ।

यात्री वाहन (पीवी) कंपनी में टाटा संस (गैर-सूचीबद्ध), टाटा स्टील और टाटा टेक्नोलॉजी के साथ-साथ अन्य निवेश भी शामिल हैं। वाणिज्यिक वाहन (सीवी) इकाई में घरेलू सीवी व्यवसाय, इवेको व्यवसाय (अधिग्रहण 2026 में पूरा होगा) और टाटा कैपिटल में हिस्सेदारी शामिल होगी।

नोमूरा ने एक नोट में कहा कि विभाजन के बाद हमारा कीमत लक्ष्य दोनों कंपनियों के बीच लगभग बराबर-बराबर बंटा हुआ है - वाणिज्यिक वाहन (सीवी) के लिए 365 रुपये और यात्री वाहन (पीवी) के लिए 367 रुपये।

- वाणिज्यिक वाहन व्यवसाय के 4 से 6 सप्ताह में इसी मूल्यांकन पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद
- बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर टाटा मोटर्स (पीवी) का शेयर 0.88 प्रतिशत की गिरावट के साथ 395.5 रुपये पर बंद हुआ

नोमूरा को उम्मीद है कि 22 सितंबर से लागू जीएसटी कटौती से त्योहारों और रुकी हुई मांग के कारण यात्री वाहन (पीवी) व्यवसाय की गति और तेज होगी। प्रीमियम प्रमुख थीम बना हुआ है, जिसमें पंच और नेक्सन जैसी कॉम्पैक्ट और माइक्रो एसयूवी की जबरदस्त बुकिंग देखी गई है। हाल में पेश हैरियर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को भी शुरुआती उम्मीदों से ज्यादा बुकिंग के साथ-साथ उत्साहजनक प्रतिक्रिया भी मिली है।

वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रबंधन को वित्त वर्ष 2026एफ में लगभग 5 प्रतिशत की उद्योग वृद्धि (यानी वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि) की उम्मीद है, जिसे जीएसटी में कटौती से मदद मिलेगी। इवेको अधिग्रहण का वित्त पोषण शुरू में 3.8 अरब यूरो के ऋण और बाद में 40 प्रतिशत इक्विटी से किया जाएगा। नोमूरा ने अभी तक इस सौदे से किसी भी मूल्य सृजन को शामिल नहीं किया है। कंपनी को 2024-28ई के दौरान राजस्व में 5 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) और एबिटा मार्जिन में 5.4 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक सुधार की उम्मीद है।

इस विभाजन का कंपनी पर निफ्टी और सेंसेक्स जैसे सूचकांकों में उसकी स्थिति पर असर पड़ेगा। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि वाणिज्यिक वाहन कारोबार निफ्टी और सेंसेक्स से हट जाएगा जबकि पीवी इकाई दोनों सूचकांकों का हिस्सा बनी रहेगी।

adani
WELSPUN

TENDER NOTICE

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST FOR VARIOUS CATEGORIES OF SERVICES & SUPPLIES

Adani Welspun Exploration Limited (AWEL) "Operator" has been awarded MB-OSN-2005/2 [under a Production Sharing Contract (PSC)], Contract Area MB/OSDSF/B9/2016 and Contract Area MB/OSDSF/C37/2024 [under a Revenue Sharing Contract (RSC)] by the Government of India. These acreages are in shallow water situated in the Tapti Daman sector of the Mumbai Offshore Basin.

The Operator intends to kick start the development program in these shallow water acreages. The Operator would be tendering for various Surface facility related services and procurement for carrying out development activities in these acreages. The Operator invites Expression of Interest from Indian and International companies for the purpose of pre-qualifying experienced bidders, for supplying services / items as listed in the detailed EOI published on our website https://www.adaniwelspun.com (Contracts > Open EOIs).

Interested companies are requested to visit our website and submit their interest to the respective EOI by clicking "Submit Response" within three weeks from publication of this EOI in newspaper.

pnb Housing
Finance Limited
Ghar Ki Baat

Regd. Office : 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001
Phone: 011 - 66030500, E-mail: investor.services@pnbhousing.com,
Website: www.pnbhousing.com, CIN: L65922DL1988PLC033856

सदस्यों को डाक मतपत्र की सूचना

एतद् द्वारा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि धारा 108 और 110 के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अन्य लागू प्रावधान के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमों, 2014 (''प्रबंधन नियम'') के नियम 20 और 22, सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचिकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 (''सेबी सूचीबद्धता विनियम'') के विनियमन 44 के रूप में संशोधित और अन्य लागू कानूनों और विनियमों एमसीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ पठित, अन्य बातों के साथ साथ ई–मतदान के माध्यम से डाक मतपत्र आयोजित करने के लिए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सभी अन्य संबंधित परिपत्र सहित परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और नवीनतम यानी 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025, (सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'') सेबी परिपत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2024, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी और एमसीए द्वारा अधिसूचित सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस–2) और संबंधित सेबी परिपत्र और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, जिसमें कोई सांविधिक संशोधन(ओं) या पुन: अधिनियमन शामिल है, जो समय –समय पर लागू और संशोधित किए गए हैं, इस डाक मतपत्र (''सूचना'') में निर्धारित विशेष व्यवसाय को संपादित करने के लिए, इसके अंतर्गत सामान्य संकल्प पारित करके, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (''दूरस्थई–मतदान'' या '' ई–मतदान'') के माध्यम से मतदान करके डाक मतदान के माध्यम से कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन मांगा जाता है।

मद सं.	प्रस्तावित संकल्प	संकल्प का प्रकार
1.	कंपनी के नामित गैर–कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री डी. सुरेंद्रन (डीआईएन : 10174317) की नियुक्ति	सामान्य

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने मंगलवार, 14 अक्टूबर, 2025 को उन सदस्यों को इलेक्टॉनिक मोड (ईमेल) के माध्यम से व्याख्यात्मक विवरण और ई–मतदान निर्देशों के साथ डाक मतपत्र सूचना का प्रेषण पूरा कर लिया है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरीज प्रतिभागी(ओं) द्वारा सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी मालिकों की सूची में दिखाई दिए हैं और शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 (''कट–ऑफ डेट'') को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर कंपनी/डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं। डाक मतपत्र सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.pnbhousing.com,** पर स्टॉक एक्सचेजों की वेबसाइट यानी **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** और **www.evoting.nsdl.com** में एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों के नाम रजिस्टर में या कट–ऑफ दिनांक के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा रखी गई लाभकारी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं, वे दूरस्थ ई–मतदान के माध्यम से सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए पात्र हैं। एक व्यक्ति जो कट–ऑफ दिनांक के अनुसार सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए मानेगा।

ई–मतदान के निर्देश: कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई–मतदान प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की सेवाएं ली हैं, ताकि सूचना में निर्धारित सामान्य संकल्प पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

ई–मतदान सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी :

दूरस्थ ई–मतदान प्रारंभ होने की अवधि	बुधवार, 15 अक्टूबर, 2025, पूर्वाह्न 09:00 बजे (आईएसटी)
दूरस्थ ई–मतदान समाप्त होने की अवधि	गुरूवार, 13 नवंबर, 2025, अर्पाह्न 05:00 बजे (आईएसटी)

दूरस्थ ई–वोटिंग सुविधा को एनएसडीएल द्वारा 05:00 बजे (आईएसटी) गुरूवार, 13 नवंबर, 2025 के बाद अक्षम कर दिया जाएगा।

दूरस्थ ई–मतदान की प्रक्रिया पर विस्तृत प्रक्रियाऔर अनुदेश जिसमें सदस्य अपना ईमेल पते को पंजीकृत कर सकते हैं और/या अपना वोट डाल सकते हैं, सूचना में निर्दिष्ट किए गए हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री सुजीत कुमार (सदस्यता सं. एफसीएस 12562, सीपी नंबर 22684), श्री विजय के सिंघाल (सदस्यता सं. एफसीएस13221, सीपी नंबर 10385), को संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स के भागीदारों, कंपनी सचिवों, नई दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया में एक निष्पक्ष और पारदर्शीता में संचालन के लिए ''संवीक्षाकर्ता'' के रूप में नियुक्त किया है।

डाक मतपत्र के परिणामों की घोषणा शनिवार, 15 नवंबर, 2025 को या उससे पहले संवीक्षाकर्ता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद की जाएगी और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर संप्रेषित की जाएगी, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है और कंपनी की वेबसाइट यानी **www.pnbhousing.com** और एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी प्रदर्शित होंगे।

ई–मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल **www.evoting.nsdl.com** अनुभाग डाउनलोड पर उपलब्ध है या कॉल करें : 022–48867000 और 022–24997000 या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडील को evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध भेजें। आप **investor.services@pnbhousing.com** पर भी लिख सकते हैं।

प्रति पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता./–
वीना जी कामथ
कंपनी सचिव

दिनांक : 14 अक्टूबर, 2025
स्थान : नई दिल्ली

टाटा संस बाजार में आई तो सूचीबद्ध फर्मों को फायदा

कृष्ण कांत
मुंबई, 14 अक्टूबर

यदि टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाती है तो समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों, जिनकी संख्या सात है, को बड़ा फायदा हो सकता है। इससे टाटा संस में उनके निवेश का मूल्य बढ़ जाएगा, जो वर्षों पहले टाटा संस के वर्तमान संभावित मूल्यांकन की तुलना में कम मूल्यांकन पर किया गया था।

समूह की सात सूचीबद्ध कंपनियों की टाटा संस में कुल मिलाकर लगभग 12.1 प्रतिशत हिस्सेदारी है। टाटा संस में सूचीबद्ध कंपनियों की हिस्सेदारी उनका ऐसा बड़ा बिना वसूला लाभ है, जिसे टाटा संस के सूचीबद्ध होने पर 'उचित' बाजार मूल्यांकन मिलेगा।

टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर जैसी सूचीबद्ध समूह कंपनियां टाटा संस में शेयरधारकों का तीसरा सबसे बड़ा समूह हैं। ये टाटा ट्रस्ट्स और शापूरजी पलोनजी समूह के बाद आती हैं। इसके अलावा ट्रेंट के पास इस साल मार्च के अंत में टाटा संस में लगभग 1,000 प्रति शेयर के सममूल्य वाले संचयी तरजीही शेयर हैं, जिनकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये है।

सात टाटा ट्रस्टों को संयुक्त रूप से प्रवर्तक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके पास टाटा संस की 65.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट क्रमशः 27.98 प्रतिशत और 23.56 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ टाटा संस के दो सबसे बड़े शेयरधारक हैं।

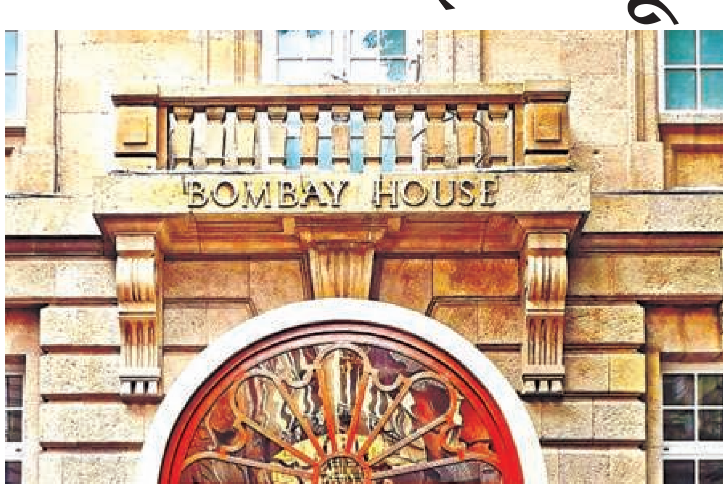

टाटा संस में बढ़ जाएगा निवेश का मूल्य

- टाटा संस में सात सूचीबद्ध टाटा कंपनियों की कुल मिलाकर 12.1 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसकी संयुक्त बुक वैल्यू 30,700 करोड़ रुपये है और बाजार मूल्य इससे कई गुना ज्यादा
- सात टाटा ट्रस्टों को संयुक्त रूप से प्रवर्तक के रूप में वर्गीकृत किया गया है
- समूह की सात सूचीबद्ध कंपनियों की टाटा संस में कुल मिलाकर 12.1 प्रतिशत हिस्सेदारी है

दूसरी ओर, शापूरजी पलोनजी समूह अपनी दो निवेश फर्मों - स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी का मालिक है। हरेक के पास 9.2 प्रतिशत हिस्सेदारी है। अन्य शेयरधारकों, जिनमें व्यक्ति भी शामिल हैं, के पास टाटा संस में कुल मिलाकर 4.2 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स में सत्ता संघर्ष चल रहा है और शापूरजी पलोनजी परिवार के नेतृत्व में शेयरधारकों का एक वर्ग टाटा संस को सूचीबद्ध कराने के लिए दबाव बना रहा है। दिलचस्प बात यह है कि टाटा संस उन कुछ बड़ी होल्डिंग कंपनियों में से एक है जो शेयर बाजारों में सूचीबद्ध नहीं हैं।

अन्य बड़े व्यावसायिक समूहों जैसे बजाज होल्डिंग्स, पिलानी इन्वेस्टमेंट्स, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, टीवीएस होल्डिंग्स, कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और बंगाल ऐंड असम कंपनी की होल्डिंग कंपनियां सूचीबद्ध हैं।

टाटा संस के प्रत्येक साधारण शेयर का अंकित मूल्य अभी 1,000 रुपये है और संयुक्त आधार पर इसकी बुक वैल्यू लगभग 62.8 लाख रुपये बैठती है। इसका मतलब है इस वर्ष मार्च के अंत तक संयुक्त आधार पर खाता-बही में इनकी कीमत लगभग 2.54 ट्रिलियन रुपये है।

इस वर्ष मार्च के अंत में टाटा समूह की सूचीबद्ध कंपनियों की टाटा संस में संयुक्त हिस्सेदारी की संयुक्त बुक वैल्यू 30,705 करोड़ रुपये थी। बाजार मूल्य और भी अधिक होने की संभावना है क्योंकि बड़ी होल्डिंग कंपनियां अपनी बुक वैल्यू के मल्टीपल पर कारोबार करती हैं। इसकी तुलना में देखें तो इन कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट टाटा संस में उनकी हिस्सेदारी की निवेश लागत केवल ~449.13 करोड़ रुपये बताती है।

अन्य कंपनियों में टाटा स्टील और टाटा मोटर्स 3.06 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दो सबसे बड़ी शेयरधारक हैं। इसके बाद टाटा केमिकल्स (2.53 प्रतिशत), टाटा पावर (1.65 प्रतिशत), इंडियन होटल्स (1.11 प्रतिशत), टाटा कंज्यूमर (0.43 प्रतिशत) और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (0.25 प्रतिशत) का स्थान आता है।

संपत्ति के मामले में टाटा संस के बाद देश की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी बजाज होल्डिंग्स है जो अपनी नवीनतम बुक वैल्यू के 2.1 गुना पर कारोबार कर रही है। बजाज होल्डिंग्स, बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व सहित राहुल बजाज समूह की अधिकांश कंपनियों में प्रमुख शेयरधारक है।

हालांकि सवाल यह है कि क्या ये सूचीबद्ध समूह कंपनियां टाटा संस में अपने निवेश को बेचेंगी या उस पर मुनाफा बुक करेंगी।

शेयर विभाजन के बाद टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प. 4 फीसदी चढ़ा

बीएस संवाददाता
मुंबई, 14 अक्टूबर

टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (टीआईसी) के शेयर में मंगलवार को 9 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई क्योंकि आज इसका एक शेयर 10 शेयरों में बंट गया। संशोधित व्यवस्था के तहत शेयरधारकों को 10 रुपये अंकित मूल्य वाले हर शेयर के बदले 1 रुपये के 10 शेयर मिले। अपने इंट्राडे में लाभ का कुछ हिस्सा गंवाने के बाद शेयर पिछले सत्र के मुकाबले 4.33 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,035 रुपये पर बंद हुआ। कारोबारियों ने कहा कि शेयर विभाजन से तरलता बढ़ने और अधिक खुदरा भागीदारी बढ़ने की संभावना है। पिछले महीने टीआईसी के शेयरों ने विभाजन से पहले 11,840 रुपये का सर्वाधिक ऊंचा स्तर छुआ था। टाटा समूह की निवेश होल्डिंग कंपनी ने 2025 में अब तक 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हासिल की है और इस समय उसका बाजार पूंजीकरण 52,351 करोड़ रुपये है।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search https://t.me/Magazines_8890050582 (@Magazines_8890050582)

संक्षेप में

कंपनियों ने बॉन्ड से 17,500 करोड़ जुटाए

भारत के कंपनी जगत ने मंगलवार को घरेलू ऋण पूंजी बाजार से बॉन्ड के जरिए 17,500 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए। इसमें भारती टेलीकॉम ने दो किश्तों में बॉन्ड के माध्यम से 10,500 करोड़ रुपये जुटाए। इससे यह इस वित्त वर्ष में घरेलू बाजार में किसी भारतीय कंपनी द्वारा सबसे बड़ा बॉन्ड निर्गमन बन गया। अन्य प्रमुख जारीकर्ताओं में बजाज फाइनैंस, आदित्य बिड़ला कैपिटल, पूनावाला फाइनैंस आदि थे। भारती एयरटेल की होल्डिंग कंपनी भारती टेलीकॉम ने दिसंबर 2028 में परिपक्व होने वाले बॉन्ड के माध्यम से 7.45 प्रतिशत पर 5,250 करोड़ रुपये जुटाए। इसके अतिरिक्त भारती टेलीकॉम ने 7.35 प्रतिशत पर 5,250 करोड़ रुपये जुटाए, जो अक्टूबर 2027 में परिपक्व होने वाले बॉन्ड के माध्यम से जुटाए गए। *बीएस*

ईपीएफओ की कर्मचारी नामांकन योजना शुरू

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सोमवार को 'कर्मचारी नामांकन योजना, 2025' शुरू करने की घोषणा की। यह योजना नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करती है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिनियम के तहत पहले से पंजीकृत और बिना पंजीकृत दोनों श्रमिकों की स्वेच्छा से पात्र कर्मचारियों की घोषणा और नामांकन करें। नियोक्ता किसी भी कारण से ईपीएफओ में पहले से पंजीकृत नहीं हुए श्रमिकों का नामांकन कर सकते हैं। इस क्रम में 1 जुलाई, 2017 और 31 अक्टूबर, 2025 के बीच प्रतिष्ठान में शामिल हुए श्रमिक और इस घोषणा की तारीख तक जीवित व कार्यरत श्रमिक का नामांकन किया जा सकता है। यह योजना 1 नवंबर, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक चलेगी। यह योजना वर्ष 2017 की पूर्व योजना को आगे बढ़ाना है। इस क्रम में 2019 से 2016 के बीच पंजीकृत नहीं किए गए श्रमिक जोड़े जा सकते हैं। *बीएस*

डिजिटल ऋण की वृद्धि दर हुई सुस्त

वित्त वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 26) की पहली तिमाही में मंजूर डिजिटल ऋण जारी करने की वृद्धि दर सुस्त होकर करीब तीन करोड़ रही जबकि इसका सकल मूल्य 43,019 करोड़ रुपये था। लिहाजा वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में संख्या में 13 प्रतिशत और मूल्य में 17 प्रतिशत सुस्त वृद्धि हुई। हालांकि यह वृद्धि वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही और वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में मजबूत थी और यह संख्या के मामले में क्रमशः 34 प्रतिशत और 23 प्रतिशत बढ़ी थी जबकि मूल्य के मामले में 33 से 34 प्रतिशत बढ़ी थी। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर इंपावरमेंट (फेस) के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में मंजूर डिजिटल ऋणों की संख्या 2.7 करोड़ थी और इनका मूल्य 36,888 करोड़ रुपये था। हालांकि वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में ऋण की संख्या 2.2 करोड़ और इनका मूल्य 27,577 करोड़ रुपये था। डिजिटल ऋण का मूल्य वित्त वर्ष 23 के 12 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 20 प्रतिशत हो गया। *बीएस*

16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा

सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है। सरकार ने 31 दिसंबर, 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था और नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया का इसका चेयरमैन बनाया गया था। इस आयोग को 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। आयोग मुख्य तौर पर एक अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण पर सिफारिशें करता है। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट दाखिल करने करने की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई जा रही है। आयोग में चार सदस्य हैं। सचिव ऋत्विक पांडे, दो संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार इसकी सहायता करते हैं। सेवानिवृत्त नौकरशाह एनी जॉर्ज मैथ्यू व अर्थशास्त्री मनोज पांडा आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं, जबकि एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष व आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी. रवि शंकर अंशकालिक सदस्य हैं। *भाषा*

आईएमएफ ने बढ़ाया वृद्धि अनुमान

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर

वृद्धि से मिला बल

- वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान पहले के 6.4 प्रतिशत से 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत किया
- आईएमएफ ने कहा कि पहली तिमाही की मजबूत वृद्धि ने अमेरिकी शुल्क के असर को कम करने के साथ अर्थव्यवस्था को और मबजूत किया
- 2025 के लिए वैश्विक वृद्धि का अनुमान भी 20 आधार अंक बढ़ाकर 3.2 प्रतिशत कर दिया गया है

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का पूर्वानुमान 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा कि भारत की पहली तिमाही की मजबूत वृद्धि ने अमेरिका के बढ़े शुल्क के नुकसान की भरपाई कर दी है।

आईएमएफ ने डब्ल्यूईओ के अद्यतन के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वृद्धि का अनुमान 20 आधार अंक से संशोधित कर 6.2 प्रतिशत कर दिया है।

विश्व बैंक ने पिछले सप्ताह वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया था, जबकि उसने जून में 6.3 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। वहीं भारत की ओर से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर अपेक्षा से अधिक शुल्क लगाए जाने के कारण वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 20 आधार अंक घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया था। विश्व बैंक ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रह सकता है, जिसे खपत में वृद्धि से लगातार मजबूती मिल रही है।

आईएमएफ के आर्थिक परामर्शदाता और अनुसंधान विभाग के निदेशक पियरे-ओलिवियर गौरींचस ने कहा कि देशों को राजकोषीय बफर बनाकर, मजबूत संस्थागत वातावरण बनाकर और वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने रहकर आर्थिक रूप से लचीला बनने की आवश्यकता है।

एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गौरींचस ने कहा कि वृद्धि निजी क्षेत्र तथा अन्यत्र विकसित प्रौद्योगिकियों को अपनाने से होती है।उन्होंने कहा, 'देशों को श्रम बल बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए सही प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि देश तेजी से बढ़ सकें और निजी क्षेत्र, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके।'

गौरींचस की यह टिप्पणी आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा के हालिया बयान के संदर्भ में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनिश्चितता अब नई सामान्य स्थिति है और देशों को इसके लिए कम कस लेने की जरूरत है।

आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर दर 6.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। आईएमएफ ने जुलाई में भारत का वृद्धि अनुमान 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया था। उसने खपत में तेज वृद्धि और सार्वजनिक निवेश पर जोर दिए जाने संबंधी नीतिगत सुधारों को देखते हुए अनुमान बढ़ाया था। इसने सौम्य वैश्विक वातावरण और महंगाई में कमी आने को भी अनुमान बढ़ाने की वजह बताई थी।

2025 के लिए वैश्विक वृद्धि का अनुमान भी 20 आधार अंक बढ़ाकर 3.2 प्रतिशत कर दिया गया है। 2026 के लिए आईएमएफ की रिपोर्ट में वृद्धि अनुमान में कोई बदलाव न करते हुए इसे 3.1 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।

आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है, 'वैश्विक अर्थव्यवस्था ने व्यापार नीति के झटकों के प्रति लचीलापन दिखाया है। ये झटके शुरुआत में अपेक्षा से कम नजर आए, लेकिन नीतियों में बदलाव से हालिया आंकड़ों में इसका असर दिख रहा है।'

भारत इस समय 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क का सामना कर रहा है, जिससे टेक्सटाइल, फुटवीयर और समुद्री उत्पाद जैसे श्रम केंद्रित क्षेत्रों पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है।

चूना पत्थर प्रमुख खनिज में शामिल

साकेत कुमार
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर

खनन मंत्रालय ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिज में शामिल किया है। मंत्रालय ने कहा कि नीति आयोग द्वारा पिछले साल गठित एक अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के बाद इसे एक प्रमुख खनिज के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण 10 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा।

इस समय चूना पत्थर लघु खनिज रियायत नियमों के तहत लघु खनिज के रूप में सूचीबद्ध है। यह लघु खनिज को निकालने के लिए राज्य स्तर के नियम के अधीन था। प्रमुख खनिज के रूप में अधिसूचित होने के बाद चूना पत्थर अब खान और खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय निरीक्षण में आ गया है। अंतर मंत्रालयी समिति ने प्रकाश डाला था कि चूना पत्थर देश के कई हिस्सों में व्यापक रूप से उपलब्ध है और इसका प्रमुख उपयोग सीमेंट, रसायन, उर्वरक, स्मेल्टर और चीनी निर्माण जैसे बड़े पैमाने के उद्योगों होने लगा है।

नवंबर 2024 में प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि चूना पत्थर को एक प्रमुख खनिज के रूप में माना जा सकता है और चूना पत्थर के सभी लघु खनिज पट्टों को प्रमुख खनिज पट्टों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रमुख खनिजों में कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि शामिल हैं। इन्हें राष्ट्रीय महत्त्व वाले खनिज की श्रेणी में रखा गया है और केंद्र के नियमों के अधीन आते हैं। वहीं लघु खनिजों में संगमरमर, स्लेट, शैल आदि शामिल हैं, जिनका स्थानीय उपयोग होता है और वे संबंधित राज्य कानूनों के तहत आते हैं। नए दिशानिर्देशों के तहत लघु खनिज पट्टों के रूप में दिए गए सभी मौजूदा चूना पत्थर खनन पट्टों को 31 मार्च, 2026 तक भारतीय खान ब्यूरो के साथ पंजीकरण करना होगा। तब तक वे मौजूदा दरों पर अपने संबंधित राज्य सरकारों को रॉयल्टी का भुगतान करना जारी रखेंगे। राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित खनन योजना 31 मार्च, 2027 तक या उनकी समाप्ति तक, जो भी पहले हो, मान्य रहेंगी। इस तिथि के बाद खनन जारी रखने के लिए, पट्टेदारों को अनुमोदन के लिए भारतीय खान ब्यूरो के पास नई खनन योजनाएं प्रस्तुत करनी होंगी।

चुंबक के लिए शुल्क छूट नहीं

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर

वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग ने भारी उद्योग मंत्रालय से कहा है कि प्रस्तावित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत रेयर अर्थ स्थायी चुंबक (आरईपीएम) के निर्माण में उपयोग की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों के आयात के लिए सीमा शुल्क या उपकर से छूट दिए जाने की जरूरत नहीं है।

अधिकारियों ने कहा कि योजना के तहत मिलने वाली पूंजीगत सब्सिडी ही उच्च लागत से आने वाली समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त होगी। अधिकारियों के मुताबिक भारत में स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों और मशीनरी पर खर्च काफी अधिक होने की उम्मीद है क्योंकि लगभग सभी उपकरणों को चीन के अलावा अन्य देशों, जैसे जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया से मंगवाना होगा। पीएलआई योजना के तहत बोली हासिल करने वालों (निजी कारोबारियों) को पीएलआई योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है, जो 6,000 टन सालाना संयुक्त उत्पादन क्षमता वाले 5 संयंत्र स्थापित करेंगे।

भारी उद्योग मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है, जो विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा कर रहा है। अधिकारियों ने उल्लेख किया कि मसौदा पीएलआई योजना में शुरुआत में बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) और पूंजीगत वस्तुओं पर उपकर (संयंत्र और मशीनरी) से छूट का प्रावधान था, जो आरईपीएम विनिर्माण संयंत्र के लिए जरूरत होती है।

बहरहाल राजस्व विभाग ने भारी उद्योग मंत्रालय को बताया कि ऐसी छूट किसी भी योजना या नीति दस्तावेज का हिस्सा नहीं होनी चाहिए और अगर जरूरी हो तो अलग अलग मामलों हिसाब से इस पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद एमएचआई ने मसौदा योजना से शुल्क छूट का प्रावधान हटा दिया।

इस मसले पर वित्त मंत्रालय या भारी उद्योग मंत्रालय ने बिज़नेस स्टैंडर्ड की ओर से मांगी गई जानकारी पर कोई जवाब नहीं दिया।

अधिकारियों ने कहा कि योजना के तकनीकी पहलुओं को देख रहे परमाणु ऊर्जा विभाग ने अनुमान लगाया था कि भारत में प्रति वर्ष 1,200 टन आरईपीएम का उत्पादन करने वाले संयंत्र स्थापित करने के लिए खर्च चीन की तुलना में 4 गुना ज्यादा हो सकता है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने संकेत दिया है कि ऐसी सुविधा के लिए भारत में लगभग 1,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए सीमा शुल्क से छूट के बजाय पूंजीगत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है।

खाद्य तेल आयात के शुल्क में हो स्थिरता

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर

भारत के पास खाद्य तेल आयात के शुल्क पर दीर्घावधि 3 से 5 नीतिगत योजना होनी चाहिए। भारत के पास घरेलू प्रसंस्करण उद्योग की सुरक्षा के लिए कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेल पर न्यूनतम कम से कम 7.5 से 10 अंतर हो।

हालिया शोध पत्र, 'भारत में खाद्य तेल क्षेत्र के शुल्क में उतार-चढ़ाव और साझेदारों के परिदृश्य' में कहा गया कि खाद्य तेल के आयात शुल्क में अचानक से आयात शुल्क में बदलाव होने से थोक व खुदरा मूल्य प्रभावित होते हैं। इससे मूल्य श्रृंखला में हरेक प्रभावित होता है। यह शोध पत्र संयुक्त रूप से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के सेंटर फॉर इकनॉमिक स्टडीज ऐंड प्लानिंग (सीईएसपी, वेईके पॉलिसी एडवाइजरी ऐंड रिसर्च और एसोचैम ने प्रकाशित किया।

इस शोध पत्र के अनुसार वर्ष 2011 से 2021 के दौरान भारत में कच्चे पाम ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के तेल पर शुल्क में 25 से अधिक बार बदलाव किया गया। यह शुल्क संरक्षणवाद के दौर में करीब शून्य से लेकर 50 से 70 प्रतिशत से अधिक रहा था। शोधपत्र में कहा गया, 'पिछले एक दशक में खाद्य तेलों पर आयात शुल्क ने असाधारण अस्थिरता दिखाई है।'

शोधपत्र में पाम तेल पर आयात शुल्क को संदर्भ बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसका कारण यह है कि पाम ऑयल भारत के वार्षिक खाद्य तेल आयात का लगभग 60 प्रतिशत है।

सितंबर में थोक महंगाई में कमी आई

हिमांशी भारद्वाज
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर

भारत का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)पर आधारित महंगाई सितंबर में गिरकर 0.13 प्रतिशत हो गई। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़े के अनुसार थोक महंगाई अगस्त में चार महीने के उच्च स्तर 0.52 प्रतिशत पर थी। भारत में थोक मूल्य महंगाई को थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मापा जाता है।

थोक महंगाई में सुस्ती प्रमुख तौर पर प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट (-3.32 प्रतिशत) और ईंधन व बिजली खंड में जारी अपस्फीति के रुझान के कारण हुई। थोक महंगाई में उस समय सुस्ती आई है जब एक दिन पहले भारत की खुदरा महंगाई सितंबर में 99 महीने के निचले स्तर 1.54 प्रतिशत पर आ गई थी। खुदरा महंगाई में गिरावट अनुकूल आधार प्रभाव और खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण आई थी। सितंबर में प्राथमिक खाद्य पदार्थों में अपस्फीति और बढ़कर -5.22 प्रतिशत हो गई। इसका कारण सब्जियों (-24.41 प्रतिशत), दालों (-17.19 प्रतिशत), आलू (-42.24 प्रतिशत) और प्याज (-63.79 प्रतिशत) की कीमतों में भारी गिरावट थी। हालांकि दूध और अंडे, मांस और मछली जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति सितंबर में पिछले महीने की तुलना में बढ़ गई।

यूरोपीय संघ के शुल्क से भारतीय स्टील को दोहरा नुकसान?

ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 14 अक्टूबर

यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा कोटा में कटौती करने और कोटा से ऊपर की मात्रा पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के प्रस्तावित कदम से 2026 में भारतीय इस्पात निर्माताओं के लिए दोहरा संकट पैदा हो सकता है।

इस महीने की शुरुआत में यूरोपीय आयोग ने अधिक वैश्विक क्षमता को देखते हुए यूरोपीय संघ के इस्पात उद्योग को बचाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। इस योजना के तहत शुल्क मुक्त आयात 183 लाख टन प्रति वर्ष तक कम किया जाएगा, 2024 के स्तर से 47 प्रतिशत कम है। साथ ही कोटा से बाहर आयात पर शुल्क को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

अगर यूरोपीय संसद और परिषद अंतिम विनियमन पर सहमत हो जाते हैं तो यह प्रस्ताव जून 2026 तक समाप्त होने वाले इस्पात सुरक्षा उपाय की जगह लेगा। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो जनवरी 2026 से लागू होने जा रहे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) के साथ मिलकर यूरोपीय संघ में भारत से पहुंचने वाला स्टील कीमत के हिसाब से कम प्रतिस्पर्धी रह जाएगा। भारत के स्टील निर्यात के लिए यूरोपीय संघ सबसे बड़ा बाजार है, जहां कुल निर्यात का लगभग 45 प्रतिशत भेजा जाता है। क्रिसिल इंटेलिजेंस के निदेशक सेहुल भट्ट ने कहा कि यूरोपीय संघ ने 2024 में 274 लाख टन तैयार स्टील का आयात किया, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत थी। इसमें फ्लैट स्टील उत्पादों का निर्यात 97 प्रतिशत था।

भारत के स्टील निर्यात के लिए यूरोपीय संघ सबसे बड़ा बाजार है

यूरोपीय संघ की नई शुल्क व्यवस्था में 183 लाख टन शुल्क मुक्त आयात होना है, जिसमें फ्लैट स्टील 128 लाख टन होगा। इस हिसाब से यह 2024 के आयात से 40 प्रतिशत कम होगा। भट्ट ने कहा कि इससे भारत के कोटे में भी इसी अनुपात में कमी आने की संभावना है, क्योंकि भारत से मुख्य रूप से फ्लैट स्टील का निर्यात होता है।

इक्रा के उपाध्यक्ष सुमित झुनझुनवाला ने कहा कि यूरोपीय संघ के प्रस्ताव से भारत के इस्पात निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, जो अपने कुल निर्यात का 32 से 45 प्रतिशत यूपोरीय संघ को भेजता है। उन्होंने कहा, 'जनवरी 2026 से प्रभावी प्रस्तावित प्रतिबंधों के साथ सीबीएएम भारतीय इस्पात निर्यातकों के लिए दोहरा नुकसान हो सकता है, जिससे निर्यात मात्रा में वृद्धि बाधित हो सकती है।'

अगर अप्रत्यक्ष असर के हिसाब से देखें तो इस कदम से व्यापार डायवर्जन का बढ़ने की संभावना है। झुनझुनवाला ने बताया कि वर्तमान में यूरोपीय संघ को भेजे जाने वाले लगभग 120 लाख टन एशियाई इस्पात निर्यात को भारत सहित वैकल्पिक बाजारों की ओर मोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन देशों की भारत के इस्पात आयात में पहले ही 70 से 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ऐसे में प्रतिस्पर्धा तेज होने से घरेलू स्टील की कीमतों पर असर पड़ सकता है।

अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने 12 प्रतिशत सुरक्षा शुल्क लगाया था, जो 7 नवंबर, 2025 तक लागू है।

बीएस सूडोकू 5411

	6			3			2	1
	5				4			
2	8							5
								4
				1		9		
6	9			4				
3	2			6			9	
			8			3		7
					9	4		

परिणाम संख्या 5410

9	5	4	6	7	1	2	8	3
2	7	1	8	4	3	5	6	9
3	8	6	5	9	2	1	7	4
5	6	2	9	3	8	4	1	7
4	3	8	1	5	7	9	2	6
7	1	9	4	2	6	8	3	5
8	9	7	3	1	5	6	4	2
6	2	5	7	8	4	3	9	1
1	4	3	2	6	9	7	5	8

कैसे खेलें? हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

मध्यम ★★★☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव | दिल्ली | उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में मंगलवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 2,850 रुपये बढ़कर 1,30,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई जबकि पिछली सत्र में यह 1,27,950 रुपये पर बंद हुई थी। चांदी भी 6,000 रुपये के उछाल के साथ 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। पिछले बाजार सत्र में यह 1,79,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2635/2640 गेहूं शरबती 4200/4300, चावल शरबती सेला 4100/4200, स्टीम 5000/5100, लालमती 5900/6200, चावल (सोना) 5300/5400, दाल अरहर सवा नं. 8800/9000, पटका 9500/10000, रिजैक्शन 8400/8600, चना दाल 7000/7100 चना देशी छना 6600/6700, चना चापा छना 6700/6800, एग्रो प्योर बेसन 2780, मटर देशी 4000 /4100, उड़द साबुत (काला) 8600/ 9900, दाल उड़द (काली) 9300/9500, उड़द धोया 9300/11000, मसूर छोटी 9000/10000, मलका 7800/8800, किरानाः जीरा 22000/24000, लालमिर्च गुंटूर 15000/23000, हल्दी निजाम फली (50 किलो) 7800/8300, धनिया एमपी 9300/13000, छोटी इलायची (किलो) 2100/2950, बड़ी इलायची 1480/1485, कालीमिर्च (किलो) 740/780, सुपारी (किलो) 485/540, सौंफ मोटी 13500/16500,

कानपुर
गेहूं 2640/2650 जौ 2300/2350, चावल मसूरी 3300/3400, चावल मोटा 3000 /3100, देशी चना 6050/6075, चना छना 6800/7000, दाल चना 7000/7100, देशी मटर 3700/3800, पिचकी 2900 /2950, मटर दाल 4200/4250, अरहर लेमन 6800/6825, दाल अरहर 9500 /9800, स्पेशल 8800/9000, उड़द एसक्यू 7900/7925, एफएक्यू 7000/7010 राजमा चित्रा 9400/11700, मूंग 6100 /7400, मसूर छोटी 9000/9500, छांटी 9800/10500, सरसों 6600/6640, तिल सफेद 11000/11200, सोया (टीन) 2100 /2160, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)2400/2550, सरसों खल 2600/2640, पामोलिन 2200/2300, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 2050 /2200, मधुसूदन देशी घी 10100, वासुदेव 9850, परम प्रीमियम 10100, पदम श्री 10100, लीलाधर 10000, अलसी 7900 /8000, धनियाः लोकल 8900/9000, राजस्थान 9200/9500, बढ़िया 10000 /12800, हल्दी 13800/16000,

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो) : नया लड्डू 1825 /1865, खुरपा 1680/1705, चाकू 1725 /1860, रसकट &, शक्कर 1910/1930, चौरसा &, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 4150, टिकोला 4100, देवबंद 4130, थाना भवन 4040, सिम्भावली 4170,

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो) : नया लड्ड्डू 1825 /1865, खुरपा 1680/1705, चाकू 1725 /1860, रसकट &, शक्कर 1910/1930, चौरसा &, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 4150, टिकोला 4100, देवबंद 4130, थाना भवन 4040, सिम्भावली 4170,

हापुड़
अनाज-दालः गेहूं 2700/2725, चावल परमल 3400/3450, डुप्लीकेट बासमती सेला 6100/6200, बासमती 1121 स्टीम 8500/8600, चना 5950/6000, चनादाल 7000/7300, काबली चना 8000/9500, राजमा देशी चित्रा 9500/11000, मटर 3700/3750, मटर दाल 3900/4000, अरहर लेमन 6750/6800, दाल अरहर 9200/10200, मसूर 9500/10000, उड़द देसी 6800/7000, दाल उड़द 9000/9500, धोया 10000/10500, मूंग यूपी 6400/6500, मूंग दाल 8500/10000,

जयपुर
दाल (जीएसटी अतिरिक्त): मूंग मोगर 8800/9000, मोटा 9200/9500, उड़द मोगर 9500/10000, मोटा 9500/10300, चौला मोगर 7900/8000, मोठ मोगर 8000/8500, मूंग दाल छिलका देशी 9000/9500, मलका 9500/ 10000, अरहर 9000/10000, मटर दाल 4000/4100, चना दाल मीडियम 7000/ 7100, बोल्ड 7200/7300, उड़द साबुत देशी 7000/7100, मटर सफेद 3750 /3800

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)170, राइसब्रान (अखाद्य) 168, खल सरसों 2600, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1300, लाल &, कंटीन्यूअस 1300, सरसों (टन) 19500, सूरजमुखी (टन) 16500, गेहूं 2640/2650, आटा (50 किलो)1510, मैदा 1610, चोकर (45 किग्रा) 1150, चोकर (30 किग्रा) 750, मक्की बिहार 2350/2400 **भाषा/एनएनएस**

डिस्क्लेमर.. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search https://t.me/Magazines_8890050582 (@Magazines_8890050582)

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 205

जारी है अनिश्चितता

अमेरिका की व्यापार नीति से संबंधित अनिश्चितता अभी भी वैश्विक आर्थिक बहस पर हावी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा जारी वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) के अक्टूबर संस्करण में कहा गया कि वैश्विक वृद्धि में कमी के जोखिम अप्रैल की तुलना में थोड़े कम हुए हैं लेकिन अभी भी वे ऊंचे स्तर पर हैं। अब ध्यान कीमतों, खपत और निवेश पर शुल्क दरों के प्रभाव की ओर स्थानांतरित हो रहा है। आईएमएफ ने चालू वर्ष के लिए अमेरिका के वृद्धि पूर्वानुमानों को जुलाई की तुलना में 10 आधार अंक बढ़ाकर 2 फीसदी कर दिया है। भारत के चालू वर्ष के वृद्धि संबंधी अनुमानों में भी संशोधन किया गया है और इन्हें 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.6 फीसदी कर दिया गया है। कई अन्य पूर्वानुमान लगाने वालों ने भी चालू वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमानों में संशोधन किया है। अनुमानों में यह सुधार पहली तिमाही में अपेक्षा से बेहतर वृद्धि संबंधी परिणामों के कारण हुआ है।

बहरहाल, अनिश्चितता को देखते हुए वृद्धि संबंधी अनुमानों में मामूली संशोधन शायद बहुत अधिक मायने न रखे। अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात पर 50 फीसदी का प्रतिबंधात्मक शुल्क लागू किया है। भारत के वार्ताकार इस सप्ताह अमेरिका जा रहे हैं और उम्मीद है कि दोनों देश जल्दी ही किसी साझा लाभ वाले व्यापार समझौते तक पहुंचेंगे। भारत पर अमेरिकी शुल्क जहां तुलनात्मक रूप से ऊंचा है वहीं भारत अनिश्चितता से जूझ रहा इकलौता देश नहीं है। जैसा कि डब्ल्यूईओ ने भी कहा उच्च अमेरिकी शुल्क दर बाहरी मांग को कम कर रही है जिससे बड़ी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर हो रहा है। व्यापार नीति की अनिश्चितता कंपनियों के बीच निवेश की मांग को भी प्रभावित कर रही है। प्रमाण दिखाते हैं कि आर्थिक नीति अनिश्चितता में एक मानक विचलन का इजाफा निवेश में दो फीसदी की गिरावट लाता है। इसका असर करीब दो साल बाद चरम पर पहुंचता है। कंपनियां अनिश्चितता के कारण निवेश को टालना चाहती हैं।

यह बात भी ध्यान देने लायक है कि शुल्क दरें इकलौती अनिश्चितता नहीं हैं। उदाहरण के लिए आव्रजन से संबंधित नीतिगत बदलाव भी विकसित और कम आय वाले देशों, दोनों जगहों पर वृद्धि को प्रभावित करेंगे। अनुमानों के मुताबिक कार्यबल में शामिल अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा उत्तरी अमेरिका में है, जिनमें से अधिकांश अमेरिका में हैं।

अमेरिका में आव्रजन नीतियों में बदलाव ने उत्पादन पर असर डाला होगा। इसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें प्रवासी कामगारों का दबदबा है। विनिर्माण, आतिथ्य और कृषि आदि उद्योग ऐसे ही क्षेत्र हैं जहां अपेक्षाकृत मुद्रास्फीति का अधिक दबाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका में कुल मुद्रास्फीति की दर में इजाफा होने की उम्मीद है जो फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति को सहज बनाने के नजरिये से एक जोखिम हो सकता है।

वर्ष 2027 से 2030 के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के सालाना औसतन 3.2 फीसदी की दर से विकसित होने की उम्मीद है। महामारी के पहले यानी 2000 से 2019 के बीच यह औसत दर 3.7 फीसदी थी। काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वैश्विक व्यापार से जुड़े मुद्दे किस प्रकार हल होते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है। अभी तक अधिकांश कारोबारी साझेदारों ने अमेरिका का विरोध नहीं करने का ही निर्णय लिया है। परंतु कुछ समझौतों में शामिल विचित्र शर्तों और अमेरिकी रुख में परिवर्तन को देखते हुए हालात बहुत जल्दी बदल भी सकते हैं।

विश्व व्यापार संगठन के अर्थशास्त्री हाल ही में 2025 के वस्तु व्यापार वृद्धि के अनुमानों को अगस्त के 0.9 फीसदी से बढ़ाकर 2.4 फीसदी कर चुके हैं। यह मोटे तौर पर उत्तरी अमेरिका में आयात की अग्रिम आपूर्ति के कारण संभव हुआ। हालांकि, 2026 के वृद्धि अनुमानों को पहले के 1.8 फीसदी से कम करके 0.5 फीसदी कर दिया गया है। वैश्विक सेवा निर्यात वृद्धि में भी धीमापन आने की उम्मीद है और यह 2024 के 6.8 फीसदी से कम होकर 2026 में 4.4 फीसदी रह सकती है। अमेरिका द्वारा उत्पन्न अनिश्चितता और व्यापारिक तनाव केवल वस्तुओं के व्यापार को ही नहीं, बल्कि सेवाओं और निवेश को भी प्रभावित करेंगे। भारत को अमेरिका के साथ संवाद बनाए रखने के साथ-साथ यूरोपीय संघ जैसे अन्य समझौतों को भी शीघ्रता से अंतिम रूप देने का प्रयास करना चाहिए।

बिनय सिन्हा

एआई के दौर में इंटरनेट प्रबंधन की वैश्विक चुनौती

एआई के दौर में इंटरनेट का संचालन करने के लिए सरकारों और उन निकायों के बीच सहमति की आवश्यकता होगी जो इसके सेवा प्रदाता हैं या इन सेवाओं के बड़े उपयोगकर्ता हैं। बता रहे हैं नितिन देसाई

बीते कुछ दशकों में जो सबसे अहम तकनीकी उन्नति नजर आई है वह नई सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित है। वर्ष 1990 में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की कुल संख्या करीब 30 लाख थी। इनमें भी अधिकांश लोग अमेरिका में थे। तब से अब तक इंटरनेट के इस्तेमाल में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है और आज दुनिया भर में करीब 5.5 अरब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें विकसित देशों की 93 फीसदी आबादी और विकासशील देशों की 63 फीसदी आबादी शामिल है। मोबाइल संचार और मोबाइल फोन के विकास ने भी इस तेजी में अहम भूमिका निभाई है। यह स्पष्ट रूप से हाल के वर्षों में दुनिया की अब तक की सबसे तेज और बड़ी तकनीकी प्रगति है।

20 वीं सदी के अंत में जब इंटरनेट का इस्तेमाल व्यापक हो चला था और वह बहुत हद तक वाणिज्यिक रुझान वाला हो गया था तब सरकारें मानक निर्धारण, आवंटन अधिकार के लिए संस्थानों के चयन, और इंटरनेट शासन से जुड़े अन्य पहलुओं में अधिक भूमिका चाहती थीं। इसी कारण वर्ष 2003 और 2005 में दो बार विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ) की स्थापना की मांग की गई। तब से बीते 20 साल से हर वर्ष आईजीएफ की बैठक हो रही है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा देखे जाने वाले अधिकांश विकास संबंधी मुद्दों में प्रभावी नियंत्रण का केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर होता है। यहां तक कि दूरसंचार जैसी अंतरराष्ट्रीय संपर्क वाली गतिविधियों में भी। परंतु इंटरनेट इससे अलग है। यह एक वैश्विक सुविधा है और इसके सभी तत्व वैश्विक प्रकृति के हैं, भले ही उनमें से कुछ किसी राष्ट्र की पहचान रखते हों। इसलिए केवल राष्ट्रीय नीतियों का समन्वय पर्याप्त नहीं है। इंटरनेट बुनियादी रूप से सीमाओं के पार साझेदारियों का नतीजा है। यही वजह है कि इसकी प्रबंधन प्रणाली को वैश्विक प्रबंधन के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय प्रभाव की भूमिका हो। बजाय कि केवल वैश्विक समन्वय की जरूरत वाले राष्ट्रीय प्रबंधन के रूप में।

आईजीएफ की स्थापना 2005 में की गई थी क्योंकि अमेरिका के अलावा अन्य सरकारों के पास इंटरनेट उपयोग और प्रसार संबंधी मानक तय करने के लिए जिम्मेदार संस्थाओं के साथ सार्थक संपर्क नहीं था। इंटरनेट के अधिकांश मानक और कार्य व्यवहार सरकारों द्वारा निर्धारित नहीं किए गए बल्कि इन्हें गैर सरकारी संस्थाओं मसलन इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स ऐंड नंबर्स (आईसीएएनएन) ने निर्धारित किया। आईजीएफ को एक बहुअंशधारक मंच के रूप में स्थापित किया जाना था ताकि निर्णय लेने के पहले विभिन्न अंशधारकों के बीच सहमति तैयार करने की कोशिश की जा सके। इसका उद्देश्य था बेहतर गुणवत्ता वाले नतीजे प्राप्त करना।

अब इंटरनेट संचालन के नीति-नियम निर्धारित करने में सरकारों की भूमिका स्थापित हो चुकी है। पहले इसमें अमेरिकी सरकार का दबदबा था लेकिन अब वह कमजोर पड़ चुका है। इतना ही नहीं अधिकांश सरकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर शासन प्रणाली विकसित की है। हालांकि अब इंटरनेट के संचालन की चुनौतियां बदल चुकी हैं।

आज का इंटरनेट उस समय से बिल्कुल अलग है जैसा कि वह 2005 में आइजीएफ की शुरुआती बैठक के समय था। उस समय इंटरनेट का व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू ही हुआ था। अब हालात बदल गए हैं। अब इंटरनेट के प्रभावी संचालन के लिए जो सबसे महत्त्वपूर्ण है, वह है ई-बैंकिंग और ई-कॉमर्स में इसका इस्तेमाल। अब यह बहुत व्यापक पैमाने पर होने लगा है: सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव में, जो उपयोगकर्ताओं को केवल जानकारी हासिल करने में नहीं बल्कि जानकारी और ऐसे विचार साझा करने में जिनका राजनीति प्रभाव भी पड़ता है। इसी तरह ई-गवर्नेंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है।

एक नया बदलाव जो देखने को मिल रहा है वह है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में तेज इजाफा। इसका रोजगार और उत्पादकता पर बहुत गहरा असर पड़ने की संभावना है। यह प्रभाव केवल जानकारी प्रदान करने तक सीमित नहीं है बल्कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जानकारी के इस्तेमाल तक फैला हुआ है। आज इंटरनेट बहुत हद तक व्यावसायिक हो चुका है और इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाले कारोबारियों से प्रभावित है। वास्तव में वैश्विक दबदबे वाली अधिकांश कंपनियां अमेरिकी हैं। इंटरनेट सेवा में दबदबा केवल सामग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि उपयोगकर्ताओं की संख्या से भी जुड़ा हुआ है। इसका परिणाम यह होता है कि कोई एक निगम विजेता बन जाता है और अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का लाभ उठाता है, जिससे कभी-कभी किसी इंटरनेट सेवा पर लगभग एकाधिकार जैसा हो जाता है। यह प्रभुत्व उपयोगकर्ताओं की जानकारी तक विशेष पहुंच और डेटा उपनिवेशवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आज इंटरनेट पर अमेरिका का प्रभुत्व उसकी सरकार की भूमिका से कम और उसकी इंटरनेट-संबंधित कंपनियों के वैश्विक प्रभाव से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है।

इस समय हम सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी उछाल के साक्षी बन रहे हैं। यह जनता की नजर में तब आया जब साल 2022 में चैटजीपीटी सामने आया। तब से अब तक एआई का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार हो चुका है। इसने सूचनाओं तक पहुंच को आसान बनाया है। यह इतना अधिक हो चुका है कि कई वेब आधारित सूचना प्रदाता अपनी घटती प्रासंगिकता को लेकर चिंतित हैं।

हालांकि जेनरेटिव एआई के उभार के आर्थिक परिणाम कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं। माना जा रहा है कि यह बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार को प्रतिस्थापित कर देगा। ऐसे रोजगारों को जो सेवाओं और उत्पादों को तैयार करने के लिए सूचनाओं का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद यह है कि 19वीं सदी में बिजली के विकास की तरह ही इससे उत्पादकता, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी और नए तरह के रोजगार तैयार होंगे।

फिलहाल एआई उपक्रम निवेश का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। खासतौर पर अमेरिका में ऐसा हो रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार में आई मौजूदा तेजी के 80 फीसदी हिस्से के लिए एआई कंपनियां जिम्मेदार हैं। परंतु जैसा कि अतीत के तकनीकी अविष्कारों के साथ हुआ, इसमें कुछ विजेता होंगे तो कुछ पीछे रह जाएंगे। इंटरनेट शासन के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू अब डेटा का भारी व्यवसायीकरण और एआई का संभावित प्रभाव होने वाला है। एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा यह है कि एआई सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट डेटा तक पहुंच प्राप्त होती है, जो सामान्यतः मुफ्त में उपलब्ध होता है, लेकिन उसी डेटा से एआई प्रदाता आर्थिक लाभ कमाते हैं। वास्तव में चीन के योजनाकार श्रम, पूंजी और जमीन की तरह डेटा को भी उत्पादन कारक मान रहे हैं। अधिकांश देश अभी भी डेटा के प्रबंधन और नियंत्रण से जूझ रहे हैं।

इंटरनेट बुनियादी रूप से वैश्विक है और राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन पर्याप्त नहीं है। इंटरनेट और एआई के डिजाइन ही नहीं, बल्कि उनके वैध उपयोग पर भी वैश्विक सहमति आवश्यक होगी। प्रभावी इंटरनेट शासन के लिए केवल सरकारों के बीच ही नहीं, बल्कि उन कंपनियों के बीच भी सहमति जरूरी होगी जो इंटरनेट और एआई में सेवा प्रदाता या प्रमुख उपयोगकर्ता हैं। एक प्रारंभिक कदम के रूप में, आईजीएफ से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह सरकारों द्वारा औपचारिक विचार के लिए एक योजना तैयार करे।

(लेखक उस कार्य समूह के अध्यक्ष रहे हैं जिसने आईजीएफ की स्थापना के बारे में सलाह दी थी)

भारत-कनाडा संबंधों में सुधार की नई शुरुआत

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विराम का अपना महत्त्व होता है। चाहे वह गलतफहमी हो, मनमुटाव हो, झड़प हो या युद्ध ही क्यों न हो, एक अस्थायी विराम देशों को पीछे हटने और अपनी स्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए आवश्यक गुंजाइश दे सकता है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद तीन दिन की यात्रा पर नई दिल्ली आईं, और यह भारत-कनाडा संबंधों के लिए बिल्कुल ऐसा ही क्षण है। ठीक एक साल पहले दोनों लोकतंत्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध काफी तनावपूर्ण लग रहे थे। कनाडा ने खालिस्तान समर्थक की हत्या के एक मामले में भारतीय राजनयिकों को अपराध की जानकारी होने का आरोप लगाया था और भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था।

कनाडा की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों ने इस बदलाव में योगदान दिया है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो सरकार के हटने से लेकर वर्तमान मार्क कार्नी सरकार के आने तक रवैये में एक स्वागतयोग्य बदलाव आया है। जून में कनाडा के कनानसकीस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्नी के बीच मुलाकात एक महत्त्वपूर्ण क्षण था। इसे दोनों सरकारों के शीर्ष स्तर पर एक प्रस्ताव के पहले अवसर के रूप में देखा गया था। अनीता आनंद की वर्तमान यात्रा एक अत्यंत आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई का प्रतीक है और विश्वास बहाली का अवसर प्रदान कर सकती है।

दोनों देशों के लिए बाहरी वातावरण, खासकर अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में कनाडा के लिए, डॉनल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद से काफी बदल गया है। जो अनिश्चितता उत्पन्न हुई है, उसने अधिकांश देशों को स्थिरता के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि, कनाडा के लिए यह परेशानी कहीं अधिक गहरी है। यह जी-7 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं किया है। कार्नी ने कनाडा की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का बड़ा वादा करने के साथ पदभार ग्रहण किया था, लेकिन ट्रंप के हमले ने अहस्तक्षेप-आधारित या मुक्त व्यापार और वाणिज्य को रोक दिया है। इस्पात, वाहन और अन्य क्षेत्रों पर अमेरिकी टैरिफ कनाडा की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के बारे में बार-बार आह्वान किया है।

हर्ष वी पंत और विवेक मिश्रा

कार्नी और ट्रंप के बीच हाल ही में दूसरी बैठक हुई जिसमें ट्रंप ने स्पष्ट रूप से अमेरिका-कनाडा संबंधों को 'स्वाभाविक संघर्ष' और 'पारस्परिक प्रेम' के बीच रखा और यह संकेत दिया कि द्विपक्षीय संबंधों में उथल-पुथल जारी रहने की संभावना है। ऐसे में, व्यापार और सुरक्षा विविधीकरण के लिए कनाडा की आवश्यकता को कम करके नहीं आंका जा सकता। कनाडाई मंत्री आनंद भारत यात्रा के बाद सिंगापुर और चीन की यात्रा करेंगी, जो कनाडा के द्विपक्षीय और वैश्विक व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। भारत उनका पहला पड़ाव है, जो कनाडा में संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की भावना को दर्शाता है।

कनाडा के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत और कनाडा 'व्यापार विविधीकरण, ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रणनीतिक सहयोग के लिए एक ढांचा स्थापित करने' की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आनंद की तीन दिवसीय यात्रा के एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मुंबई की यात्रा और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ उनकी बैठक आर्थिक अनिवार्यता को रेखांकित करती है। भारत और कनाडा का द्विपक्षीय व्यापार 2024 में लगभग 10 अरब डॉलर का था और प्रवासी संबंधों, सांस्कृतिक संबंधों तथा बढ़ते निवेश को देखते हुए इसमें वृद्धि की संभावना है।

राजनीतिक स्तर पर देखें तो आनंद की विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक विश्वास निर्माण की एक कवायद है। यह कार्य कनाडा में दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के बाद से ही जारी है, जिसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैठक हुई, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी समकक्ष नथाली जी ड्रौइन से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों देशों द्वारा नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति एक नई शुरुआत का प्रतीक है। हालांकि इन कदमों को निरंतर और उचित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी, लेकिन इस संबंध में गति महत्त्वपूर्ण होगी। विश्व व्यवस्था में वर्तमान उतार-चढ़ाव के बीच जब देश अवसरों की तलाश कर रहे हैं, भारत और कनाडा दोनों ही अगली व्यवस्था के पूर्वानुमान के चरण में हैं।

यह दोनों देशों के लिए एक अवसर है कि वे एक-दूसरे पर भरोसा बढ़ाकर दुनिया के सामने मौजूद संकट से लाभ उठाएं। कनाडा के लिए, खालिस्तान समर्थक भावनाओं को भड़काने वाले घरेलू तत्त्वों पर लगाम लगाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम सुरक्षा और संप्रभुता के संदर्भ में विश्वास बहाली का सकारात्मक संकेत देने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। कनाडा पुलिस द्वारा अमेरिका स्थित समूह सिख्स फॉर जस्टिस के एक प्रमुख आयोजक इंदरजीत सिंह गोसल सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी ऐसा ही एक कदम था। हाल के दिनों में, भारतीयों या भारतीय मूल के कनाडाई लोगों से जुड़े व्यवसायों पर लक्षित गोलीबारी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं में वृद्धि चिंता का एक विषय रही है जिस पर कनाडा को ध्यान देने की आवश्यकता है।

कनाडा के लिए भारत की तरह ही, व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा विविधीकरण एक विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। कनाडा जब भारत, सिंगापुर और चीन जैसे प्रमुख देशों की ओर देख रहा है, तो वह अपनी निष्क्रिय हिंद-प्रशांत रणनीति को पुनर्जीवित करने के लिए उत्सुक होगा। हिंद-प्रशांत में भारत की केंद्रीय भूमिका भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को आकार देती रहेगी, हालांकि पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं ने दोनों पक्षों को एक संकट प्रबंधन ढांचा बनाने की आवश्यकता के प्रति सचेत कर दिया होगा ताकि व्यापक संबंधों को इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े दो राष्ट्रों के बीच कभी-कभार उत्पन्न होने वाली उथल-पुथल से बचाया जा सके।

(लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली से जुड़े हैं)

आपका पक्ष

गाजा में शांति, रूस-यूक्रेन के बीच भी रुके युद्ध

इजरायल और हमास के बीच पिछले दो वर्षों से जारी संघर्ष का अंत हो गया है तथा दोनों ने कैदियों और बंधकों को रिहा कर शांति की ओर कदम भी बढ़ा दिए हैं। सोमवार को इजरायल ने करीब 1,900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की घोषणा की तथा हमास ने जीवित बचे सभी 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद दोनों देश शांति के लिए सहमत हुए तथा समझौता करने के लिए आगे आए। हालांकि तकरीबन दो वर्षों तक चले इस संघर्ष में गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो गई है और वहां सिर्फ ऊंचे-ऊंचे भवनों के खंडहर ही शेष रह गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा को उन्हें सौंप देने कहा था जिससे वह कथित रूप से वहां नए सिरे से विकास कर सुंदर शहर बना सकें। लेकिन जमीन की लड़ाई में फिलिस्तीन और इजरायल यह कभी नहीं चाहेंगे कि गाजा पट्टी अमेरिका के हाथ चले जाए। बहरहाल हमास-इजरायल संघर्ष के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को भी समाप्त करने के लिए विश्व के सभी देशों को दोनों देशों पर दबाव बनाना चाहिए। 21वीं सदी में अगर एक देश दूसरे से युद्ध करते हैं तो पूरे विश्व का नुकसान होता है। परमाणु युग में वैश्विक शांति जरूरी है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

इजरायल द्वारा कैदियों को रिहा किए जाने के बाद मंगलवार को गाजा पहुंचे फिलिस्तीनी

जान बचाने के लिए है दवा मौत के लिए नहीं

इस समाचार पत्र में प्रकाशित संपादकीय में विषाक्त कफ सिरप पाने से 14 बच्चों की मौत पर सटीक टिप्पणी की गई है। साथ ही कुछ सवाल भी उठाए गए हैं जिस पर सरकार और दवा निर्माता कंपनियों को आने वाले समय में गंभीरता से सोचना होगा। मासूम बच्चों की जान बचाई जा सके तथा निकट भविष्य में दोबारा इस तरह की घटना न घटे इसके लिए कठोर नीति बनाने की भी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से 14 बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल में कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 6 राज्यों की दवा बनाने वाली 19 इकाइयों की जांच आरंभ की गई है। सवाल यह उठता है कि जीवन रक्षक दवाओं और उसे बनाने वाली कंपनियों की पड़ताल ऐसी घटनाएं होने की बाद ही क्यों शुरू होती है। दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए असमान और कमजोर नियमन की जगह कठोर नियमन का प्रबंध सरकार क्यों नहीं करती है। ऐसी घटनाएं बार-बार घटती रहती हैं तथा दवाओं की गुणवत्ता में चूक बार-बार देखने को मिलती है। घटना के बाद दवा बनाने वाली 19 इकाइयों की जांच के आदेश दिए गए जबकि सभी दवा बनाने वाली इकाइयों की जांच होनी चाहिए। भारत से कई देशों में दवा का निर्यात किया जाता है। ऐसे में देश में घटिया दवा निर्माण होने इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगेंगे। इसस पहले भी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय कफ सिरप पीने से मौत का मामला सामने आया था। दवा किसी की जान बचाती है और अगर दवा से जान जाने लगे तो व्यक्ति किस चीज पर विश्वास करेगा।

शैलेंद्र कुमार पांडेय, पटना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

दक्षिण कोरिया में आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास से पहले बुसान नेवल हार्बर में भारतीय नौसेना तथा रिपब्लिक ऑफ कोरिया नौसेना के अधिकारी।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search https://t.me/Magazines_8890050582 (@Magazines_8890050582)